20 जुलाई, 2025 ☆ वर्ष 34, पृष्ठ संख्या 80, अंक 07

राजस्थान सुजस

पं. दीनदयाल उपाध्याय

अन्त्योदय संबल पखवाड़ा

(24 जून से 9 जुलाई, 2025)

अन्त्योदय

संकल्प–विकल्प–प्रकल्प

“पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे विचारक थे, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज के वंचित और उपेक्षित वर्ग के लिए समर्पित कर दिया। पं. उपाध्याय का सपना था कि भारत का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। इस पखवाड़े के माध्यम से हमने उसी संकल्प को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है।”

मुख्यमंत्री

शब्द भावना

> हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा एवं महिला इन चारों जातियों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है तथा हम संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा करेंगे, जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को गति मिलेगी।

प्रिय प्रदेशवासियों,

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए और अंतिम व्यक्ति के घर तक विकास का उजियारा पहुंचाने के लिए हमने 24 जून से 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल पखवाड़े' का शुभारम्भ किया, जो 9 जुलाई 2025 तक चला। साथ ही हमारी सरकार द्वारा चलाए गए 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' की सफलता के लिए भी मैं आप सभी को बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' के दौरान आप जन के सहयोग से हमने प्रदेश की लगभग दस हजार पांच सौ ग्राम पंचायतों में करीब डेढ़ लाख कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें करीब एक करोड़ दस लाख नागरिकों की भागीदारी रही। अभियान के अंतर्गत 20 हजार से अधिक जलस्रोतों की सफाई के कार्य किए गए। जल संरक्षण के इस पावन अभियान की सफलता के बाद हमने जन सेवा के लिए 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल पखवाड़े' की शुरुआत की।

अंत्योदय का सिद्धांत कहता है कि जब तक गरीब, किसान और मजदूर सशक्त नहीं होगा, तब तक गाँव का विकास नहीं होगा। यह अंत्योदय सम्बल पखवाड़ा उनके दर्शन को साकार करने का एक प्रयास था, जिसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों के वर्षों से अटके कार्यों को पूरा करने की योजना करना, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाना है। हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा एवं महिला इन चारों जातियों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है तथा हम संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा करेंगे, जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को गति मिलेगी।

इन शिविरों में रास्तों से अतिक्रमण हटाने, भूमि के स्वामित्व मिलने जैसे बरसों से लंबित काम पूरे हुए। साथ ही, शिविरों के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10 हजार गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। उनके द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण की योजनाओं से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का उत्थान हो रहा है। साथ ही, उनके कुशल मार्गदर्शन में देश में अभूतपूर्व विकास कार्य के साथ-साथ आतंकवाद-नक्सलवाद का खात्मा हुआ है।

आईये हम सभी मिलकर संकल्प लें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनाएं। हमारा लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय है, जिससे कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय हिन्द, जय भारत, जय राजस्थान।

राम राम साब।

प्रधान संपादक
संदेश नायक

संपादक
डॉ. रजनीश शर्मा

सहायक संपादक
डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
रेनबो ऑफसेट प्रिंटर्स
लागत मूल्य 40.00 रुपये

संपर्क
संपादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. 80058 98512
e-mail
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 34 अंक 07

इस अंक में

जुलाई, 2025

अन्त्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय **05**

शान से निकली तीज की सवारी **30**

सहकार एवं रोजगार उत्सव **40**

शब्द भावना	02
संपादकीय	04
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा	10
आत्मनिर्भर गांव, समृद्ध राजस्थान	22
पौधे घर के सदस्य ...	24
आंतकियों का काल – ऑपरेशन महादेव	26
Give up अभियान	29
चिदानंदरूप: शिवोऽहम् शिवोऽहम्	32
श्रावण मास – चहुं ओर उल्लास	36
गुरु तत्व की सक्रियता ...	38
वैदिक अध्ययन	44
वागड़ गंगा माही	50
आधे सावन में छलके बांध	54
अक्षय ऊर्जा – प्रदेश फिर सिरमौर	56
किसान संग सरकार	58
Financial Inclusion Campaign	62
मंत्रिमंडल बैठक – महत्वपूर्ण निर्णय	66
अब 'हील इन राजस्थान'	68
शतरंज – 64 खानों में बिछी बिसात	70
सामयिकी	73
सुजस प्रश्नोत्तरी	78
पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब	80

शेखावाटी की जग प्रसिद्ध हवेलियां **46**

जनता के राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. कलाम **64**

धरोहर **79**

संपादकीय

हर संकल्प सिद्धि की ओर ...

राजस्थान, जो सदियों से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और लोकचेतना के लिए पहचाना जाता रहा है, आज विकास, संवेदना और सेवा के नए मानक स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के विकास की धारा को स्पष्ट करते हुए मजदूर- किसान- महिला और युवा, इन चार वर्गों को ही भारत की चार मुख्य जातियां मानते हुए इन्हें ही भारत की आत्मा बताया है। राजस्थान सरकार ने इन चारों को नीति-निर्माण के केन्द्र में रखते हुए जो योजनाएं बनाई हैं, उनसे प्रदेश आज "सशक्त शासन, समर्पित सेवा और संवेदनशील प्रशासन" का जीवंत उदाहरण बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा भी है, 'गरीब हमारे लिए गणेश के समान हैं और उनकी सेवा हमारा धर्म है।' यह भाव 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा' के दौरान और मुखर स्वरूप में सामने आया। 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक आयोजित यह अभियान केवल प्रशासनिक पहल नहीं रहा, बल्कि "शासन को जन-मन तक पहुंचाने का जीवंत माध्यम" बन गया। मुख्यमंत्री ने स्वयं अनेक जिलों में शिविरों का निरीक्षण कर आमजन से सीधे संवाद किया और समस्याओं का समाधान धरातल पर सुनिश्चित किया।

किसी ने सच ही कहा है, यदि सेवा का भाव सच्चा हो, तो ईश्वरीय कृपा के साथ पूरी प्रकृति सहायक बन जाती है। पिछले माह 'वन्दे गंगा जल सरंक्षण जन अभियान' के बाद इस मानसून में इंद्र देवता भी राजस्थान पर मेहरबान हैं। 'हरयाळो राजस्थान वृक्षारोपण महाभियान' के अंतर्गत इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी छाया तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह अभियान सिद्ध कर रहा है कि विकास केवल इमारतों से नहीं, वृक्षों की अमृतमयी छाया से भी मापा जाएगा।

हाल ही में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय – नगरीय विकास, मेडिकल टूरिज्म, अक्षय ऊर्जा, कर्मचारी कल्याण और पदोन्नति जैसे विषयों पर सरकार की दूरदृष्टि और लोक–केंद्रित सोच को दर्शाते हैं। युवाओं के लिए 26 हजार से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा कर मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रोजगार अब केवल वादा या घोषणा नहीं रहा, बल्कि धरातल पर फलीभूत होते दिखाई दे रहा है।

यह अंक एक ऐसे नव–निर्माणशील राजस्थान की कहानी है, जो केवल प्रगति की बात नहीं करता, बल्कि उसे हर नागरिक को जीवन में अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है – जहां गरीब 'गणेश' हैं, अन्नदाता के रूप में किसान 'पूरे सम्मान के पात्र' हैं, मजदूर 'राष्ट्र निर्माण के स्तंभ' हैं, महिलाएं 'शक्ति' हैं, और युवा भविष्य के 'ध्वजवाहक'। जब शासन की नींव ही सेवा पर टिकी हो, नेतृत्व की दृष्टि संवेदना से ओतप्रोत हो और नीति का केंद्र जनकल्याण हो – तब 'संकल्प से सिद्धि' केवल नारा नहीं, बल्कि एक जीवंत यथार्थ बन जाता है। प्रदेश सरकार के महत्त्वपूर्ण निर्णयों और सफल अभियानों की प्रेरणादायी झलक समेटे हुए, 'सुजस' का जुलाई माह का यह अंक, आप सुधि पाठकों के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

(संदेश नायक)
प्रधान सम्पादक

अन्त्योदय के प्रणेता

पंडित दीनदयाल उपाध्याय
एक प्रखर राष्ट्रवादी

> पंडित दीनदयाल उपाध्याय समय से आगे की परिष्कृत एवं सुस्पष्ट सामाजिक- राजनीतिक-आर्थिक सोच वाले प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक थे। अन्त्योदय, अखण्ड एवं एकात्म राष्ट्रीयता प्रेरित एक-राष्ट्र सिद्धान्त, संघात्मकता, समाजवाद, विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था, स्वदेशी, भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद और ऐसे कई अन्य विषयों पर उनके विचार कालजयी होकर आज भी प्रासंगिक हैं। अन्त्योदय के सम्बन्ध में उनके प्रेरक विचार केन्द्र एवं राज्य सरकार के लिए लोककल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दिशा निर्देशक बने हुए हैं। प्रस्तुत आलेख ऐसे महान चिन्तक के विचारों और उन विचारों की तार्किक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में है।

डॉ. महेश चन्द्र शर्मा
अध्यक्ष, एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान

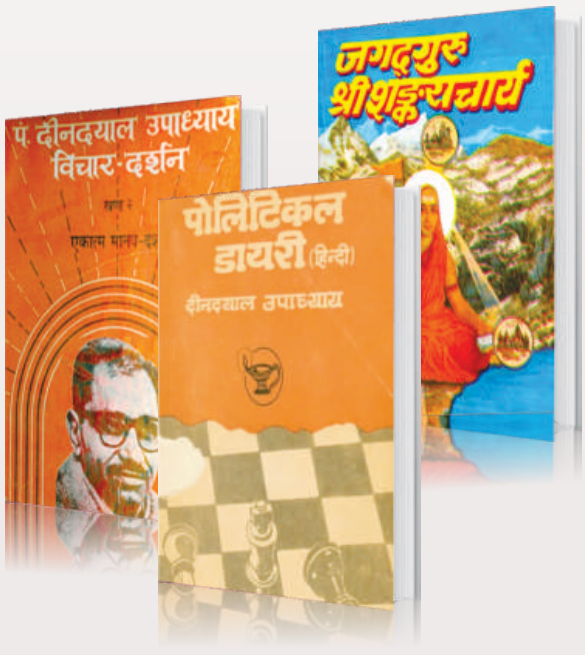

भारतीय ऋषि परम्परा की अधुनातन कड़ी हैं, पं. दीनदयाल उपाध्याय। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के आन्दोलन के अंतिम दशक (1937-1947) को द्वि-राष्ट्रवाद के आन्दोलन ने आक्रांत कर लिया था। भारत माता की भक्ति एवं वन्देमातरम् की भावना के साथ चलने वाले स्वराज्य प्राप्ति के आन्दोलन को 'राज-भोग' लालसा के बन्दर बांट आन्दोलन ने आवृत्त कर लिया था। मजहब के आधार पर भारत-विभाजन की दुरभिसंधि का दुष्काल था यह दशक।

यही वह दशक है, जब युवा एवं प्रतिभा सम्पन्न दीनदयाल सार्वजनिक जीवन में आते हैं। भारत की अखण्ड एवं एकात्म राष्ट्रीयता के अहसास के साथ वे इस विभाजनकारी दुश्चक्र के प्रतिकार की महत्वाकांक्षा लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन जाते हैं, अपने को पूर्णत: समर्पित कर प्रचारक बन जाते हैं। आजादी के नाम पर चलने वाले आन्दोलन में नीतिमत्ता, वीरव्रत एवं क्षात्र-धर्म का वे अभाव देखते हैं तथा आने वाली पीढ़ी के लिये वे एक उपन्यास लिखते हैं 'चन्द्रगुप्त मौर्य।' वे आश्चर्य चकित थे कि पाश्चात्य जीवन मूल्यों की आकांक्षा लेकर भारत की स्वतंत्रता के सपनों को पालने का प्रयत्न किया जा रहा है। उन्होंने दूसरा उपन्यास लिखा 'जगद्गुरु शंकराचार्य'। राष्ट्रीय अखण्डता एवं राष्ट्रीय एकात्मता के वे प्रखर प्रवक्ता बन गये। तब वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में उत्तर प्रदेश के सह-प्रांत प्रचारक थे। 'स्वदेश' दैनिक, 'पांचजन्य' साप्ताहिक तथा 'राष्ट्रधर्म' मासिक का प्रकाशन प्रारंभ किया।

पं. दीनदयाल उपाध्याय
अपने शिक्षकों के साथ

बी.ए. के दौरान

हस्ताक्षरित फोटो

जनसंघ के अध्यक्ष
चुने जाने पर

द्वि-राष्ट्रवाद अस्वीकार्य

हिंसाचारी मजहबी पृथकतावाद से भयाक्रांत एवं समझौतावादी तथाकथित राष्ट्रवाद पर वे निरन्तर प्रहार करते रहे। मुख्यधारा का आन्दोलन विपथगामी हो चुका था, अत: उस दुर्भाग्य को टाला नहीं जा सका, जिसने विश्व के प्राचीनतम एवं महान राष्ट्र के दो टुकड़े कर दिये, राष्ट्र की अखण्डता भंजित हुयी, द्वि-राष्ट्रवाद जीत गया। दीनदयाल उपाध्याय ने द्वि-राष्ट्रवाद की इस जीत को कभी स्वीकार नहीं किया। वे 'अखण्ड भारत' की मशाल लेकर आगे बढ़े। आजाद भारत में उनकी पहली पुस्तक आई 'अखण्ड भारत क्यों?' उन्होंने इस सपने को तथा विचार को कभी अविषय नहीं बनने दिया, अखण्ड भारत का आग्रह निरन्तर रखा।

'अखण्ड भारत देश की भौगोलिक एकता का ही परिचायक नहीं, अपितु जीवन के भारतीय दृष्टिकोण का द्योतक है, जो अनेकता में एकता का दर्शन करता है। अत: हमारे लिये अखण्ड भारत कोई राजनीतिक नारा नहीं है... बल्कि हमारे सम्पूर्ण जीवन दर्शन का मूलाधार है।' 1951 में ही दीनदयालजी राजनैतिक क्षेत्र में आये, वे भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने। जब तक वे जीवित थे, 1952 से 1967 तक सभी चुनावी घोषणा पत्रों में उन्होंने अखण्ड भारत को जनसंघ का लक्ष्य घोषित किया। वे कहते हैं 'वास्तव में अखण्ड भारत का मार्ग युद्ध नहीं है। युद्ध से भौगोलिक एकता हो सकती है, राष्ट्रीय एकता नहीं। अखण्डता भौगोलिक ही नहीं, राष्ट्रीय आदर्श भी है। देश का विभाजन दो-राष्ट्रों के सिद्धान्त तथा उसके साथ समझौता की प्रवृत्ति से हुआ। अखण्ड भारत, एक-राष्ट्र के सिद्धान्त पर मन-वचन एवं कर्म से डटे रहने पर सिद्ध होगा। जो मुसलमान आज राष्ट्रीय दृष्टि से पिछड़े हुये हैं, वे भी आपके सहयोगी बन सकेंगे, यदि हम राष्ट्रीयता के साथ समझौते की वृत्ति त्याग दें। आज की परिस्थिति में जो असम्भव लगता है वह कालान्तर में सम्भव हो सकता है, किन्तु आवश्यकता है कि आदर्श हमारे सम्मुख सदा ही जीवित रहे।' जब डॉ. राममनोहर लोहिया जैसे लोग उनके तर्क से सहमत हुये तब डॉ. लोहिया व दीनदयालजी का संयुक्त वक्तव्य आया कि 'भारत-पाक महासंघ' बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिये।

इसी अखण्डता की साधना में दीनदयाल जी ने कश्मीर के भारत विलय में उत्पन्न की गयी बाधाओं के खिलाफ देश भर में सत्याग्रह आयोजित किया। राष्ट्रीयता के साथ समझौते की प्रवृत्ति ने पुन: कश्मीर में आत्म निर्णय का बेसुरा राग अलापा। दीनदयालजी बोले "पाकिस्तान के निर्माता इस्लाम को राष्ट्रीयता का आधार मानकर चले हैं। इसी आधार पर वे मुस्लिम बहुल कश्मीर पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानते हैं। जिस दिन वे अपना अधिकार छोड़ देंगे, उनकी नींव खिसक जायेगी। किन्तु भारत द्वि-राष्ट्रवाद के सिद्धांत को न तो आज मानता है तथा न उसने कभी माना था। भारत का विभाजन यदि द्वि-राष्ट्रवाद के आधार पर होता, तो फिर यहां एक भी मुसलमान नहीं रह पाता।... यदि आज कश्मीर पर केवल इस कारण पाकिस्तान का अधिकार स्वीकार कर लें कि वहां मुसलमानों का बहुमत है, तो हम अपनी एक-राष्ट्रीयता की नींव पर कुठाराघात करेंगे। हमारे द्वारा जनता की राय जानने की घोषणा करना सैद्धांतिक दृष्टि से गलत था। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान आज उसी को पकड़े बैठा है।" पाकिस्तान के नाम से विभक्त भूमि तथा जन को वे अपना मानते थे तथा द्वि-राष्ट्रवादी अस्तित्व पाकिस्तान को अपना प्राकृत शत्रु मानते थे। बहुत लोगों को यह समीकरण समझ में नहीं आता, लेकिन दीनदयालजी इसी समीकरण को अपने जीवन में जीते थे।

एकात्म-राज्य की अवधारणा

एकात्मता के इसी बोध के कारण जब संविधान बन रहा था, उन्होंने मांग की भारत एक देश है, भारत का एक ही राज्य होना चाहिये। राजनैतिक भारत का अस्तित्व किन्हीं कृत्रिम राज्यों का संघ नहीं, वरन् उसे एकात्म-राज्य होना चाहिये। संविधान में स्वीकार की गयी संघात्मकता को वे 'भारत की राजनीति की मौलिक भूल' मानते थे। वे परम्परागत भारत की जनपदीय एवं पंचायत इकाइयों तक एकात्म-राज्य की सत्ता का विकेन्द्रीकरण चाहते थे। दुर्भाग्य से हमने पाश्चात्यों की नकल कर कृत्रिम रूप से भारत को राज्यों का संघ बनाया। राज्यों के गठन का आधार भाषा को बनाकर हमने अपने राजनैतिक जीवन में एक 'उप-राष्ट्रवाद' की दुर्गंध घोल दी। एक भयानक अनुभव से हम गुजरे, भाषावार राज्य रचना में बेहद हिंसा एवं पृथकतावाद का पोषण हुआ। भारतीय

बी.आर. कॉलेज (आगरा) छात्र संघ के उद्घाटन के अवसर पर सम्बोधित करते हुए

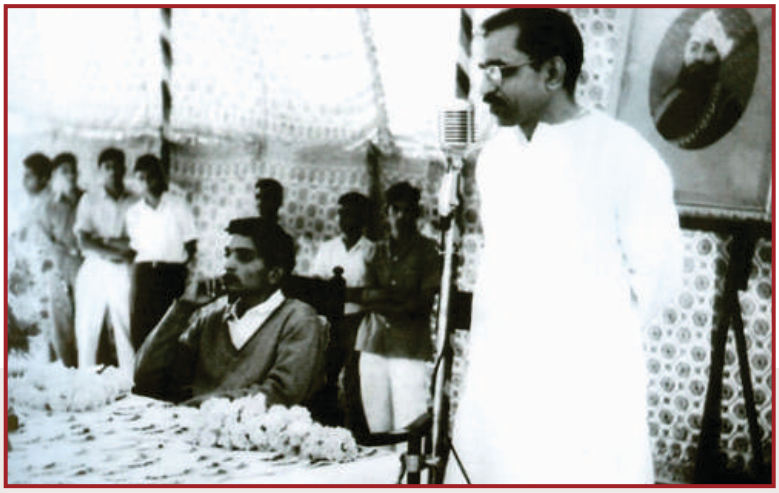

पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की स्मृति में जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर धानक्या रेलवे स्टेशन के पास राजस्थान सरकार द्वारा उनका एक भव्य राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है। यहां उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है।

जनसंघ के अलावा एक भी दल नहीं था , जो एक आवाज में बोल रहा हो।

हिंसा एवं भूख हड़ताल में हुई मौत के कारण पहला राज्य आन्ध्र प्रदेश बना तथा वैसी ही हिंसा के बाद नवीनतम राज्य तेलंगाना का निर्माण हुआ है। नदियों एवं क्षेत्रों के शाश्वत झगड़े हमने खड़े कर लिये हैं। भारतीय जनसंघ के प्रत्येक घोषणा पत्र में दीनदयालजी एकात्म राज्य की स्थापना को अपना लक्ष्य घोषित करते थे। कालीकट का उनकी ऐतिहासिक अध्यक्षीय उद्बोधन भी 'एकात्म-राज्य' की मांग को रेखांकित करता है। वे विविधता को पृथकता में परिवर्तित करनेवाली राजनीति के प्रखर एवं मुखर विरोधी थे।

साम्राज्यवादी शिक्षा ने हमें पढ़ाया था। भारत कोई देश या राष्ट्र नहीं है, वरन उपमहाद्वीप है। परिणामतः पाश्चात्य प्रभावित राजनेताओं के मन में महान एवं प्राचीन भारत की कल्पना नहीं थी, वे 'ब्रिटिश इंडिया' को ही भारत मानते थे। अतः भारत के वे हिस्से, जो अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं थे, उन हिस्सों को वे भारत नहीं मानते थे। पुर्तगाल नियंत्रित गोवा-दमण-दीव तथा फ्रांस नियंत्रित पांडीचेरी भी आजाद होने चाहिये, न केवल उन्होंने इसका प्रयत्न नहीं किया वरन् इनकी आजादी की मांग करने वालों को साम्राज्यवादी करार दिया। दीनदयाल उपाध्याय ने इस चुनौती को स्वीकार किया, गोवा मुक्ति संग्राम छेड़ा देशभर के विविध क्षेत्रों से गठित कर सौ लोगों का सत्याग्रही जत्था श्री जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में गोवा भेजा। सरकार, पुलिस कार्यवाही करे इसके लिए जनसमर्थन जुटाया। डॉ. लोहिया के समाजवादी दल ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया तथा भारत की अधूरी आजादी को कुछ पूरा करने में सफलता प्राप्त हुई। पं. दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक जीवन का यह प्रथम चरण राष्ट्र की अखण्डता को समर्पित है।

'आर्थिक लोकतंत्र' अर्थात प्रत्येक वयस्क को कार्यावसर

देश की अर्थव्यवस्था को निर्णायक आकार देने का यह समय था। साम्राज्यवादी अंग्रेज ने अपनी औद्योगिक क्रांति को सफल करने के लिये भारत के उत्पादन तंत्र को तोड़ दिया। अपने शासन एवं प्रशासन के चलाने के लिये उसने भारत की भावी पीढ़ी को सृजनात्मक एवं उत्पादक अर्थरचना से विलग कर नौकरी लोभी बनाया। भारतीय बाजार एवं प्राकृतिक संसाधनों का भयानक शोषण हुआ। 'सोने की चीड़िया' कहलाने वाला भारत कंगाल एवं दरिद्र बन गया। अर्थव्यवस्था के नये नियामक पाश्चात्यों के ही दूसरे ध्रुव 'समाजवाद' के रूझानवाले बन गये, सोवियत रूस का अनुगमन करते हुये, पंचवर्षीय योजनाओं का निरूपण हुआ। सहकारी खेती एवं उद्योगों के सरकारीकरण का यह दौर बहुत चुनौतीपूर्ण था। दीनदयाल उपाध्याय ने इस चुनौती को स्वीकार किया। शासन व समाज को चेताया। उनकी दो पुस्तकें आई पहली अंग्रेजी में 'टू प्लान्स : प्रॉमिसेज, परफोर्मेन्स, प्रोस्पेक्ट्स' (दो योजनायें- वायदे, अनुपालन, आसार) तथा दूसरी हिन्दी में 'भारतीय अर्थनीतिः विकास की एक दिशा' इन पुस्तकों में उन्होंने भारतीय 'अर्थायाम' का विश्लेषण किया। 'आर्थिक लोकतंत्र' की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि जैसे 'राजनीतिक लोकतंत्र का निकर्ष (कसौटी या परख) है, प्रत्येक वयस्क को मताधिकार, उसी तरह प्रत्येक वयस्क को कार्यावसर (रोजगार) यह आर्थिक लोकतंत्र का निकर्ष है।

स्वरोजगार, विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के हामी

उन्होंने परम्परागत 'स्वरोजगार कार्यक्षेत्र को सबल बनाने की सलाह दी। निजी एवं सरकारी क्षेत्र के कृत्रिम विभाजन को नकारने की सलाह दी। औद्योगिक क्रांति एवं उपनिवेशवाद के गर्भ से जन्मी केन्द्रीकरणवादी अर्थव्यवस्था का निषेध करते हुये विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था को अपना आदर्श बताया। अंत्योदय का प्रतिपादन करते हुये उन्होंने आगाह कि हमारी समस्या केवल अर्थ का अभाव (गरीबी) ही नहीं है। वस्तुत: अर्थ का अभाव एवं अर्थ का प्रभाव (उपभोगवादी अमीरी) दोनों धर्म के लिये क्षतिकारक होते हैं। उत्पादन में वृद्धि, वितरण में समता तथा उपभोग में संयम के त्रि-सूत्री समीकरण को उन्होंने प्रस्तुत किया। एक पुस्तक तथा 'योजना बदलो' शीर्षक से उन्होंने पांच धारावाहिक आलेख लिखे। वे पाश्चात्य 'वाद' परम्परा के ढांचे से बंधकर सोचने की बजाए भारतीय परम्परा एवं परिस्थिति को समझकर, व्यावहारिक आयोजन के पक्ष में थे। उन्होंने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं के लिये दो शब्दों का निदान पर्याप्त है, पहला है 'स्वदेशी' तथा दूसरा है विकेन्द्रीकरण।

'स्वदेशी' - एक व्यापक अवधारणा

'स्वदेशी' की उनकी अवधारणा केवल आर्थिकी तक सीमित नहीं थी। वे

पंडित जी एक कार्यक्रम में ध्वजारोहण करते हुए

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ विचार विमर्श करते हुए

पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. श्री भैरोंसिंह शेखावत जी के साथ बैठक के दौरान

व्यापक रूप से सम्पूर्ण व्यवस्थाओं एवं वातावरण का 'भारतीयकरण' चाहते थे। उनके आलेख 'लोकतंत्र का भारतीयकरण', 'शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण' और 'अर्थ व्यवस्था का भारतीयकरण' आदि प्रसिद्ध हुये।

सिद्धान्त, विचार एवं संगठन महत्वपूर्ण

भारतीयता एवं भारत की अखण्डता की उपासना करते हुये, वे भारतीय जनसंघ को गढ़ रहे थे। भारतीय जनसंघ का विस्तार व विकास लोगों को आश्चर्यचकित करने वाला था। कांग्रेस के बाद जनसंघ एक मात्र दल था, जो अखिल भारतीय दल के रूप में विकसित हुआ। प्रत्येक चुनाव में यह दल आगे बढ़ा, 1952 से 1967 तक हुये चुनाव इस बात के साक्षी हैं। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट तथा स्वतंत्रपार्टी सभी को पीछे छोड़ते हुये 1967 में यह दल कांग्रेस के बाद द्वितीय नम्बर का दल बन गया। शेष दलों के पास बड़े नामवर नेता थे, ये सभी दल किसी न किसी वर्गीय हित की बात करते थे। अत: इनके पास कोई न कोई वोटबैंक भी था। जनसंघ के पास न ऐसा 'नेता' था न कोई 'वोट बैंक', फिर यह दल आगे बढ़ कैसे रहा है, लोगों को समझ में नहीं आता था। वस्तुत: इसका रहस्य पं. दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व में था। वे व्यक्ति पूजक राजनीति के विरोधी थे। सिद्धान्त, विचार एवं संगठन को आगे रखते थे, व्यक्ति को इनके पीछे। उन्होंने निष्ठावान कार्यकर्त्ताओं की फौज निर्माण की। कार्यकर्त्ताओं में निष्ठायें पुष्ट हों, इसके लिये सैद्धांतिक स्पष्टताओं के लिये उन्होंने अप्रतिम परिश्रम किये। अभ्यास वर्गों एवं स्वाध्याय मण्डलों की श्रृंखला खड़ी की। स्वयं के जीवन का आदर्श खड़ा किया, स्वयं के जीवन में यह साकार करके दिखाया–

नहीं चाहिए पद–यश–गरिमा, सभी चढ़े माँ के चरणों में।
भारत माता की जय केवल, शब्द पड़े जग के करणों में।

परिणामत: जनसंघ के अप्रतिम अधिवेशन, कच्छ करार के खिलाफ भारत की राजनीति का प्रथम विराट प्रदर्शन इतिहास में रेखांकित हो पाये एवं राजनैतिक दल होते हुये भी उन्होंने उसे सांस्कृतिक आन्दोलन की तरह चलाया। भारतीय जनसंघ एक अलग प्रकार का दल है। किसी भी प्रकार सत्ता में आने की लालसा वाले लोगों का झुण्ड नहीं है। जनसंघ एक दल नहीं, वरन् आन्दोलन है। यह राष्ट्रीय अभिलाषा का स्वयंस्फूर्त निर्झर है। यह राष्ट्र के नियत लक्ष्य को आग्रहपूर्वक प्राप्त करने की आकांक्षा है।" दीनदयाल जी ने स्वयं कहा कि वे राजनीति में संस्कृति के राजदूत हैं। यही वह रहस्य था, जिससे जनसंघ सभी दलों को पीछे छोड़ते हुये आगे बढ़ा।

भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

'राष्ट्र राज्य' की राजनैतिक अवधारणा, जो पश्चिम से आयी थी, दीनदयाल जी ने इसमें निगड़ित (बेड़ीबद्ध) अमानवीयता को उजागर किया तथा 'भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की अलख जगायी। भारतीय समाज शास्त्र के राष्ट्रवाची तकनीकर शब्द पदां को उन्होंने खोजा। 'चिति' और 'विराट' संकल्पनाओं की युगानुकूल व्याख्या की। भौतिकतावादी क्षेत्रीय राष्ट्र-राज्यवाद के समक्ष चुनौती प्रस्तुत कर दी परिणामत: 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्यधारा के उद्घोष बन गए। आज भारत में बहुराष्ट्रवाद की कल्पना करने वाले वामपंथी तथा द्वि-राष्ट्र की कल्पना करने वाले मजहबी पृथकतावादी राजनेता जन-सामान्य के कठघरे में खड़े हैं।

एकात्म मानववाद

भारतीयता एवं राष्ट्रवाद के इसी चिन्तन ने दीनदयाल जी को 'एकात्म मानववाद' तक पहुँचाया। भारतीय मनीषा मानव को न तो केवल व्यक्ति मानती है तथा न केवल समाज। व्यक्ति और समाज को परस्पर विरोधी एवं पृथक इकाई भी भारतीय विचार नहीं मानता, जैसा कि पाश्चात्य 'व्यक्तिवाद' एवं 'समाजवाद' की विचारधारायें मानती हैं। दीनदयाल जी ने इनका प्रखरता एवं तार्किकता के साथ खण्डन किया तथा कहा 'व्यष्टि व समष्टि पृथक व परस्पर विरोधी नहीं, वरन् 'एकात्म' इकाई हैं। मानव इस एकात्मता की उपज है।' दीनदयाल जी ने इन 'एकात्मता' की संज्ञाओं को विस्तार दिया, मानव केवल व्यक्ति व समाज ही नहीं, वह प्रकृति का भी हिस्सा है, मानव केवल भौतिक इकाई नहीं है, उसमें आध्यात्मिकता निगड़ित है। अत: उन्होंने कहा 'व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि एवं परमेष्ठी की एकात्मता मानव में निगड़ित है।' एकात्म मानव का एक सांगोपांग विचार दर्शन उनकी युग को एक अनुपम एवं अद्भुत देन है।

त्रि–भाषा फॉर्मूला पर पंडित दीनदयालजी का लेख, पांचजन्य (15 मई, 1967)

पाञ्चजन्य : १५ मई १९६६

त्रि-भाषा सूत्र बनाम अंग्रेजी

— श्री दीनदयाल उपाध्याय

शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन तथा शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने फिर एक बार भाषा के प्रश्न को विवाद का विषय बना दिया है। यह विषय पिछले बीस वर्षों में अनेक बार चला है और दृष्टिकोणों का समन्वय करते हुए समझौते का मार्ग भी निकाला गया है। किन्तु अंग्रेजी भक्तों का एक ऐसा दुराग्रही अल्पमत है जो हर मौके का लाभ उठाकर मामले को कुरेदता रहता है तथा इस प्रश्न पर निश्चितता और स्थायित्व नहीं आने देता। समझौतों का उपयोग उसने अधिक सुविधायें लेने के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं के मार्ग में रोड़े अटकाये रखने के लिए ही किया है।

संविधान के निर्देशों की उपेक्षा

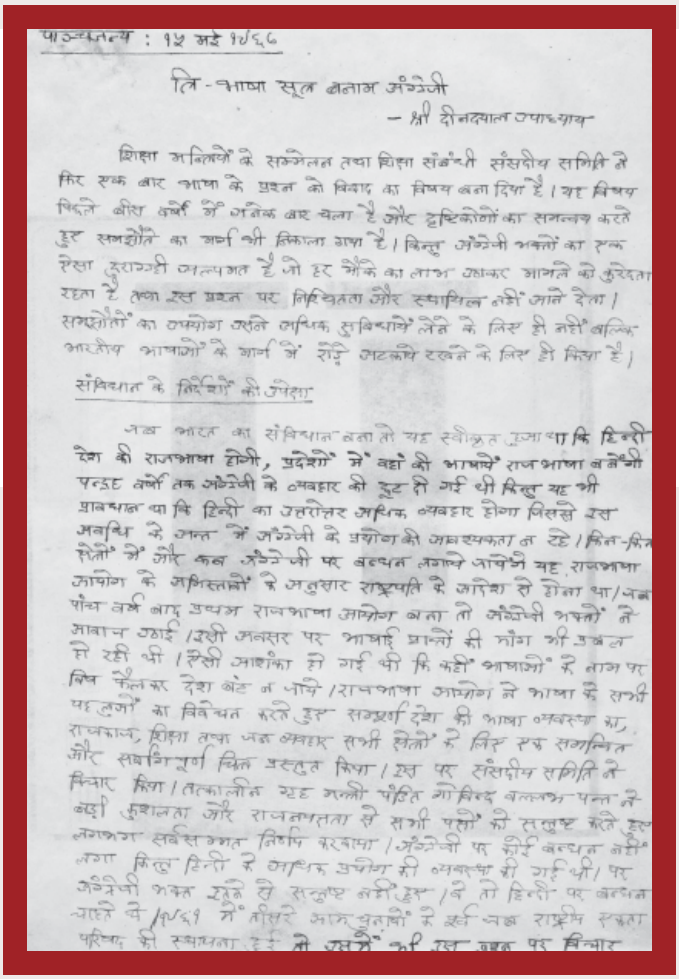

जब भारत का संविधान बना तो यह स्वीकृत हुआ था कि हिन्दी देश की राजभाषा होगी, प्रदेशों में वहां की भाषायें राजभाषा बनेंगी। पन्द्रह वर्षों तक अंग्रेजी के व्यवहार की छूट दी गई थी किन्तु यह भी प्रावधान था कि हिन्दी का उत्तरोत्तर अधिक व्यवहार होगा जिससे इस अवधि के अन्त में अंग्रेजी के प्रयोग की आवश्यकता न रहे। किन-किन क्षेत्रों में और कब अंग्रेजी पर बन्धन लगाये जायेंगे यह राजभाषा आयोग के अभिमतों के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश से होना था। जब पाँच वर्ष बाद प्रथम राजभाषा आयोग बना तो अंग्रेजी भक्तों ने आवाज उठाई। इसी अवसर पर भाषाई प्रान्तों की माँग भी उग्र हो रही थी। ऐसी आशंका हो गई थी कि कहीं भाषाओं के नाम पर [illegible] फैलकर देश बंट न जाये। राजभाषा आयोग ने भाषा के सभी पहलुओं का विवेचन करते हुए सम्पूर्ण देश की भाषा व्यवस्था का, राजकाज, शिक्षा तथा जन व्यवहार सभी क्षेत्रों के लिए एक समन्वित और सर्वांगपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया। इस पर संसदीय समिति ने विचार किया। तत्कालीन गृह मन्त्री पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त ने बड़ी कुशलता और राजनयता से सभी पक्षों को सन्तुष्ट करते हुए लगभग सर्वसम्मत निर्णय करवाया। अंग्रेजी पर कोई बन्धन नहीं लगा किन्तु हिन्दी के अधिक प्रयोग की व्यवस्था की गई थी। पर अंग्रेजी भक्त इससे सन्तुष्ट नहीं हुए। वे तो हिन्दी पर बन्धन चाहते थे। १९६१ में तीसरे आम चुनावों के पूर्व जब राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई तो उसने भी इस प्रश्न पर विचार

भारतीय जनसंघ के सभी कार्यकर्ताओं को विमर्श में सहभागी बनाते हुये उन्होंने 1964 में ग्वालियर के अभ्यासवर्ग में इस विचार को अंतिम रूप से लेख बद्ध किया। 'सिद्धान्त एवं नीति' नामक प्रलेख तैयार हुआ। इस प्रलेख की प्रस्तावना लिखते हुये दीनदयाल जी कहते हैं :-

"आज भारत के इतिहास में क्रांति लाने वाले दो पुरुषों की याद आती है। एक वह, कि जब जगद्गुरु शंकराचार्य सनातन बौद्धिक धर्म का संदेश लेकर देश में व्याप्त अनाचार को समाप्त करने चले थे और दूसरा वह, कि जब 'अर्थशास्त्र' की धारणा का उत्तरदायित्व लेकर संघ राज्यों में बिखरी राष्ट्रीय शक्ति को संगठित कर साम्राज्य की स्थापना करने चाणक्य चले थे। आज इस प्रारूप को प्रस्तुत करते समय वैसा ही तीसरा महत्वपूर्ण प्रसंग आया है, जबकि विदेशी धारणाओं के प्रतिबिम्ब पर आधारित मानव सम्बंधी अधूरे व अपुष्ट विचारों के मुकाबले विशुद्ध भारतीय विचारों पर आधारित मानव कल्याण का सम्पूर्ण विचार 'एकात्म मानववाद' के रूप में उसी सुपुष्ट भारतीय दृष्टिकोण को नये सिरे से सूत्रबद्ध करने का काम हम प्रारम्भ कर रहे हैं।"

एक नयी प्रस्थानत्रयी

दीनदयाल उपाध्याय भारतीय विचार परम्परा में शांकर वेदान्त, कौटिल्य अर्थशास्त्र व स्वयं द्वारा निरुपित 'एकात्म मानववाद' की एक नयी प्रस्थानत्रयी की स्थापना करते हैं।

दीनदयाल जी सैद्धांतिक व आदर्शवादी नेता थे, लेकिन वे नितांत व्यावहारिक भी थे। तभी तो उन्होंने इतना बड़ा राजनैतिक दल खड़ा कर दिया। देव दुर्लभ कार्यकर्त्ताओं की एक अद्भुत श्रृंखला का निर्माण कर दिया। जिस लोकतांत्रिक राजनीति में वे कार्य कर रहे थे, वे दलों की सीमाओं को जानते थे। अतः उनका ध्यान मतदाताओं पर अभिकेन्द्रित था। वे मानते थे कि स्वस्थ लोकतंत्र की पूर्व शर्त है 'लोकमत परिष्कार'। उन्होंने इसे एक अवधारणा के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया। उनका एक कालजयी वाक्य है 'सिद्धान्तहीन मतदान, सिद्धान्तहीन राजनीति का जनक है।' तृतीय महानिर्वाचन के पूर्व उन्होंने 'आपका मत' शीर्षक से नौ आलेख लिखे। ये आलेख ही 'लोकमत परिष्कार' को व्याख्यायित करने वाली पाठ्य सामग्री है। वे मानते है 'लोकतंत्र का नियामक नेता, संसद, दल या सरकार नहीं, वरन् 'मतदाता' है। उनका आग्रह था 'मतदाता को मतवान बनाओ।'

अपने काल की सब समस्याओं को उन्होंने दूर दृष्टि के साथ देखा। तात्कालिकता की मजबूरियाँ उन्हें कभी डिगा न सकी। सम्पूर्णता के साथ अभी उनका अध्ययन नहीं हो पाया है। आने वाली पीढ़ियों तक यदि उनका विवेचन पहुँच सकेगा, तो निश्चिय ही वे पीढ़ियाँ दीनदयाल जी की सार्थकता एवं प्रासंगिकता को समझेंगी। 1967-68 में दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बना दिये गये। पर्दे के पीछे से काम करने वाला व्यक्ति अब व्यासपीठ पर आ गया, दीनदयाल जी उत्सुकता उत्पन्न करनेवाली प्रसिद्धि प्राप्त करने लगे। बस नजर लग गयी, वे केवल 44 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे, साजिशों के क्रूर हाथों ने उन्हें हम से छीन लिया। अध्यक्ष के नाते उन्होंने ऐतिहासिक सम्बोधन दिया। समापन में उन्होंने कहा :–

'हम अतीत के गौरव से अनुप्राणित हैं, परन्तु उसको भारत के राष्ट्रजीवन का सर्वोच्च बिन्दु नहीं मानते। हम वर्तमान के प्रति यथार्थवादी हैं, किन्तु उससे बंधे नहीं। हमारी आँखों में भविष्य के स्वर्णिम सपने हैं, किन्तु हम निद्रालु नहीं, बल्कि उन सपनों को साकार करने वाले कर्मयोगी हैं। अनादि अतीत, अस्थित वर्तमान तथा चिरंतन भविष्य की कालजयी सनातन संस्कृति के हम पुजारी हैं।... विजय का विश्वास है, तपस्या का निश्चय लेकर चलें।'

राजस्थान सरकार द्वारा 24 जून से 9 जुलाई, 2025 तक आयोजित **'पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा'** ने प्रदेश के कोने-कोने में बदलाव की एक नई धारा प्रवाहित की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और संवेदनशील दृष्टिकोण में यह पखवाड़ा **'लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय'** की भावना को साकार करता दिखाई दिया। इस विशेष अभियान का उद्देश्य था – समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, वर्षों से लंबित समस्याओं का त्वरित समाधान करना और जनसेवा को शासन के विचार और व्यवहार का केंद्र बनाना।

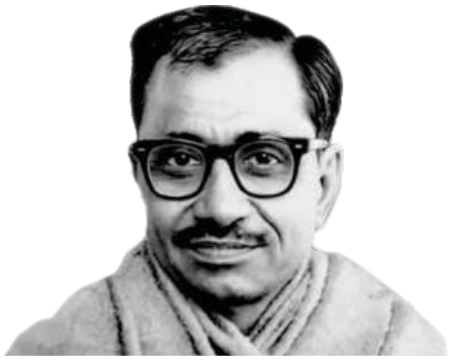

पं. दीनदयाल उपाध्याय

अन्त्योदय संबल पखवाड़ा

(24 जून से 9 जुलाई, 2025)

'लक्ष्य अन्त्योदय, प्रण अन्त्योदय, पथ अन्त्योदय'

इस पखवाड़े को केवल प्रशासनिक अभियान न मानते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं कई जिलों का दौरा कर न केवल शिविरों का निरीक्षण किया, बल्कि जनसामान्य से सीधे संवाद भी स्थापित किया। उन्होंने 3 से 8 जुलाई तक बालोतरा, जोधपुर, कोटा, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली–बहरोड़, चूरू, बीकानेर और सवाईमाधोपुर जैसे जिलों में आयोजित शिविरों में भागीदारी कर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया।

'वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई ये पांच आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति की पूरी होनी ही चाहिए।'

– पं. दीनदयाल उपाध्याय

जमीनों के प्रकरणों का धरातल पर हुआ समाधान

गांवों में लंबित राजस्व संबंधी प्रकरण एक आम समस्या है। इन समस्याओं के समाधान से किसान, मजदूर और जरूरतमंद व्यक्ति को व्यापक स्तर पर राहत पहुंचायी जा सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पखवाड़े के अंतर्गत राजस्व विभाग को नोडल नियोजित किया, जिसने 60 हजार 716 सीमाज्ञान, 1 लाख 32 हजार से अधिक नामांतरण, 26 हजार 858 सहमति विभाजन और 31 हजार 848 रास्तों से जुड़े मामलों का समाधान कर वर्षों पुराने विवादों को सुलझाया। इससे न केवल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हुआ, बल्कि आमजन को उनके हक के कागज भी प्राप्त हुए।

निर्बाध विद्युत–जल आपूर्ति को मिली गति

गांव ढाणी से लेकर कस्बे तक पर्याप्त बिजली-पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में पखवाड़े के दौरान ऊर्जा विभाग ने 55 हजार 437 झूलते बिजली तारों को दुरुस्त किया। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 43 हजार 493 नए नल कनेक्शन जारी कर और 15 हजार 869 पानी की टंकियों की सफाई कर ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की। इस दौरान वन विभाग ने 1 करोड़ 92 लाख 17 हजार से अधिक पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का पर्याय बने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को गति प्रदान की। कृषि विभाग द्वारा 1 लाख 91 हजार 197 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया।

आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा का कवच हुआ अधिक मजबूत

खाद्य विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 लाख 88 हजार 279 खाद्य सुरक्षा आवेदनों को निस्तारण किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1 लाख 95 हजार 270 पेंशनर्स का सत्यापन किया गया। इसके साथ ही, 8780 यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए और 79 हजार 577 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में पंजीकृत किया गया। इस दौरान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 17 हजार 938 स्कूटी हेतु ई-वाउचर जारी किए गए तथा 12 हजार 50 स्कूटियों का वितरण किया गया।

नई सोच, ठोस परिणाम

जैसलमेर की खुमानसर ग्राम पंचायत में गंगाराम की खातेदारी समस्या का त्वरित समाधान हुआ। वहीं श्रीगंगानगर की रावला तहसील में 30 साल से बंद रास्ता खुलवाया गया। साथ ही, धौलपुर के धनौरा गांव में 70 वर्षीय जगदीश और 85 वर्षीय पतोली का तीन दशक पुराना विवाद का निपटान हुआ। भीलवाड़ा की कोयली देवी को शिविर में खेत तक पहुंचने का रास्ता मिल सका। जन सेवा के ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं, पखवाड़े के माध्यम से लाखों लोगों को राहत पहुंचाई गई है।

यह पखवाड़ा राजस्थान सरकार की 'आपणो अग्रणी राजस्थान' की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत निरीक्षण और मार्गदर्शन ने इस अभियान को न केवल प्रभावी बनाया, बल्कि ग्रामीणों में विश्वास भी जगाया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। इन शिविरों में गरीब, मजदूर, महिला, युवा सहित सभी वर्गों की समस्याओं के समाधान ने अंत्योदय और सुराज संकल्प को सिद्धि की ओर बढ़ाया है। कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से छूट न जाए – यह संकल्प अब धरातल पर साकार हो रहा है।

बिचून, जयपुर

24 जून, 2025

पं. दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा
(24 जून से 9 जुलाई, 2025)

जन के साथ, ज़मीन से जुड़ा नेतृत्व

राजस्थान में जनकल्याण की एक नई इबारत लिखी गई जब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 24 जून को जयपुर जिले की दूदू तहसील के बिचून ग्राम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ किया। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का संकल्प था। शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में 2014 से आए परिवर्तन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का विज़न स्पष्ट है–गरीब, युवा, महिला और किसान ही देश की असली ताकत हैं। इन्हीं वर्गों को सशक्त करने से भारत का सर्वांगीण विकास संभव है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का ज़िक्र करते हुए उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है – जो सिर्फ पर्यावरण संरक्षण नहीं, भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी है।

इस अवसर पर आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री ने योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र, स्वीकृति पत्र और पट्टे वितरित किए। उनका सहज, सुलभ और संवेदनशील नेतृत्व जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने में सक्षम रहा।

> पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे विचारक थे, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज के वंचित और उपेक्षित वर्ग के लिए समर्पित कर दिया। पं. उपाध्याय का सपना था कि भारत का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। इस पखवाड़े के माध्यम से हम उसी संकल्प को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं।
>
> **मुख्यमंत्री**

एक कप चाय, आत्मीय संवाद

बिचून से जयपुर लौटते समय मुख्यमंत्री ने रास्ते में अपने काफिले को रोककर अचानक चाय की एक छोटी सी दुकान पर रुककर बारिश की फुहारों के बीच चाय का आनंद लिया। यह कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि एक मानवीय संवेदना से जुड़ा क्षण था, जहाँ उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से आत्मीयता से संवाद किया, उनकी कुशलक्षेम पूछी। रास्ते भर लोगों ने मुख्यमंत्री का फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया – यह आमजन के बीच उनकी स्वीकार्यता और जुड़ाव का प्रमाण था।

पं. दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा
(24 जून से 9 जुलाई, 2025)

चेहरों पर लौट रही मुस्कान

जोधपुर के दईजर में पं. दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जोधपुर की इस ऐतिहासिक भूमि पर 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत ने गरीब को गणेश मानकर अन्त्योदय का उद्घोष किया था।

श्री शर्मा ने कहा कि अन्त्योदय संबल पखवाड़ा गरीब और वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव का जरिया बना है। इसके अन्तर्गत शिविरों के माध्यम से गांवों में भूमि के सीमांकन, नामांतरण, सहमति विभाजन और रास्तों के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया गया है। साथ ही, गरीबी मुक्त गांव के लिए बीपीएल परिवारों का सर्वे, किसानों को सशक्त करने के लिए मृदा नमूनों का संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया है। पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण का विशेष प्रबंध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अभियान की उपादेयता के उदाहरण बताते हुए कहा कि 24 जून से प्रदेशभर में संचालित इन शिविरों में बड़ला बासनी गांव में पिछले पांच वर्षों से लंबित विवादित भूमि प्रकरण का शांतिपूर्ण समाधान हुआ है। वहीं, पंचायत समिति लूणी के सर गांव में 70 वर्षीय श्रीमती मोहन कंवर, बावड़ी के जोइंतरा गांव में 82 वर्षीय नेत्रहीन श्री फरसाराम, ओसियां के बारा खुर्द गांव में 90 वर्षीय श्री चुतराराम एवं भोपालगढ़ के अरटिया कलां गांव में विधवा श्रीमती कमला सहित विभिन्न लोगों को पेंशन का लाभ प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पं. दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का निरीक्षण किया तथा लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजन को व्हील चेयर व मोटराइज्ड ट्राई साइकिल और अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना व सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के लाभार्थियों को चैक प्रदान किए गए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री खेत सिंह निवासी श्रीरामनगर, बाडिया पुरोहितान एवं समस्त ग्रामवासियों को नए रास्ते एवं दईजर की श्रीमती ममता को प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, श्री नारायणराम हुडा को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व श्रीमती धापू को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रमाण-पत्र देकर लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पौधरोपण भी किया।

> “पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित अन्त्योदय का संकल्प हमारी सरकार का मूल मंत्र है। इसी संकल्प की दिशा में हमारी सरकार पं. दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक केन्द्र व राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। यह पहल हमारी सरकार की गांव व गरीब के प्रति संवेदनशीलता एवं उनके उत्थान की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।”
>
> **मुख्यमंत्री**

पं. दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा
(24 जून से 9 जुलाई, 2025)

वंचित वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास

> राज्य सरकार प्रदेश की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए कृत्संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पूर्वी राजस्थान के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना (ईआरसीपी), शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, देवास, माही, नर्मदा सहित विभिन्न परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है।
>
> **मुख्यमंत्री**

सवाई माधोपुर में बालेर (खंडार) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिविरों के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में इन शिविरों से आमजन के भूमि संबंधी विवादों का समाधान, नर्सरियों से पौधों का वितरण, मृदा नमूनों का संग्रहण, मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण, मंगला पशु बीमा, पशुओं की जांच, इलाज और टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड वितरण, गरीब परिवारों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा एनएफएसए सहित कई लंबित प्रकरणों के निस्तारण कार्य किए गए।

श्री शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, वहीं प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित हैं तथा 5 साल में 4 लाख सरकारी व 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं।

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास एवं उन्नयन के लिए काम कर रही है। खंडार विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के शिवाड़ और बहरावण्डा खुर्द में 132 केवी जीएसएस की स्थापना, विभिन्न सड़कों का चौड़ाईकरण तथा बनास नदी रपट निर्माण सहित विभिन्न निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। खंडार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन, राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत एनीकट निर्माण, पांचोलास से फलौदी सड़क मार्ग तथा आरसीसी कल्वर्ट ऑन कल्याणपुरा नाला विद अप्रोच सीसी रोड सहित विभिन्न निर्माण कार्य भी करवाए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपये की लागत से बालेर-करणपुर सड़क का निर्माण कराने की भी घोषणा की।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी श्री प्रवीण बैरवा (एनएफएसए), श्रीमती सरोज (कन्यादान योजना), श्रीमती सम्पत्ति देवी (वृद्धावस्था पेंशन), श्री रामवीर मीना (स्वामित्व पट्टा) तथा श्रीमती मीना देवी (पीएम आवास योजना) को प्रमाणपत्र एवं चैक वितरित किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने समारोह परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

पं. दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा
(24 जून से 9 जुलाई, 2025)

लंबित प्रकरणों में तुरंत राहत

खैरथल-तिजारा के ग्राम असलीमपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पखवाड़े के माध्यम से ग्राम स्तर पर ही किसानों को वर्षों से लंबित राजस्व के विभिन्न प्रकरणों में तुरंत राहत मिली है। गांवों में इन शिविरों के माध्यम से पानी, बिजली, स्वच्छता से जुड़े विभिन्न कार्य प्रमुखता से किए गए हैं। वहीं, हर पात्र परिवार तक आयुष्मान कार्ड का वितरण एवं पशुओं का टीकाकरण भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पखवाड़े में नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गांव गूगलहेडी में लगभग 25 घरों तक पहुंचने का रास्ता उपलब्ध नहीं था, शिविर में अतिक्रमण किए गए रास्ते को खुलवाकर 100 लोगों को रास्ता दिया गया।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अलवर, भरतपुर के लिए 5 हजार 432 करोड़ रुपये की चम्बल पेयजल योजना को स्वीकृति प्रदान कर तिजारा के 172 गांवों में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि अलवर की रूपारेल नदी के लिए मुख्यमंत्री ने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के माध्यम से जो प्रस्ताव भेजा उसे नेशनल वाइल्ड लाईफ बोर्ड से स्वीकृति मिल चुकी है। इससे रूपारेल नदी में पानी की आवक होगी।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि बीडा के माध्यम से भिवाड़ी, नीमराणा और अब बहरोड़ तक सतत विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां के ओद्योगिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए बजट में पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, तिजारा के लिए कन्या महाविद्यालय, खैरथल-तिजारा में सावित्री बाई छात्रावास और एक महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास की भी सौगात दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय सहायता से भिवाड़ी में खेलों के विकास के लिए इंडोर स्टेडियम और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन किया तथा विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर लाभार्थियो से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की लाभार्थी को चैक और स्कूल शिक्षा की मेधावी छात्राओं को स्कूटी का वितरण भी किया।

> हमारी सरकार खैरथल-तिजारा जिले में विभिन्न विकास कार्य करवा रही है। इन कार्यों से तिजारा विधानसभा क्षेत्र का भी चहुंमुखी विकास हो रहा है। तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। खुशखेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है।
>
> **मुख्यमंत्री**

पं. दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा
(24 जून से 9 जुलाई, 2025)

गरीब को समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास

> राज्य सरकार गरीब को गणेश मानते हुए सेवाभाव से उसे समाज की मुख्यधारा में लाने का कार्य कर रही है। 8 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने और प्रदेश के विकास रूपी पहिये को गति देने के लिए दिन-रात कार्य किया जा रहा है।
>
> **मुख्यमंत्री**

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गिरूड़ी गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कोटपूतली-बहरोड़ जिला प्रदेश की राजधानी जयपुर तथा देश की राजधानी दिल्ली के निकट होने के साथ ही आर्थिक राजधानी मुम्बई से भी जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र कृषि समृद्ध होने के साथ ही औद्योगिक दृष्टि से भी अग्रणी है। श्री शर्मा ने कहा कि जिले का नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र वैश्विक निवेशकों की पसंदीदा जगह है। कोटपूतली-बहरोड़ और नीमराणा में संचालित हजारों उद्योग स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करने के साथ ही प्रदेश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

कोटपूतली-बहरोड़ जिले को मिला 4 हजार करोड़ से अधिक का बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोटपूतली-बहरोड़ जिले के चहुंमुखी विकास के लिए 4 हजार 102 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। बानसूर विधानसभा के लिए भी अनेक काम किए हैं। नारायणपुर को नगर पालिका बनाने के साथ ही नारायणपुर सीएचसी में बैड संख्या बढ़ाकर 50 की गई है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपये की लागत से एमडीआर 50 से नयाबास वाया खेड़ा, श्यामपुरा, रसनाली, बासदयाल, बास शेखावत तक सड़क तथा 9 करोड़ से अधिक लागत से हाजीपुर से हरसौरा वाया गुवाड़ा, चूला, बावली का बास सड़क तथा साढ़े आठ करोड़ रुपये की लागत से कराणा से बिलाली स्टैंड वाया बड़ागांव बिलाली तक सड़क बनवाई जा रही है।

श्री शर्मा ने कार्यक्रम में श्री बलवीर भूपसेड़ा (पीएम कुसुम योजना), ग्राम पंचायत अजबपुरा की सरपंच श्रीमती प्रियंका नरूका (टीबी मुक्त ग्राम), ग्राम पंचायत हमीरपुर की सरपंच श्रीमती सीता देवी (टीबी मुक्त ग्राम), श्रीमती अनीता देवी (पीएम स्वनिधि योजना) एवं श्रीमती पूजा (मंगला पशु बीमा योजना) को चैक एवं प्रमाणपत्र वितरित किए। साथ ही ग्राम मोरोडी के श्री रामकरण, श्री राजेन्द्र व श्री गोपीराम को भूमि बंटवारे के कागजात सौंपे।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन किया और पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

पं. दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा
(24 जून से 9 जुलाई, 2025)

वंचित वर्ग के जीवन में बदलाव

सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा में अन्त्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत शिविर का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10 हजार गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे व उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है । मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बालोतरा जिले के चहुंमुखी विकास के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया है। नाकोड़ा उपस्वास्थ्य केंद्र का पीएचसी क्रमोन्नयन, खारा फांटा-सिणधरी-मिठोडा-सिवाना-देवंदी-मोकलसर एनएच-325 तक सड़क निर्माण, देवड़ा-फूलन राखी सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य तथा रामपुरा से बालोतरा वाया अजीत, समदड़ी, जेठंतरी, कनाना रोड का टेंडर स्वीकृत किया जा चुका है। साथ ही, पादरू में अनार की खेती को बढ़ावा देने के लिए मंडी परिसर के नजदीक 10 हेक्टेयर जमीन का आवंटन तथा किसानों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 50 एमवीए का ट्रांसफार्मर स्वीकृत कर लगवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सिणधरी से सिवाना मोकलसर और पाली जैतपुर - गेलावास - बरवा - मजल - करमावास डबल लेन सड़क का टेंडर किया जा चुका है। वहीं, बालोतरा एवं सिवाना में बफर स्टोरेज बनवाया जाएगा। चाडो की ढ़ाणी में नए कन्या महाविद्यालय का निर्माण जारी है। सिणधरी को नवीन नगर पालिका बनाने की अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। साथ ही, सिवाना में रोडवेज बस स्टैंड संबंधी कार्य करवाया जाएगा।

इससे पहले सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत पादरू में आयोजित शिविर का अवलोकन किया तथा विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर लाभार्थियो से संवाद किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थी प्रेमलता को चैक एवं रेखा को गोद-भराई किट प्रदान की। उन्होंने लाभार्थियों को राजश्री योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना के चैक एवं निक्षय पोषण किट भी वितरित किए। साथ ही, मंगला पशु बीमा पॉलिसी एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रमाण पत्रों का वितरण किया। वहीं, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की स्टॉल पर लाभार्थियों को मकान के पट्टे सौंपे एवं दिव्यांगों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर भी वितरित की।

> प्रदेशभर में 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत गांव में नामांतरण, स्वामित्व पट्टा, सहमति विभाजन, भूमि विवाद एवं रास्तों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का शिविरों में निस्तारण किया गया।
>
> **मुख्यमंत्री**

शेरगढ़, जोधपुर

5 जुलाई, 2025

पं. दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा
(24 जून से 9 जुलाई, 2025)

बदलते राजस्थान की तस्वीर

> हमारा प्रयास है कि समाज का कोई भी व्यक्ति या परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों में लोगों के चेहरों पर नजर आ रहा विश्वास बदलते राजस्थान की तस्वीर है, जिसमें शासन और प्रशासन आमजन के द्वार आ रहे हैं।
>
> **मुख्यमंत्री**

जोधपुर जिले की शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सोइंतरा ग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्त्योदय की भावना के साथ किए गए कार्यों से हमारा प्रदेश पूरे देश में समावेशी विकास का रोल मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में बिजली, पानी, रोजगार एवं उद्योग क्षेत्र की प्रगति के लिए कई कदम उठाए हैं। किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराना तथा युवाओं को पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियां देना हमारा लक्ष्य है। श्री शर्मा ने कहा कि जोधपुर उस ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, जिसने मरुभूमि की आत्मा को सदियों से संजोया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब तक 142 राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण करा चुकी है, जबकि गत सरकार ने 5 वर्षों में केवल 57 भवनों का निर्माण करवाया था। राज्य सरकार ने पिछले डेढ़ साल में 89 हजार स्कूली विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप तथा 10 लाख 51 हजार को साइकिलें वितरित की हैं, जबकि गत सरकार ने पूरे पांच साल में केवल 986 टैबलेट-लैपटॉप तथा 10 लाख 36 हजार साइकिलें ही बांटी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जोधपुर जिले के चहुंमुखी विकास के लिए 3 हजार 541 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र को भी कई सौगातें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कनोडिया पुरोहितान उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तथा सेखाला, नाथडाऊ एवं केतुकलां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्ग को आवास, बिजली, शौचालय, गैस कनेक्शन और बैंक खाते जैसी कई सुविधाएं मिली हैं, जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है।

इससे पहले श्री शर्मा ने 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान' के अंतर्गत मुख्यमंत्री वृक्ष कुंज का लोकार्पण किया व आमजन के साथ वृक्षारोपण किया। उन्होंने गोगाजी व आशापुरा माताजी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि व खुशहाली की कामना भी की।

पं. दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा
(24 जून से 9 जुलाई, 2025)

सेवा ही सुशासन का आधार

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कोटा के सांगोद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविर और सुपोषित मां अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कहा कि केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास तेजी से कर रही हैं। महिला कल्याण को प्रमुख प्राथमिकता देते हुए नीतियों एवं योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 14 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत प्रशिक्षण दिया है और लगभग 5 लाख 60 हजार महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना से 1 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया है। राज्य सरकार ने 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 10 लाख बालिकाओं को साईकिल वितरित की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवा रही है। हमने कोटा जिले के विकास के लिए 3 हजार 30 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने 26.24 करोड़ रुपये की लागत से परवन नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज तथा 45 करोड़ रुपये की लागत से कालीसिंध नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण किया। साथ ही, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्राम कनवास में 41.87 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के नवीन भवन निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया गया। उन्होंने सांगोद में 16.69 करोड़ रुपये की लागत से डलने वाली सीवरेज लाइन और ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास भी किया।

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि अंत्योदय संबल पखवाड़ा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उस विचारधारा का सजीव रूप है, जिसमें समाज के सबसे वंचित और जरूरतमंद व्यक्ति के कल्याण का संकल्प निहित है। राज्य सरकार ने इसी सोच के साथ इस पखवाड़े की शुरुआत की है, ताकि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। श्री बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेवा को सुशासन का आधार बनाया है। राज्य सरकार भी उसी सोच के साथ योजनाओं को पंचायत और गांव तक पहुंचा रही है। आज महिलाएं, युवा, किसान और मजदूर सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ रहे हैं। यह अंत्योदय की दिशा में एक ठोस कदम है।

> “यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में चार जातियां- किसान, युवा, महिला एवं मजदूर बताई हैं। उनकी मंशा के अनुरूप राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की पहल की है जिसके अंतर्गत 24 जून से 9 जुलाई तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से व्यापक कार्य कर इन वर्गों को लाभान्वित किया गया।”
>
> **मुख्यमंत्री**

पं. दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा
(24 जून से 9 जुलाई, 2025)

हर जरूरतमंद का हो रहा आर्थिक सशक्तीकरण

> प्रदेश के हर व्यक्ति-हर परिवार को सशक्त और समृद्ध बनाते हुए उनकी सेवा करना हमारी सरकार का सर्वोच्च ध्येय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा इसी दिशा में हमारा एक ठोस कदम है।
>
> **मुख्यमंत्री**

बीकानेर में श्रीडूंगरगढ़ के गुसांईसर बड़ा गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल शिविर के अंतर्गत आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरे समर्पण और निष्ठा से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गोपाल क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया। साथ ही, किसानों की मांग के अनुरूप मूंगफली की खरीद के लिए निर्धारित समय को भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए हम रामजल सेतु लिंक परियोजना (ईआरसीपी) और यमुना जल समझौता पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। साथ ही, हमने इंदिरा गांधी और गंगनहर परियोजना के विकास कार्य के लिए भी 4 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं, हम किसानों को वर्ष 2027 तक दिन के समय में बिजली उपलब्ध कराने के लिए दृढ़संकल्पित हैं।

श्री शर्मा ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास तेजी से कर रही है। महिला कल्याण को प्रमुख प्राथमिकता देते हुए नीतियों एवं योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाड़ो प्रोत्साहन योजना, मेधावी छात्राओं को साइकिल वितरण, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना आदि के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है। हमने डेढ़ वर्ष के अल्प कार्यकाल में 69 हजार पदों पर नियुक्तियां दी है और लगभग 1 लाख 88 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि डेढ़ साल में पेपरलीक का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रीडूंगरगढ़ में ट्रोमा सेंटर के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी आश्वस्त किया। श्री शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और उन्होंने सिंधु जल समझौते को निरस्त कर कड़ा संदेश दिया।

पं. दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय संबल पखवाड़ा
(24 जून से 9 जुलाई, 2025)

उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की परिकल्पना

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने चूरू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण को समर्पित है और इसी भावना के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन हुआ। जिसके माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। श्री शर्मा ने कहा कि चूरू जिले के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने बजट में 834 करोड़ रुपये का प्रावधान किया तथा चूरू विधानसभा में 300 करोड़ रुपये के काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपये से रिंग रोड वाया तारानगर वाया बालेरी से सरदारशहर वाया रतनगढ़ वाया देपलसर से एनएच-52 बाइपास सड़क निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही, 20 करोड़ रुपये से चूरू-जयपुर रोड ओवरब्रिज की मरम्मत की जा रही है। सिरसला रेलवे लाइन पर अंडरब्रिज, रामनगर तिराहा और ओम कॉलोनी में आरयूबी, चूरू शहर में एलीवेटेड रोड बनाने का काम भी किया जा रहा है।

लोकार्पण और शिलान्यास

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चूरू में 3 करोड़ 62 लाख रुपये से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह तथा 11 करोड़ 76 लाख रुपये से निर्मित 200 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही, श्री शर्मा ने 7 करोड़ 50 लाख रुपये से निर्मित चूरू में कृषि महाविद्यालय खांसोली का शिलान्यास भी किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत श्रीमती ममता (मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना), श्री गिरधारी सिंह (तारबंदी), श्री कुम्भाराम (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण), श्रीमती गोमती (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना), श्री गोपीराम तथा श्री प्रताप सिंह (विभाजन रिकॉर्ड) को प्रमाण-पत्र एवं चैक वितरण तथा भामाशाहों का सम्मान भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजनांतर्गत छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी। साथ ही, मुख्यमंत्री ने समारोह परिसर में पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्री शर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोड़ी के परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर का अवलोकन किया तथा रक्तदाताओं से मिलकर उनके नेक कार्य के लिए सराहना भी की।

> हम संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा करेंगे जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को गति मिलेगी।
>
> **मुख्यमंत्री**

आत्मनिर्भर गांव, समृद्ध राजस्थान

राजस्थान में 5000 गांव होंगे गरीबी मुक्त

नित नए प्रयासों और नवाचारों से प्रदेश के ग्रामीणजन के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रयासरत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' प्रारम्भ की गई है। यह योजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील पहल है। यह केवल आर्थिक सहायता की योजना मात्र नहीं है, बल्कि उन हजारों ग्रामीण परिवारों के सपनों को संबल देने वाला एक सशक्त कदम है, जो वर्षों से गरीबी के बोझ तले दबे हुए हैं।

पहले चरण में 30 हजार से अधिक बीपीएल परिवार

राज्य सरकार ने 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' के पहले चरण में राजस्थान के 5000 गांवों को चयनित किया है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े माने गए हैं। इन गांवों में 30,631 बीपीएल परिवारों की पहचान की गई है, जिन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत हर चिन्हित परिवार का भौतिक सर्वेक्षण किया गया है, ताकि उनकी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके। इन आंकड़ों का बीपीएल जनगणना 2002 के साथ मिलान कर वेब पोर्टल पर इन्द्राज भी कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। यह कार्य सिर्फ डेटा संग्रह का नहीं, बल्कि सामाजिक उत्थान की दिशा में एक ठोस नींव रखने जैसा है, जिसमें प्रत्येक जरूरतमंद को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा। सरकार की यह कार्य शैली यह दर्शाती है कि गरीबी उन्मूलन को लेकर अब योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि मूल्यांकन, सत्यापन और कार्यान्वयन की त्रिस्तरीय रणनीति के जरिए हर ग्रामीण परिवार की जिंदगी में वास्तविक परिवर्तन लाया जाएगा।

आत्मनिर्भर परिवार कार्ड : पहचान और गरिमा का प्रतीक

हर कहानी गरीबी की नहीं होती, कुछ कहानियां गरीबी से लड़कर जीतने की भी होती हैं। 'पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' के अंतर्गत उन परिवारों को विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने कठिन हालातों में भी हार नहीं मानी और अपने प्रयासों से खुद को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर दिखाया। राज्य सरकार ऐसे संघर्षशील और प्रेरणादायक परिवारों को 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज रही है। यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, उनके आत्मबल और मेहनत की सार्वजनिक स्वीकृति है। अब तक 17,891 परिवारों के खातों का सत्यापन पूरा हो चुका है और कुल 22,400 ऐसे परिवारों को यह सम्मान राशि मिलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही, इन परिवारों को 'आत्मनिर्भर परिवार कार्ड' दिया जा रहा है, जो केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक पहचान और गरिमा का प्रतीक होगा।

हर हाथ को हुनर, हर घर को रोजगार

'पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' केवल सम्मान या सहायता तक सीमित नहीं है, यह एक समग्र बदलाव की नींव है। योजना का

एक और महत्वपूर्ण और मानवीय पहलू यह है कि उन परिवारों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है, जो अभी भी कठिनाई से जूझ रहे हैं और जिन्हें सरकारी सहयोग की आवश्यकता है। राज्य सरकार ऐसे परिवारों को स्वरोजगार, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और अन्य सरकारी योजनाओं से सक्रिय रूप से जोड़ रही है। इसमें अब तक 61,442 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि गांव-गांव तक इस योजना की पहुंच, गूंज और उस पर लोगों के भरोसे का जीता-जागता सबूत है।

ठोस आर्थिक मदद की पहल

प्रत्येक बीपीएल परिवार को आजीविका गतिविधियों के लिए एक लाख रूपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। वहीं महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रति परिवार 15,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी दी जाएगी, जिससे वे अपने छोटे-छोटे उद्यम शुरू कर सकें और घर की आर्थिक रीढ़ बन सकें।

प्रोत्साहन से प्रेरणा

राज्य सरकार ने 'पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' को प्रभावी और परिणाममुखी बनाने के लिए एक त्रैमासिक रैंकिंग प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक तिमाही में उन जिलों का आकलन किया जाएगा, जिन्होंने योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट परिणाम दिखाए हैं और अधिक से अधिक बीपीएल परिवारों को गरीबी की जंजीरों से मुक्त कर आत्मनिर्भर बनाया है। इस रैंकिंग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को क्रमशः 50 लाख, 35 लाख और 25 लाख रुपये की आकर्षक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह वित्तीय पुरस्कार न केवल उन जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सम्मान और मान्यता का स्रोत होगा, बल्कि उन्हें और भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। इस पहल का उद्देश्य केवल योजना के क्रियान्वयन को मॉनिटर करना नहीं है, बल्कि हर जिले में प्रतिस्पर्धात्मक भावना जगाकर, स्थानीय प्रशासन को बीपीएल परिवारों के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे ग्रामीण विकास की गति तेज होगी और हर गांव में 'गरीबी मुक्त' होने का सपना जल्द ही साकार होगा।

दूसरे चरण में 5000 गांव

योजना के दूसरे चरण में भी पहले चरण की तरह 5000 गांवों को चयनित किया गया है, जहां अब तक 22,872 परिवारों का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। यह सर्वेक्षण न केवल आंकड़ों का संग्रह है, बल्कि हर परिवार की वास्तविक परिस्थितियों को समझने और उनकी जरूरतों के अनुसार मदद पहुंचाने का एक संवेदनशील प्रयास भी है। लगातार चल रहा सर्वेक्षण इस बात का सबूत है कि राजस्थान सरकार गरीबी उन्मूलन के अपने संकल्प के प्रति कितनी गंभीर और प्रतिबद्ध है। सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें गरीबी के जंजीरों से मुक्त करने की दिशा में एक निरंतर, सुनियोजित और व्यावहारिक योजना का हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़ों में सुधार करना नहीं, बल्कि हर गांव और परिवार की स्थिति में वास्तविक बदलाव लाना है। यही वजह है कि प्रत्येक परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनकी समस्याओं, जरूरतों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए, सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर लक्षित सहायता और विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं।

सामाजिक पुनर्निर्माण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक

आज जब 'आत्मनिर्भर भारत' की बात होती है, तो 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' 'आत्मनिर्भर गांव' की परिकल्पना को मूर्त रूप देती है। ये गांव अब केवल खेती-किसानी या पारंपरिक रीति-रिवाजों का केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि नवाचार, कौशल विकास, आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय के केंद्र बनेंगे। ग्रामीण जनता का स्वाभिमान बढ़ेगा, उनके सपने साकार होंगे और वे खुद अपने भविष्य के निर्माता बनेंगे। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में एक गहरा और स्थायी बदलाव लेकर आने वाली क्रांति है। यह योजना उन लोगों के लिए एक उजाला है जो दशकों से गरीबी की बंदिशों में जकड़े हुए थे। यह योजना 'अंत्योदय' के महान सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को भी विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, जो देश के अन्य हिस्सों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जहां हर गांव अपने आप में एक संपन्न, खुशहाल और आत्मनिर्भर समुदाय बनकर उभरेगा। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक समाज सुधार की नई कहानी है, जो गरीबी और असमानता के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक साबित होगी।

हरियाली तीज
76वां राज्यस्तरीय वन महोत्सव

हरयाळो राजस्थान मिशन में इस वर्ष लगेंगे 10 करोड़ पौधे

एक ही दिन में रिकॉर्ड ढाई करोड़ पौधे लगाए गए

कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

प्रदेशभर में 27 जुलाई को हरियाली तीज के अवसर पर 76वां वन महोत्सव मनाया गया। जयपुर के मदाऊ स्थित जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में हुए राज्य स्तरीय समारोह को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सम्बोधित किया।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन महोत्सव पर्यावरण एवं वृक्षों के संरक्षण के प्रति हमारे उत्तरदायित्व का प्रतीक है। राज्य सरकार इसे जन आंदोलन का रूप दे रही है। उन्होंने प्रत्येक प्रदेशवासी से अपनी मां के नाम कम से कम एक पौधा जरूर लगाने, उसे परिवार का सदस्य मानकर देखभाल करने और हरयाळो राजस्थान मिशन में सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि मां पार्वती और भगवान शिव को समर्पित हरियाली तीज पर वन महोत्सव मनाने का शुभ अवसर मिला है। हरियाली तीज ही नहीं, बल्कि सावन का पूरा महीना भगवान शिव की आराधना और उपासना से जुड़ा है। बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा से प्रदेश और देश में खूब बारिश हो रही है, जिससे चारों तरफ हरियाली है और खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। प्रदेश में आधे से ज्यादा बांध भर चुके हैं। यह पहली बार हुआ है कि बीसलपुर बांध जुलाई में ही भर गया। आज किसान, मजदूर सहित सभी वर्ग खुशहाल हो रहे हैं और हमारा राजस्थान समृद्ध हो रहा है।

भारतीय संस्कृति में वृक्षों का विशेष महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वृक्षों का विशेष महत्व है। मनुष्य किसी भी परिस्थिति में हो, वृक्षों के संग रहकर कुशल जीवनयापन कर सकता है। स्कंदपुराण में भी पेड़ों की महत्ता को दर्शाते हुए एक वृक्ष को दस पुत्रों के बराबर माना गया है। प्रभु श्रीराम का सीता माता एवं लक्ष्मण जी के साथ चौदह वर्ष तक वन में रहना प्रेरणादायी है। पांडवों ने वनवास के दौरान वन में आश्रय लिया और अपनी सभी जरूरतों को वनोपजों से पूरा किया।

एक दिन में ढाई करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने पिछले साल हरियाली तीज के पर्व पर मिशन हरयाळो राजस्थान का शुभारंभ किया था। गत वर्ष 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। राज्य सरकार इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। हरियाली तीज के पावन पर्व पर एक दिन में ढाई करोड़ पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। हरयाळो मिशन के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत अग्रणी

श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी हरित पहलों के माध्यम से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में भारत को अग्रणी बनाने का काम किया है। भारत ने फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पंचामृत की सौगात दी है, जिसमें भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा की आधी जरूरतें अक्षय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', 'स्वच्छ भारत मिशन' और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान जनता से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को स्वस्थ रखने में पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम नई पीढ़ी को पर्यावरण से जोड़ने के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान एक मिसाल

उन्होंने कहा कि राजस्थान में जल और पर्यावरण संरक्षण की परम्परा पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। मां अमृता देवी ने अपनी तीन बेटियों समेत 363 लोगों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहूति दी थी। हम उनकी इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए जोधपुर के खेजड़ली में अमृतादेवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध प्राणवायु के लिए नगर वन भी स्थापित किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार से 22 नगर वन स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा 18 अन्य नगर वनों की स्थापना के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाए गए हैं।

ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए उठा रहे महत्वपूर्ण कदम

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन कवर बढ़ाने के क्रम में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 3 हजार 500 से अधिक स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र बनाया गया है। वहीं, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और इसे हरा-भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये की हरित अरावली विकास परियोजना प्रारम्भ की है। हमने हरित राजस्थान बनाने के साथ पहली बार प्रदेश में ग्रीन बजट भी पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 'वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान' के माध्यम से जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐतिहासिक पहल की है। इसके अन्तर्गत 42 हजार से ज्यादा जल स्रोतों की सफाई हुई। वहीं, 'कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान' चलाकर 45 हजार जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

ड्रोन से किया बीजारोपण

समारोह में मुख्यमंत्री ने सिंदूर का पौधा लगाया और ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण भी किया। उन्होंने वन विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और रोहिड़ा पर आधारित ब्रोशर का विमोचन भी किया। उन्होंने अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार और इनोवेशन अवॉर्ड का वितरण किया। श्री शर्मा ने विश्वविद्यालय परिसर में जगद्गुरू रामानंदाचार्य की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया।

संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को हरियाला बनाने का संकल्प लिया गया है। प्रदेश एक हरित क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा ने कहा कि हम पौधे को लगाने के साथ ही उसके संरक्षण का कार्य भी कर रहे हैं, जिससे वे वृक्ष का आकार ले सके। इस दौरान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने प्रदेशभर में हरयाळो राजस्थान के अंतर्गत किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी।

ऑपरेशन सिंदूर

न्याय की अखंड प्रतिज्ञा

आतंक के आकाओं पर कहर बन बरसा

सिंदूर

आतंकियों का काल बना

ऑपरेशन महादेव

बायसरन घाटी में घटनास्थल पर केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह

संसद में ऑपरेशन महादेव की जानकारी देते केंद्रीय गृहमंत्री

22 अप्रेल, 2025 को पहलगाम, कश्मीर की बायसरन घाटी में आतंकी घटना में जयपुर के नीरज उधवानी सहित 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर अकारण ही मौत के घाट उतार दिया गया था। मृतकों में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक था। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से 7 मई को आतंक के आकाओं को सबक सिखाने और कम से कम 125 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद आखिर 28 जुलाई को सेना के 4 पैरा, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने उन तीन दरिन्दो को भी मौत के घाट उतार दिया, जिन्होंने धर्म पूछकर भारत की मां-बहिनों का सुहाग उजाड़ने का दुस्साहस किया था।

पहलगाम हमले के ठीक एक महीने बाद जब राजस्थान के पलाना बीकानेर में सार्वजनिक सभा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी 22 मई 2025 को पहलगाम के आतंकियों को ललकार रहे थे, ठीक उसी दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव की शुरूआत की।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लोक सभा में 29 जुलाई को अपने भाषण के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से आतंकी शिविरों और आतंकवादियों के आकाओं का सफाया किया तथा इसके बाद 'ऑपरेशन महादेव' के माध्यम से पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों का भी सफाया कर दिया गया है।

ऑपरेशन महादेव हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक बहुत बड़ी संयुक्त सफलता है, जिस पर देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व है।

आंतकी घटना में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि देते केंद्रीय गृहमंत्री

उन्होंने बताया कि कश्मीर के दाचीगाम में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त 'ऑपरेशन महादेव' में पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकवादी - सुलेमान उर्फ फैजल जट्ट, हमजा अफगानी और जिबरान को 28 जुलाई को मौत के घाट उतार दिया गया है। सुलेमान लश्कर-ए-तैयबा का 'ए' श्रेणी का कमांडर था, जो पहलगाम और गगनगीर में हुए आतंकवादी हमलों में शामिल था। अफगान और जिबरान भी लश्कर-ए-तैयबा के 'ए' श्रेणी के आतंकवादी थे, जिन्होंने बायसरन घाटी में हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी।

ऑपरेशन महादेव

22 अप्रैल 2025 को दोपहर 1 बजे पहलगाम हमले के बाद गृहमंत्री शाम 5:30 बजे श्रीनगर पहुंच गए थे। 23 अप्रैल को सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को पाकिस्तान भागने से रोकने के पुख्ता इंतजाम करने का निर्णय किया गया और उन्हें देश से भागने नहीं दिया गया। सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी व्यवस्था की कि ये आतंकवादी देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग सकें।

जिस दिन लश्कर और उसके संगठन टीआरएफ ने पहलगाम हमले की ज़िम्मेदारी ली थी, उसी दिन तय कर लिया गया था कि इस हमले की जांच एनआईए करेगी। गृहमंत्री ने बताया एनआईए को आतंकवादी मामलों की वैज्ञानिक जांच करने और दोषियों को सज़ा दिलाने में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त एजेंसी के रूप में विशेषज्ञता प्राप्त है और एनआईए की दोषसिद्धि दर 96 प्रतिशत से ज़्यादा है।

ऑपरेशन महादेव 22 मई 2025 को शुरू किया गया था। पहलगाम के हमले के ठीक एक महीने बाद 22 मई 2025 को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को दाचीगाम क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की मानव खुफिया सूचना मिली।

दाचीगाम में अल्ट्रा सिग्नल पकड़ने के लिए भारतीय एजेंसियों द्वारा बनाए गए उपकरणों के माध्यम से प्राप्त इस सूचना की पुष्टि के लिए आईबी और सेना द्वारा 22 मई से 22 जुलाई तक निरंतर प्रयास किए गए। आईबी, सेना और सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान, उनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए ठंड और ऊंचाई पर पैदल चलते रहे।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले श्री नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

22 जुलाई को सेंसर के माध्यम से सफलता मिली और आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई। तब 4 पैरा के नेतृत्व में सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों ने मिलकर आतंकवादियों को घेर लिया और 28 जुलाई के ऑपरेशन में तीनों आतंकवादियों को मार दिया गया।

आतंकियों के साथ खूनी राइफलों की भी पुष्टि

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इन तीनों आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जब इन तीनों आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, तो चार लोगों ने उनकी पहचान की और बताया कि इन तीनों आतंकवादियों ने ही पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था।

इसके बाद पहलगाम आतंकवादी हमले के स्थल पर मिले कारतूसों की एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर, दाचीगाम में इन तीनों आतंकवादियों से बरामद तीन राइफलों से उनका मिलान किया गया। ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीन आतंकवादियों के पास से तीन राइफलें बरामद की गईं - एक 19 एम-4 कार्बाइन और दो एके 47।

तीनों राइफलों को 28 जुलाई की रात ही में एक विशेष विमान से चंडीगढ़ पहुंचाया गया और गोलीबारी करके इनके खाली खोल तैयार किए गए। इसके बाद पहलगाम हमले में मिले कारतूसों का राइफलों की बैरल और गोलीबारी के बाद निकले गोलों से मिलान किया गया और तब यह पुष्टि हुई कि पहलगाम में इन्हीं तीनों राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई थी।

कड़ी से जोड़ी कड़ी

हमले की जांच की शुरुआत में ही मृतकों के परिवारों से बातचीत की गई, पर्यटकों, खच्चर मालिकों, टट्टू मालिकों, फ़ोटोग्राफ़रों, कर्मचारियों और दुकान में काम करने वालों सहित कुल 1055 लोगों से 3000 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई और यह सब वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड किया गया। एनआईए ने गहन जांच की और 1055 लोगों के बयान लिए।

इस प्राप्त जानकारी के आधार पर आतंकवादियों के स्केच बनाए गए और 22 जून 2025 को बशीर और परवेज की पहचान की गई, जिन्होंने पहलगाम हमले के अगले दिन आतंकवादियों को पनाह दी थी। बशीर और परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने खुलासा किया कि 21 अप्रैल 2025 की रात 8 बजे तीन आतंकवादी उनके पास आए थे और उनके पास दो एके 47 और एक एम 4 कार्बाइन राइफल थी।

बशीर और परवेज की मां ने भी मारे गए तीनों आतंकवादियों की पहचान की और एफएसएल ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि ये ही तीनों पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी थे और इनसे बरामद 2 एके 47 और एक एम 9 कार्बाइन का इस्तेमाल इस हमले में किया गया था। एनआईए ने बैसरन घाटी से खाली कारतूस बरामद किए थे और उनकी फोरेंसिक साइंस लैब में जाँच की गई थी। जब ये आतंकवादी मारे गए, तो उनसे बरामद राइफलों की जाँच की गई और फोरेंसिक मिलान के बाद यह शत-प्रतिशत पुष्टि हुई कि पहलगाम हमले में इन्हीं तीनों राइफलों का इस्तेमाल किया गया था। यह भी पाया गया कि इनमें से 44 कारतूस 19 एम-4 कार्बाइन के थे और 25 कारतूस एके 47 राइफल के थे।

पाकिस्तानी वोटर आईडी, पाकिस्तानी चॉकलेट

पूरे सबूत हैं कि ये तीनों पाकिस्तानी थे क्योंकि तीन में से दो आतंकवादियों के पाकिस्तानी वोटर नंबर उपलब्ध हैं, राइफलें भी उपलब्ध हैं, उनके पास जो चॉकलेट मिली हैं वो भी पाकिस्तान में बनी थीं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में 23 अप्रैल और 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठकों में यह संकल्प लिया गया कि ये आतंकवादी जहां कहीं भी छिपे हैं और उन्हें जो भी प्रशिक्षित कर रहे हैं, उन्हें सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ द्वारा उचित जवाब दिया जाएगा।

इन आतंकवादियों को मारना इतना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि 22 दिनों तक सीआरपीएफ, सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में इन आतंकवादियों का पीछा किया और ड्रोन से भेजे गए भोजन पर पलकर उन्हें मार गिराया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में कहा था कि आतंकवादियों के पास जो भी ज़मीन बची है उसे नष्ट कर दिया जाएगा और आज उनके प्रशिक्षण शिविर, मुख्यालय और लॉन्च पैड सब तहस-नहस कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें उखाड़ दी गई हैं और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोदी सरकार ने 75 पाकिस्तान समर्थक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।

आखिर पहुंचे अंजाम तक...

Give up अभियान से साकार हो रही सामाजिक न्याय की अवधारणा

अभियान के अंतर्गत 24 लाख लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा, एनएफएसए से जुड़े 53 लाख नए लाभार्थी

– **अमनदीप**, जन संपर्क अधिकारी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग निरंतर प्रदेश में सभी पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रहा है। प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में एनएफएसए के अंतर्गत लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीलिंग है। यह संख्या पूरी हो जाने के कारण नए पात्र वंचित व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने हेतु गिव अप अभियान गत वर्ष 1 नवंबर को शुरू किया गया।

गिव अप अभियान के तहत प्रदेशभर में गत वर्ष एक नवंबर से अब तक 24 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा द्वारा विभिन्न जिलों का दौरा कर गिव अप अभियान की गहन समीक्षा की जा रही है। श्री गोदारा ने बताया कि विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के कारण प्रदेश की जनता ने इस अभियान को सामाजिक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा है। आमजन से मिले सहयोग के कारण आज गिव अप अभियान प्रदेश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि सभी सक्षम लाभार्थी अभियान की अवधि में स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा त्यागें, ताकि असल हकदारों को योजना का लाभ मिल सकें। उन्होंने कहा की सक्षम लोगों द्वारा छोड़ी गई खाद्य सब्सिडी गरीब के मुंह का निवाला बनती है। राज्य सरकार की वास्तविक हकदारों को लाभ दिलाने की इस अभिनव पहल का अनुकरण अन्य विभागों द्वारा भी किया जाएगा। इससे राज्य सरकार के संसाधनों का न्यायसंगत वितरण संभव हो सकेगा।

गिव अप अभियान के द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ने के साथ साथ प्रदेश में 27.62 लाख लोगों द्वारा ई-केवाईसी संपन्न नहीं करवाई जाने के कारण स्वत: ही उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हट गया। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा सूची में नए पात्र व्यक्तियों के लिए जगह बनी। 26 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कर कमलों से खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुन: प्रारंभ होने के बाद, अब तक 53.79 लाख पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जोड़े जा चुके हैं। राज्य सरकार के इस कदम से खाद्य सुरक्षा का लाभ पात्र वंचितों को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत प्रति वर्ष 450 रुपये में 12 गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत नि:शुल्क चिकित्सा भी मिल रही है। राज्य सरकार के इस कल्याणकारी कदम से वंचित लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है एवं वे मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने की बजट में घोषणा की थी। इस लक्ष्य को बजट सत्र के दौरान ही विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया। एनएफएसए में पात्र वंचितों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने हेतु जिला कलेक्टर को भी खाद्य सुरक्षा सूची में लाभार्थी को शामिल करने के लिए अधिकृत किया गया है।

खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित गिव अप अभियान के तहत सक्षम लाभार्थियों द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने की प्रक्रिया को ओर सुगम बनाया गया है। इसके तहत सक्षम लाभार्थी अब खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जाकर स्वतः अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकते हैं। इससे पहले खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने हेतु ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लगने के कारण खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने के इच्छुक सक्षम लाभार्थी गिव अप अभियान से जुड़ नहीं पा रहे थे। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लाभार्थी निम्नांकित लिंक का उपयोग कर सकते हैं: https://rrcc.rajasthan.gov.in/NfsaGiveUpStatus.aspx

निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले परिवार अपात्र

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे परिवार, जिनका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है तथा ऐसे परिवार जिनके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर), खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे परिवार, जिनके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक हो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपात्र होंगे। अभियान की अवधि में स्वेच्छा से नाम न हटवाने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरूद्ध नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

शान से निकली तीज माता की सवारी

राजस्थान की राजधानी जयपुर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का जीवंत मेल है। इन्हीं परंपराओं में शामिल है **तीज माता की सवारी**, जो हर साल श्रावण मास में धूमधाम से निकाली जाती है। जयपुर में यह पर्व एक भव्य शोभायात्रा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें तीज माता की सवारी मुख्य आकर्षण होती है। तीज माता को देवी पार्वती का रूप माना जाता है, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तीज का पर्व इसी तपस्या और शिव-पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति में मनाया जाता है।

राजस्थानी संस्कृति के रंग-बिरंगे तीज त्योहार के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से जयपुर में 27 एवं 28 जुलाई को आयोजित दो दिवसीय तीज महोत्सव-2025 के अवसर पर पहले दिन पारम्परिक तीज माता की सवारी निकाली गई। इस पारम्परिक तीज महोत्सव में तीज माता की भव्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, आम नागरिक, देशी-विदेशी पर्यटक शामिल हुए।

तीज महोत्सव के अवसर पर तीज माता की आरती के लिए छोटी चौपड़ पर बड़े मंच पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल जी महाराज, विधायकगण श्री बालमुकुंद आचार्य और श्री गोपाल शर्मा, जयपुर नगर निगम, हेरिटेज,

महापौर श्रीमती कुसुम यादव, जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर एवं देशी विदेशी पर्यटक एवं आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

माता की शोभायात्रा में कच्छी घोड़ी, शेखावाटी क्षेत्र के गैर नृत्य की झांकी ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। बहुरुपिया कलाकारों ने श्री नारद, श्री कृष्ण, श्री शंकर भोले जैसे अपने बहुरूपों से मोहित किया। कालबेलिया नृत्यांगनाओं ने अपनी मोहक नृत्य कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चरी नृत्य, हेला ख्याल की शानदार प्रस्तुतियों की झांकियों के साथ ही कठपुतलियों का नर्तन भी मंचित हुआ।

बांक्या वादन, ध्वज वाहक, हाथियों की शाही सवारी, मधुर बैंड वादन सजे-धजे बैल, ऊंटों की कतार, रणबांकुरे जवान, मोर डांस, बड़ा नगाड़ा नाद सवारी के दौरान राजसी ठाठ का नजारा प्रस्तुत कर रहे थे। तीज माता की भव्य सवारी त्रिपोलिया गेट से शुरू हुई। सबसे पहले लाल बग्घी, बैंड टोली और तीज माता की सवारी आई। त्रिपोलिया के दोनों ओर खड़े भक्तों ने तीज माता के जयकारे लगाये।

भव्य रूप से आयोजित तीज उत्सव और तीज माता की अद्भुत शोभायात्रा में राजस्थान की लोक कलाओं में निपुण लगभग 200 कलाकारों ने राजस्थान की रंग-बिरंगी संस्कृति को साकार कर दिया। लोक-कलाकार ने अपनी कलाओं के प्रदर्शन से जयपुर वासियों सहित यहां आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की शानदार कला-संस्कृति से परिचित करवाया।

चिदानंदरूपः
शिवोऽहम् शिवोऽहम्

भगवान शिव, चेतना के सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान स्वरूप हैं। सत्यम् शिवम् सुंदरम् की अवधारणा उनके माध्यम से ही मूर्त होती है। वे परम तत्त्व होते हुए भी अत्यंत सहज हैं, सरल हैं। यही कारण है कि अत्यल्प उपासना में ही वे प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष भी कहा गया है।

भारतवर्ष में विविध धार्मिक परंपराओं की पृष्ठभूमि एवं पल्लवन में राजस्थान की धरा भी एक विशिष्ट स्थान रखती है। यहां वैष्णव, शैव और शाक्त परंपराएं सह-अस्तित्व में फलती-फूलती रही हैं। विशेष रूप से शैव परंपरा की जड़ें यहां इतनी गहरी हैं कि हर श्रावण मास में, जब वातावरण में हरियाली और नम शीतल बयारों का संगम होता है, तब प्रदेश के कोने-कोने से श्रद्धालु गंगाजल और अन्य पवित्र स्रोतों का जल लेकर शिवालयों की ओर उमड़ पड़ते हैं। यह आलेख राजस्थान के कुछ ऐसे ही प्राचीन, दिव्य और ऐतिहासिक शिव मंदिरों की एक संक्षिप्त परंतु सारगर्भित यात्रा है, जो न केवल हमारी धार्मिक चेतना को समृद्ध करते हैं, अपितु स्थापत्य-कला की दृष्टि से भी अद्वितीय धरोहर हैं।

हर्षनाथ मंदिर (सीकर)

यह मंदिर सीकर के हर्ष पर्वत पर स्थित है। इसका निर्माण 10वीं सदी में विग्रहराज द्वितीय के काल में हुआ था। मंदिर में लिंगोद्भव शिव की मूर्ति स्थापित है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु को शिवलिंग का आदि और अंत जानने हेतु परिक्रमा करते हुए दर्शाया गया है। यह मंदिर महामारू शैली में निर्मित है। इसे औरंगजेब के सेनापति खानजहां बहादुर ने ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद राजा शिवसिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया।

कायावर्णेश्वर महादेव (झालावाड़)

क्यासरा गांव के पास स्थित श्री कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहां के शिवलिंग की विशेषता यह है कि इसका आकार हर 12 वर्षों में सुपारी जितना बढ़ता है। मंदिर के गर्भगृह में विशाल लिंग स्थापित है और पास ही मंदाकिनी कुंड स्थित है। मान्यता है कि राजा जनमेजय ने इस कुंड में स्नान कर अपने रोगों से मुक्ति पाई और यहीं से शिवलिंग प्राप्त कर उसकी स्थापना की। मंदिर में उनकी मूर्ति भी विराजमान है।

अजय-गंध महादेव (अजमेर)

अजमेर नगर के पश्चिम में अरावली पर्वतमालाओं के बीच स्थित अजय गंध महादेव मंदिर अपनी विशिष्ट गंध वाले शिवलिंग के कारण प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इसका निर्माण छठी-सातवीं शताब्दी में राजा अजय पाल ने कराया

एकलिंगजी (उदयपुर)

उदयपुर नाथद्वारा मार्ग पर स्थित एकलिंगजी मेवाड़ के महाराणाओं के इष्टदेव रहे हैं। 8वीं सदी में बप्पा रावल द्वारा स्थापित यह मंदिर पाशुपत सम्प्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। भगवान शिव की चौमुखी लिंगमूर्ति के चारों ओर सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप अंकित हैं, जो उनके त्रिकालदर्शी और त्रिदेवात्मक स्वरूप को दर्शाते हैं। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को एकलिंगजी का दीवान मानते हुए शासन किया।

था। एक किंवदंती के अनुसार, जब पुष्कर में ब्रह्मा जी का यज्ञ हो रहा था, तब भगवान शिव की अवज्ञा से अग्नि प्रकट नहीं हुई। बाद में कपालेश्वर रूप में भगवान शिव की कृपा से अग्नि प्रज्वलित हुई। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने यज्ञ की सिद्धि हेतु कृपा की और तभी से पुष्कर क्षेत्र की रक्षा हेतु उनका यह पावन धाम स्थापित हुआ।

हरिहरेश्वर मंदिर (बदराना, झालावाड़)

बदराना गांव में दो नदियों के संगम पर श्री हरिहरेश्वर का मंदिर है। यह मंदिर शिव और विष्णु के अद्वितीय सम्मिलन का प्रतीक है, जहां एक ही मूर्ति में आधे भाग में शिव तथा दूसरे भाग में विष्णु का दर्शन होता है।

शीतलेश्वर महादेव (चंद्रभागा)

चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित अनेक मंदिरों में शीतलेश्वर महादेव मंदिर सबसे बड़ा और प्राचीन है। एक अभिलेख में इसे चंद्रशेखर शिव का मंदिर बताया गया है, जिसमें शिव की विश्वमूर्ति रूप में उपासना हुई है। यहां मुख्य रूप से शिव की लकुलीश रूप की उपासना होती थी, जो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन शिव मंदिर माना जाता है। प्रवेश द्वार पर दो भुजाओं वाले लकुलीश की प्रतिमा उत्कीर्ण है। वराह मूर्ति की चौकी पर मिले अभिलेख में पाशुपत आचार्य द्वारा लकुलीश उपासना का उल्लेख लकुलीश संप्रदाय की लोकप्रियता दर्शाता है।

अचलेश्वर महादेव (माउंट आबू)

यह मंदिर भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा का केंद्र है। अचलगढ़ की पहाड़ियों में स्थित यह स्थल शिव के विराट शरीर की प्रतीकात्मक आराधना का सशक्त रूप है।

बाड़ौली के शिव मंदिर (चित्तौड़गढ़)
गुप्तकालीन स्थापत्य शैली में निर्मित यह मंदिर समूह धार्मिक आस्था और शिल्प सौंदर्य का अद्वितीय संगम है। नौ मंदिरों के इस समूह में घाटेश्वर महादेव का मंदिर सबसे प्रमुख और भव्य है।

देव सोमनाथ मंदिर (डूंगरपुर)

12वीं सदी में निर्मित यह त्रिस्तरीय मंदिर सोम नदी के किनारे स्थित है और अपनी स्थापत्य विशिष्टताओं के लिए प्रसिद्ध है। 108 खंभों पर टिका यह मंदिर मिट्टी और चूने से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय स्थापत्य की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है।

भंडदेवरा शिव मंदिर (बारां)

इसे 'हाड़ौती का खजुराहो' कहा जाता है। पंचायतन शैली में निर्मित यह मंदिर स्थापत्य और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग (शिवाड़, सवाई माधोपुर)

कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाने वाला यह स्थान शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदिर की स्थापना सुदेहा और उसकी बहन घुश्मा की चमत्कारी कथा से जुड़ी है। यह मंदिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य आभा के लिए प्रसिद्ध है।

नीलकंठ महादेव (सरिस्का, अलवर)

घने जंगलों में स्थित यह मंदिर 10वीं सदी के बड़गुजर शासकों द्वारा निर्मित माना जाता है। यहां की प्रकृति और आध्यात्मिकता, साधकों को एक अलग ही अनुभव देती है।

परशुराम महादेव (राजसमंद-पाली सीमा)

500 सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद पहुंचने वाला यह गुफा मंदिर भगवान परशुराम की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। यहां चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता ध्यान और साधना को सहज बनाती है।

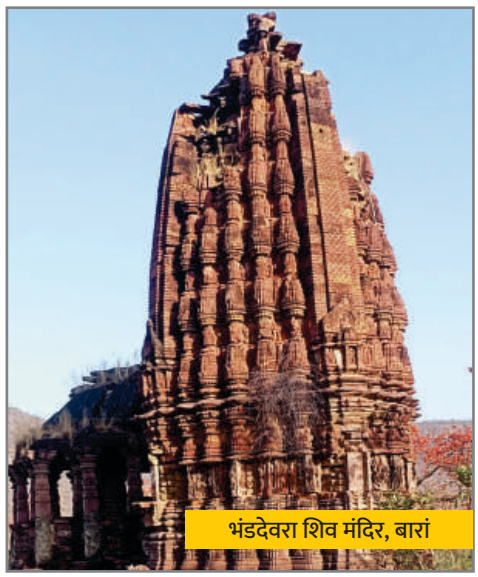

भंडदेवरा शिव मंदिर, बारां

मण्डलेश्वर शिव मंदिर, बांसवाड़ा

मंडलनाथ महादेव, जोधपुर

नीलकंठ महादेव, अलवर

घुश्मेश्वर, सवाई माधोपुर

अचलेश्वर महादेव मंदिर, सिरोही

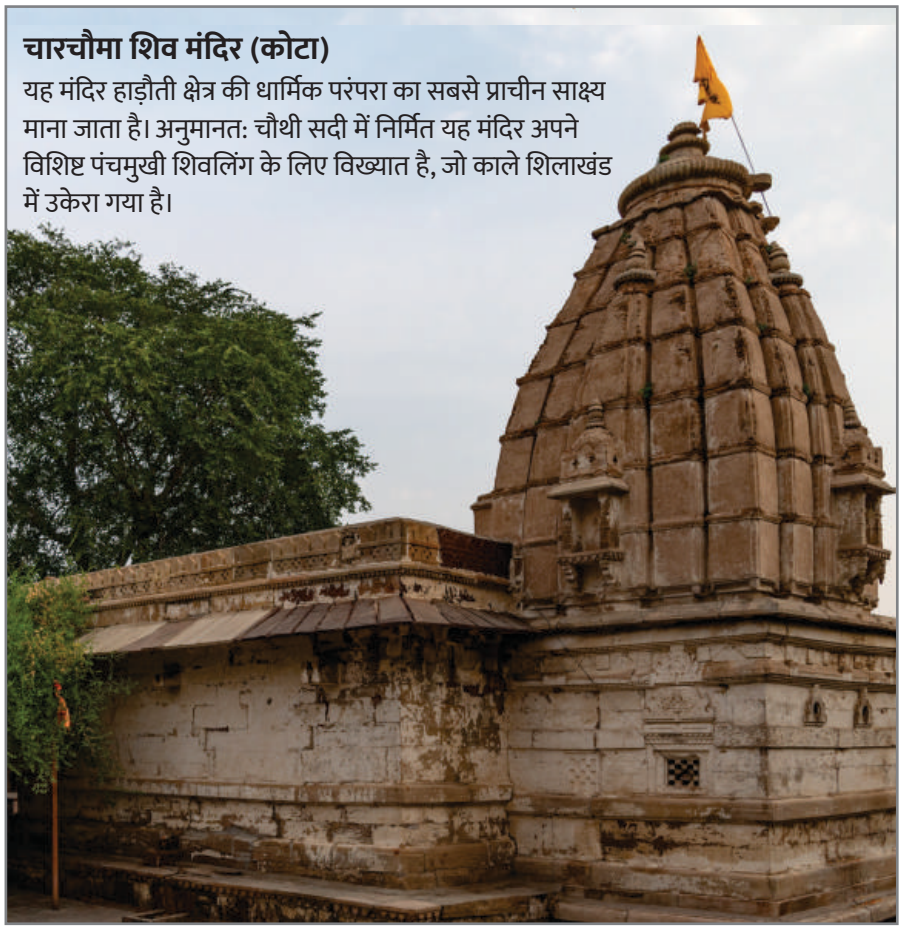

चारचौमा शिव मंदिर (कोटा)

यह मंदिर हाड़ौती क्षेत्र की धार्मिक परंपरा का सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। अनुमानत: चौथी सदी में निर्मित यह मंदिर अपने विशिष्ट पंचमुखी शिवलिंग के लिए विख्यात है, जो काले शिलाखंड में उकेरा गया है।

बीसलदेव मंदिर (टोंक)

बीसलपुर बांध के समीप स्थित यह मंदिर 12वीं शताब्दी का स्थापत्य चमत्कार है। भगवान शिव को गोकर्णेश्वर के रूप में यहां पूजा जाता है। जलाशय के कारण मंदिर का बाहरी क्षेत्र अब जलमग्न रहता है।

मालेश्वर महादेव (जयपुर)

सामोद के समीप स्थित यह मंदिर सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन के साथ शिवलिंग के झुकने की अनोखी प्राकृतिक घटना के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर 1101 ई. का है और यहां स्थित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है।

राजस्थान के शिव मंदिर केवल ईंट-पत्थरों के स्थापत्य नहीं हैं, वे आस्था, इतिहास और आत्मिक चेतना के जीवंत केंद्र हैं। ये मंदिर हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की निष्ठा, स्थापत्य के सौंदर्य और सनातन परंपरा की गरिमा को समेटे हुए हैं।

जिन शिव को चंद्रमौलि, त्रिपुरांतक, नीलकंठ और शंभु कहा जाता है, वे इस धरा पर अपनी कृपा वर्षा करते रहें और जनमानस को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें, यही प्रार्थना है।

हर हर महादेव।

शिव आराधना के साथ जनकल्याण की कामना

भगवान भोलेनाथ के प्रिय और पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण वातावरण में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सपत्नीक मंत्रोच्चार व वैदिक विधि-विधान के अनुसार भगवान शिव का पूजन और रुद्राभिषेक किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, शांति और सर्वांगीण कल्याण की प्रार्थना की।

श्रावण मास : चहुं ओर उल्लास

भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम

कांवड़ यात्रा

भारतीय संस्कृति में सावन का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव की उपासना में सहस्रघट, कांवड़ यात्रा और सोमवार को शिवालयों में दर्शन, सहित पूरे माह शिव भक्ति के आयोजन हर कहीं दिखाई देते हैं। इस माह पूरे देश में विशेष श्रद्धा और उत्साह के साथ लाखों भक्तगण कांवड़ यात्रा निकालते हैं, जो शिवभक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है।

कांवड़

श्रावण मास में कांवड़ यात्रा में विभिन्न प्रकारों की कांवड़ देखने को मिलती है, **जैसे खड़ी कांवड़, हथेस्वरी कांवड़, डाक कांवड़, दांडी कांवड़ आदि**। अधिकतर कांवड़िए बाजार से बांस की बनी साधारण या सजी हुई कांवड़ खरीदते हैं, जिनमें दो टोकरियां और एक मेहराब होती है, जिन्हें रंग-बिरंगे वस्त्रों, रिबनों, शिव-पार्वती के चित्रों, त्रिशूल, डमरू आदि से सजाया जाता है। अक्सर कांवड़िए गेरुआ वस्त्र और शिव की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनते हैं, पैरों में घुँघरू बांधते हैं, जिससे लय बनी रहती है और यात्रा का वातावरण भक्तिमय होता है। सामान्य कांवड़िए रास्ते में विश्राम कर सकते हैं, जबकि डाक कांवड़िए बिना रुके शिवलिंग तक पहुंचते हैं। खड़ी कांवड़ में सहयोगी भक्त कांवड़ को हिलाते रहते हैं, ताकि उसका संतुलन बना रहे, वहीं दांडी कांवड़ में भक्त दंडवत करते हुए लेट-लेटकर कठिन तप के साथ यात्रा पूरी करते हैं, जो गहन भक्ति और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है।

ऐतिहासिक मान्यताएं

जनश्रुति के अनुसार पहला कांवड़िया भगवान परशुराम को माना जाता है। उन्होंने अपने पिता ऋषि जमदग्नि की आज्ञा पर कांवड़ में गंगाजल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। एक अन्य लोकमान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से विष निकला था, उसका भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षार्थ स्वयं पान कर लिया। इसके बाद उनके कंठ नीले पड़ गये व शरीर में जलन होने लगी। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ महादेव भी कहते हैं। तत्पश्चात देवताओं ने जलाअभिषेक किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त रावण ने घोर तप किया। इसके लिए वह कांवड़ में जलभर कर लाया और भगवान शिव का जलाभिषेक किया।

कांवड़ यात्रा का वैज्ञानिक महत्व

सावन मास में वातावरण शुद्ध, ठंडा और हरियाली से भरपूर होता है, जो यात्रा के लिए अनुकूल होता है। इस समय नंगे पांव चलने से शरीर के एक्यूप्रेशर बिंदु सक्रिय होते हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है। गंगाजल में औषधीय गुण होते हैं और उसे पैदल ले जाना शरीर के संतुलन और सहनशक्ति को बढ़ाता है। यह यात्रा मानसिक एकाग्रता, संयम, धैर्य और भक्ति की भावना को भी प्रबल करती है। इसमें भाग लेने से सामाजिक एकता, सहिष्णुता और मेलजोल की भावना का भी विकास होता है। यात्रा के परंपरागत नियम जैसे पैदल चलना, ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, मौन या भक्ति में लीन रहना, 'ॐ नमः शिवाय' का जप करना और गंगाजल को कांवड़ में झुलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना, ये सभी आध्यात्मिकता के साथ-साथ सामाजिक अनुशासन और धैर्य को भी सशक्त करते हैं। इस प्रकार कांवड़ यात्रा धार्मिक होने के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी लाभकारी है।

गलता कुंड का पवित्र जल

शिवालयों में अर्पित

जयपुर, जिसे 'छोटी काशी' के नाम से जाना जाता है, में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। यह यात्रा गलता से शुरु होकर गलता जी मंदिर, सूर्य मंदिर और कई अन्य छोटे-बड़े मंदिरों में पहुंचती है। कांवड़िये सबसे पहले गलता जी के पवित्र कुंड से जल भरते हैं, जिसे वे श्रद्धा और भक्ति के साथ विभिन्न शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। जयपुर में कई प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं, जहाँ कांवड़ यात्रा जाती है, जो शहर की धार्मिक परंपरा में गहरा स्थान रखते हैं। कांवड़ यात्रा आमतौर पर गलता से शुरु होकर गलता जी मंदिर, झारखंड महादेव मंदिर, मदारेश्वर मंदिर, एकलिंगेश्वर मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर और अंबिकेश्वर आदि मंदिरों में पहुंचती है, जहां पवित्र कुंड का जल अर्पित किया जाता है। यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करती है।

रामदेवरा पदयात्रा

बाबा रामदेव पैनोरमा से मंदिर तक

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपनी एक दिवसीय जैसलमेर यात्रा के दौरान रामदेवरा में बाबा रामदेव पैनोरमा से बाबा रामदेव मंदिर तक पैदल यात्रा की। उन्होंने इस पदयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं से आत्मीयता से मुलाकात की। श्रद्धालु भी अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर बेहद उत्साहित नजर आए। पदयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं (जातरूओं) ने विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री का फूल बरसाकर तथा माला पहनाकर स्वागत-अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव की ध्वजा (नेजा) थामे पैदल यात्रा की। इस भक्तिमय माहौल में लोक कलाकार रिक्खियां गाते हुए मुख्यमंत्री के साथ-साथ चले। पदयात्रा समाप्त होने पर मुख्यमंत्री बाबा रामदेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि स्थल के दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इसके बाद श्री शर्मा डालीबाई के समाधि स्थल भी पहुंचे तथा वहां भी पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने परिसर में स्थित जम्मा जागरण स्थल पर बाबा रामदेव की रिक्खियों का श्रवण किया।

डिग्गी कल्याणजी का लक्खी मेला

आस्था और परंपरा का सैलाब

राजस्थान के टोंक जिले के डिग्गी गांव में हर वर्ष सावन शुक्ल एकादशी को आयोजित होने वाला डिग्गी कल्याणजी का लक्खी मेला आस्था, परंपरा और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम है।

भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी महाराज को समर्पित यह स्थल जन-जन की श्रद्धा का केंद्र है। मेले का प्रमुख आकर्षण 90 किलोमीटर लंबी 'लक्खी पदयात्रा' है, जो जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर से आरंभ होकर डिग्गी कल्याण जी मंदिर तक पहुंचती है। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों, हरिनाम संकीर्तन और भजन करते हुए सामूहिक रूप से शामिल होते हैं। मार्ग में भंडारे, सेवा शिविर, चिकित्सा और विश्राम की निःशुल्क व्यवस्था स्थानीय लोगों और संस्थाओं द्वारा की जाती है, जिससे यह यात्रा न केवल भक्ति, बल्कि सेवा, अनुशासन और परम्परागत लोकसंस्कृति का जीवंत उदाहरण बन जाती है।

इस वर्ष 60वीं पदयात्रा का शुभारंभ 31 जुलाई, 2025 को ध्वज पूजन और आरती के साथ हुआ। यह मेला यह दर्शाता है कि भक्ति सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि जनसंपर्क, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समर्पण का उत्सव भी है।

गुरु तत्व की सक्रियता का अवसर

गुरु पूर्णिमा

सदियों से भारतवर्ष ने ज्ञान की भूमि पर गुरु को ईश्वर से भी ऊँचा स्थान दिया है। कबीरदास ने कहा था–

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पांय।
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय॥

यह केवल दोहा नहीं, भारतीय चेतना की नींव है। गुरु पूर्णिमा वह विशेष दिवस है, जब हम न केवल अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, बल्कि अपने भीतर की शिष्यता को पुन: जागृत करते हैं – यह विनम्रता, यह जिज्ञासा और यह समर्पण, आध्यात्मिक उत्थान की पहली सीढ़ी है।

गुरु ज्ञान का दाता है, परंतु शिष्य बनने की पात्रता हमारा प्रयास है

– डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

गुरु पूर्णिमा: एक पावन संयोग

गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह वह दिन है जब चंद्रमा, पृथ्वी और अन्य ग्रह एक विशेष सीध में आते हैं, जिससे मानव चेतना विशेष रूप से ग्रहणशील बन जाती है। यहीं से गुरु तत्व–वह दिव्य ऊर्जा जो अज्ञान के अंधकार को काटती है–सक्रिय होता है। यही वह दिन था जब आदि योगी शिव ने सप्तर्षियों को योग का पहला उपदेश दिया था। उन्होंने उन सातों साधकों को अपना शिष्य स्वीकारा और यहीं से गुरु परंपरा की शुरुआत मानी जाती है।

गुरु के छह गुणात्मक आयाम (वृत्तियाँ)

एक सच्चा गुरु केवल शिक्षाविद नहीं होता–वह संवेदना, ऊर्जा, दृष्टि और करुणा का अद्भुत समन्वय होता है। गुरु की सत्ता में छह विशिष्ट वृत्तियाँ होती हैं, जो उसे साधारण मानव से विलक्षण बनाती हैं

1. गणेश वृत्ति : गुरु के भीतर स्थिर बुद्धि, गहरी विवेकशक्ति और निर्णय क्षमता होती है। जैसे श्रीगणेश ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं, वैसे ही गुरु शिष्य के भ्रम और संशयों का नाश करते हैं। वे बिना भावनात्मक उलझनों में फंसे, जीवन की जटिलताओं को सरल मार्गदर्शन में बदलते हैं।

2. गौरी वृत्ति : गौरी यानी शक्ति और सौम्यता का संतुलन। गुरु में श्रद्धा, करुणा और ममतामयी स्त्रीत्व का भाव होता है। वे न केवल सिखाते हैं, बल्कि भावनात्मक स्तर पर सहारा भी देते हैं, जैसे एक मां अपने शिशु को गोद में उठाती है।

3. गंगा वृत्ति : गंगा बहती है ऊँचाई से नीचे की ओर–उसी तरह गुरु स्वयं को नम्र करता है, ताकि शिष्य को ऊँचाई पर ले जा सके। वह अपने अहं को पीछे रखकर शिष्य के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करता है। यह वृत्ति गुरु के निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक है।

4. गौ वृत्ति : गौ यानी गाय–सरलता, सहनशीलता और वात्सल्य की मूर्ति। गुरु शिष्य के सभी दोषों को सहकर भी उसे प्रेम करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। गुरु की यह वृत्ति, एक अभिभावक के समान उसकी कोमलता और धैर्य को दर्शाती है।

5. गगन वृत्ति : गगन यानी आकाश–असीम, अनंत, व्यापक दृष्टि। गुरु सीमाओं में नहीं बंधते। उनका दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि समष्टिगत होता है। वे हर परिस्थिति को एक विस्तृत, समग्र दृष्टिकोण से देखते हैं और शिष्य को भी उसी दिशा में विकसित करते हैं।

6. गुणग्राही वृत्ति : गुरु का हृदय सर्वग्राही होता है–वे हर स्थान, हर अनुभव और हर प्राणी में अच्छाई को खोजते हैं। वे आलोचना नहीं, ग्रहणशीलता में विश्वास रखते हैं और यही गुण उन्हें एक संपूर्ण मार्गदर्शक बनाता है।

गुरु के विविध स्वरूप

गुरु केवल एक भूमिका नहीं, बल्कि एक अवस्था है। वह जीवन में कई रूपों में आता है–कभी सशरीर, कभी चेतन ऊर्जा के रूप में। भारतीय संस्कृति ने गुरु को कई रूपों में स्वीकारा है :

1. परमगुरु : जैसे भगवान शिव–जो दृष्टिगत नहीं होते, परंतु उनकी उपस्थिति सम्पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ब्रह्म चेतना के प्रतिनिधि हैं। उनके मार्गदर्शन का स्वरूप आंतरिक होता है–मौन, मगर गहन।

2. सदगुरु : वह गुरु जो हमारे जीवन में सशरीर उपस्थित रहता है। वह हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति या योग के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। वह हमारा दैनिक पथप्रदर्शक होता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।

3. जगद्गुरु : जिनका ज्ञान केवल किसी एक व्यक्ति या समुदाय के लिए नहीं, अपितु पूरे विश्व के लिए होता है। जैसे श्रीकृष्ण, जिन्होंने गीता में केवल अर्जुन को नहीं, पूरी मानवता को ज्ञान दिया और आदि शंकराचार्य, जिनका अद्वैत दर्शन आज भी समकालीन है।

4. धर्मगुरु : धर्मगुरु वे होते हैं, जो समाज में धार्मिक अनुशासन, मर्यादा और नैतिकता की स्थापना करते हैं। उनका मार्ग भय और नियमों से शुरू होता है, लेकिन अंततः वे भी आत्मानुभूति की ओर ले जाते हैं।

5. कुलगुरु : परिवार या वंश की परंपरा में प्रतिष्ठित गुरु, जैसे शुक्राचार्य (दानवों के गुरु) या बृहस्पति (देवताओं के गुरु)। ये गुरुओं की परंपरा और ज्ञान-संरक्षण की श्रृंखला को बनाए रखते हैं।

गुरु केवल बाहर नहीं होते, वे भीतर भी होते हैं। वह मौन भी सिखाता है, और शब्द भी। वह उपस्थित भी होता है, और अदृश्य भी। लेकिन वह तब प्रकट होता है, जब शिष्य तैयार होता है।

गुरुवंदन : श्रद्धा और सम्मान

गुरु केवल पूजा के नहीं, सम्मान के अधिकारी हैं। यही भाव लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गत वर्ष से एक ऐतिहासिक पहल की –

गुरु पूर्णिमा पर 'गुरुवंदन कार्यक्रम'

गुरुजनों का प्रदेशव्यापी सम्मान

10 जुलाई 2025 को राज्यभर में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र में धर्मगुरुओं, महंतों और पुजारियों को 2100 रुपये की सम्मान राशि, श्रीफल, शॉल, मिठाई और अभिनंदन–पत्र से सम्मानित किया गया। मंत्रीगण, विधायकगण और जिला कलेक्टर स्वयं उपस्थित रहकर इस गुरु-वंदना में सहभागी बने। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि "गुरु पूर्णिमा गुरु-शिष्य परंपरा की आत्मा है। गुरुओं के सम्मान से ही हमारी सनातन संस्कृति सशक्त होती है।"

आस्था और सेवा का संगम

इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर जिले के पूंछरी का लौठा में श्रीनाथजी मंदिर में पंचामृत से अभिषेक किया उन्होंने सपत्नीक पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि के लिए कामन की। उन्होंने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण-संरक्षण का संदेश दिया।

बाद में मुख्यमंत्री ने सेवर स्थित बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचकर महंत श्री रामदास जी महाराज का गुरु पूजन कर सम्मान किया, तथा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण की।

इस दौरान उन्होंने जनता की जनसुनवाई कर त्वरित समाधान के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। यह न केवल उनकी आध्यात्मिक चेतना, बल्कि जनप्रतिनिधित्व की संवेदनशीलता का भी परिचायक है।

'सर्वजन हिताय' के साथ डबल इंजन सरकार

सहकार, रोजगार और सुरक्षा से सबका उत्थान

राजस्थान की राजधानी जयपुर के समीप स्थित दादिया गांव 17 जुलाई, 2025 को एक ऐतिहासिक दिन का साक्षी बना। यहां सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के उस समर्पण का प्रतीक था, जो 'सर्वजन हिताय' के संकल्प के साथ देश को समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम में रोजगार, सहकारिता, सुरक्षा, किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और कई योजनाओं का लाभ जनसामान्य तक पहुँचाया गया।

अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की दृढ़ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत आज दुनिया को स्पष्ट संदेश दे चुका है कि उसकी सीमाओं, सेना और नागरिकों से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक और हालिया पहलगाम हमले के जवाब में "ऑपरेशन सिंदूर" के तहत आतंकवादियों को पाकिस्तान की धरती पर जाकर समाप्त करना इस बदले हुए भारत की छवि को दर्शाता है। श्री शाह ने इसे एक मजबूत भारत की पहचान बताया।

राजस्थान की ऐतिहासिक पहचान को रेखांकित करते हुए श्री शाह ने महाराणा प्रताप, राणा सांगा, रानी पद्मिनी, पन्नाधाय जैसे महान योद्धाओं का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि न केवल वीरता की, बल्कि देशभक्ति और धर्म रक्षा की भी प्रतीक है। कृषि क्षेत्र में भी राज्य का योगदान महत्वपूर्ण है। देश के कुल ग्वार उत्पादन का 90 प्रतिशत राजस्थान से आता है। इसके साथ ही सरसों, बाजरा, तिहलन और मोटे अनाजों (मिलेट्स) के उत्पादन में भी राजस्थान देश में अग्रणी है।

उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बन चुके पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए राजस्थान सरकार ने विशेष एसआईटी का गठन किया, जिससे राज्य में निष्पक्षता और पारदर्शिता की बहाली हुई। श्री शाह ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे युवाओं का सरकारी तंत्र पर विश्वास और मजबूत हुआ है।

राइजिंग राजस्थान : निवेश के नए द्वार

श्री शाह ने कहा कि राजस्थान सरकार की निवेश नीति की सफलता का उदाहरण 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' है, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू हुए। इनमें से लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम भी प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती की, 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया और जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में पानी पहुंचाने की दिशा में अहम कार्य किए हैं। नवनेरा बैराज और ताजेवाला हैड से जल आपूर्ति की पहलें जल संरचना को और सुदृढ़ कर रही हैं।

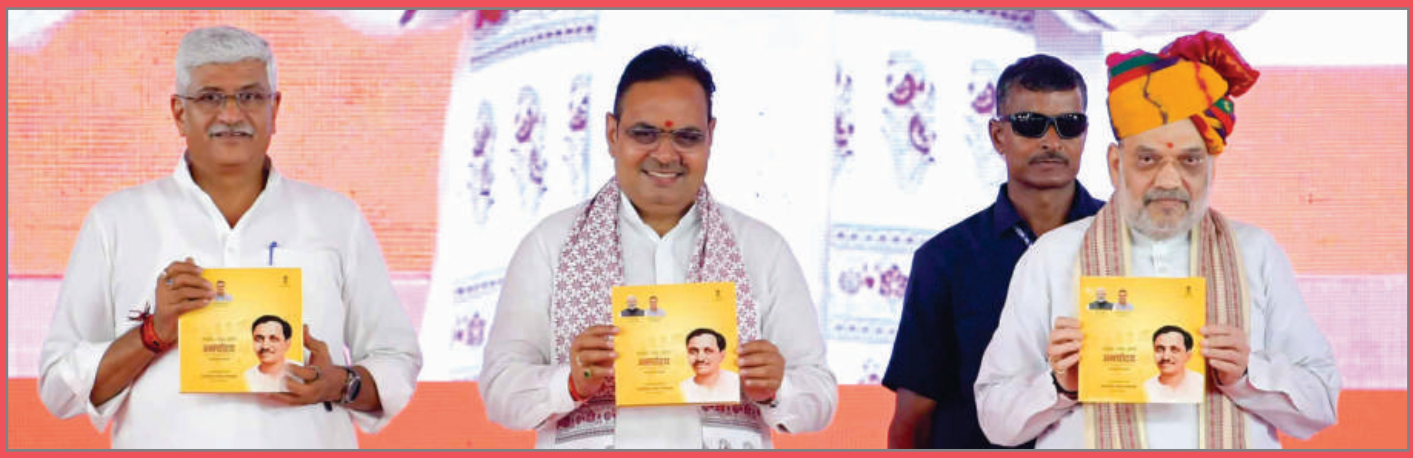

भारत की वैश्विक पहचान : चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

श्री अमित शाह ने भारत की आर्थिक प्रगति को रेखांकित करते हुए बताया कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 60 करोड़ से अधिक नागरिकों को घर, शौचालय, बिजली, गैस, मुफ्त इलाज और 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला है। 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं का राजस्थान में बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है।

सहकारिता के नवाचार : हर गांव तक पहुंच

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने इस क्षेत्र को नया आयाम दिया है। श्री शाह ने बताया कि आज देश में 8.5 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं, जिनसे 31 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। इनमें 98 प्रतिशत संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं। सहकारिता के माध्यम से देश में 20 प्रतिशत गेहूं व धान की खरीद, 35 प्रतिशत उर्वरक और 30 प्रतिशत चीनी का उत्पादन और 20 प्रतिशत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन हो रहा है।

राजस्थान बना सहकारिता का अग्रणी राज्य

राजस्थान सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में नवाचारों को अपनाया है। पिछले चार वर्षों में 61 नवाचार किए गए हैं। दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के गठन का लक्ष्य रखा गया, जिनमें से 40 हजार समितियों का गठन हो चुका है। राजस्थान अब सहकारिता क्षेत्र में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो चुका है।

जल्द लागू होगा नया को-ऑपरेटिव कोड

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही नया को-ऑपरेटिव कोड लागू करने जा रही है। राज्य में इस समय 41,000 से अधिक सहकारी समितियां सक्रिय हैं, जिनसे 1.10 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। अब तक 976 नए एम-पैक्स बनाए गए हैं और आगामी दो वर्षों में शेष सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा।

रोजगार के नए द्वार : 2 लाख से अधिक भर्तियाँ प्रक्रियाधीन

राज्य सरकार अब तक 75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्त कर चुकी है। साथ ही 28,000 पदों पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिससे प्रदेश के युवाओं को व्यापक अवसर मिल रहे हैं।

गरीबी मुक्त गांव : अंत्योदय का संकल्प

राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन कर लाखों जरूरतमंदों को राहत दी है। इसके साथ ही 'गरीबी मुक्त गांव योजना' के तहत 10,000 गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में 5,000 गांवों में सर्वे और आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेष 5,000 गांवों में कार्य प्रगति पर है।

किसान कल्याण और महिला सशक्तीकरण

राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया है, जिसे चरणबद्ध रूप से 12,000 रुपये तक किया जाएगा। अब तक 76 लाख किसानों को 6,800 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की जा चुकी है। साथ ही, दिन के समय बिजली की उपलब्धता और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करने के प्रयास जारी हैं। महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं।

लोकार्पण और लाभ वितरण : योजनाओं का धरातलीकरण

कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह ने विश्व की वृहत अन्न भंडारण योजना के तहत बने 24 गोदामों और 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण किया। साथ ही श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। इसके अलावा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 2,346 माइक्रो एटीएम दिए गए और 8,000 से अधिक युवाओं को रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपे गए। साथ ही, 100 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और सहकारिता विभाग की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया।

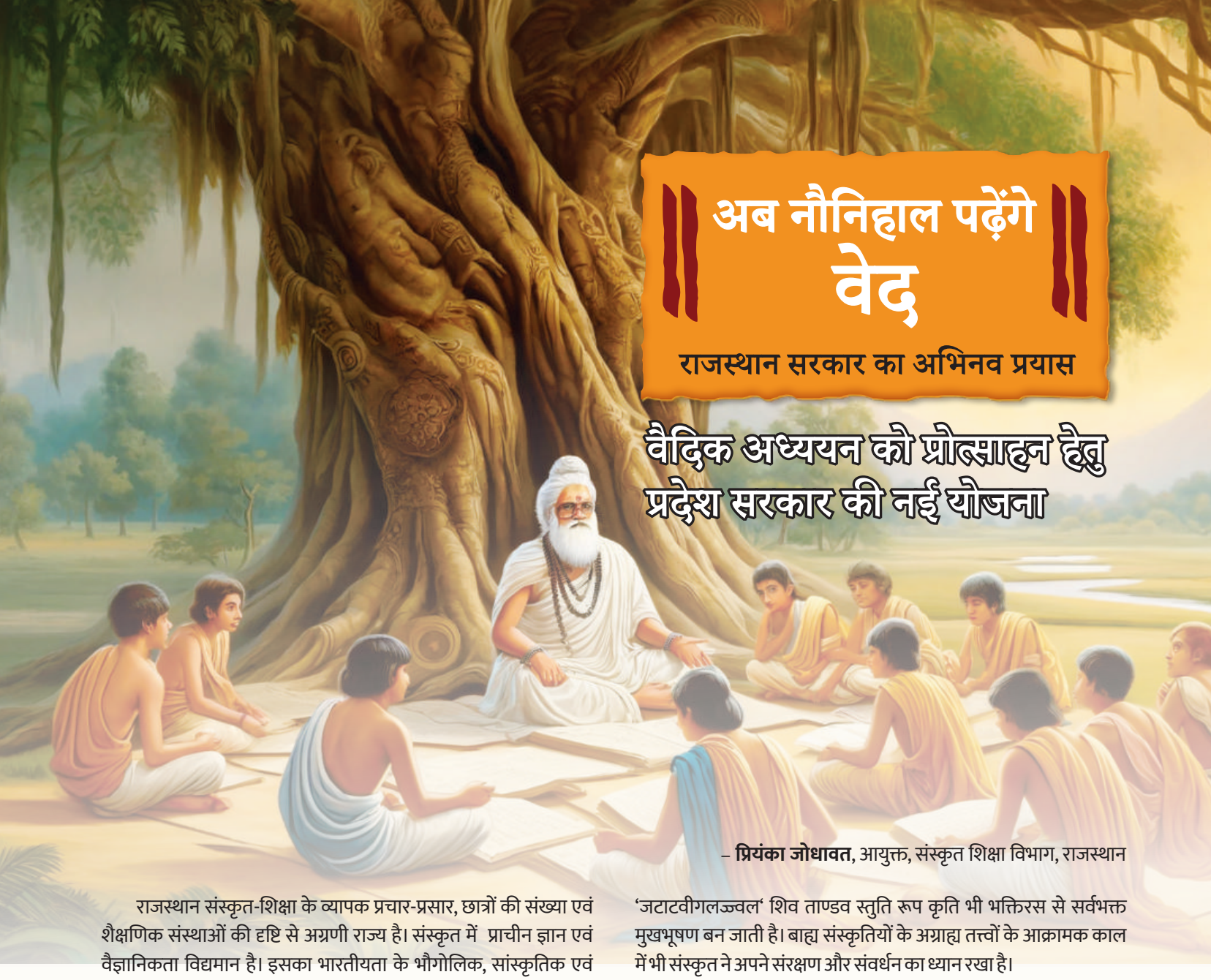

अब नौनिहाल पढ़ेंगे वेद

राजस्थान सरकार का अभिनव प्रयास

वैदिक अध्ययन को प्रोत्साहन हेतु प्रदेश सरकार की नई योजना

– **प्रियंका जोधावत**, आयुक्त, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान

राजस्थान संस्कृत-शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार, छात्रों की संख्या एवं शैक्षणिक संस्थाओं की दृष्टि से अग्रणी राज्य है। संस्कृत में प्राचीन ज्ञान एवं वैज्ञानिकता विद्यमान है। इसका भारतीयता के भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कारकों से सीधा संबंध है। प्राचीन सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र होने से राजस्थान को संस्कृत की वैदिक धारा के स्नातक ऋषिजनों की मूलभूमि होने का गौरव प्राप्त है। मरूभूमि के विद्वानों ने वेदों की विभिन्न शाखाओं को कंठस्थ कर आज तक जीवित रखने का स्तुत्य कार्य किया है। लौकिक संस्कृत की धारा के प्रवाह को निरन्तर रखने में यहां के आचार्यों, ऋषियों और शासकों ने अपना सर्वस्व समर्पित करके प्राथमिकता से इसके मूल स्वरूप की रक्षा की है। संस्कृत प्रत्येक भाषा के साथ मित्र की तरह व्यवहार करती है। यह अन्य भाषाओं के लिए मां के समान सदा पोषक का काम करती है। यह अनेक भारतीय भाषाओं की जननी और द्रविड़ भाषाओं की पोषिणी है। संस्कृत क्षेत्र विशेष या लिपि विशेष का आग्रह भी नहीं रखती है। प्राकृत, वैदिक एवं लौकिक आदि विभिन्न स्वरूपों को अपने में समाहित करने के कारण संस्कृत की शब्द संपदा आज भी सार्वजनिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक होने का सामर्थ्य रखती है। यह सर्वप्राचीन, सर्वशास्त्रमयी, सर्वविषयक है और संगीतात्मक होने से सर्वहृदयस्पर्शी भी है। संस्कृत की सर्वग्राह्यता का प्रमाण है कि जहां तुलसीकृत रामचरितमानस के अनुसार श्रीराम द्वारा 'शम्भूस्तुति' नामक स्तोत्र से शिव की महिमा का बखान किया गया है, वहीं दशानन की 'जटाटवीगलज्ज्वल' शिव ताण्डव स्तुति रूप कृति भी भक्तिरस से सर्वभक्त मुखभूषण बन जाती है। बाह्य संस्कृतियों के अग्राह्य तत्त्वों के आक्रामक काल में भी संस्कृत ने अपने संरक्षण और संवर्धन का ध्यान रखा है।

एकीकरण के समय राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न रियासतों में चल रहे संस्कृत के प्रकल्पों की एक व्यवस्थित संरचना पारंपरिक संस्कृत शिक्षा के लिए तैयार की गई, जो शिक्षा विभाग के समानान्तर "संस्कृत शिक्षा विभाग" के रूप में निरंतर वृद्धिशील है। राजस्थान में संचालित संस्कृत शिक्षा विभाग देववाणी के संरक्षण एवं संवर्धन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसका वर्तमान में गौरवास्पद परिणाम है कि राजस्थान में अध्ययनोपरान्त अनेक छात्र भारतवर्ष में संस्कृत शिक्षक के रूप में संस्कृत का प्रचार-प्रसार एवं जीविकोपार्जन कर रहे हैं।

संभाग स्तर पर आदर्श वेद विद्यालय

भारतीय ज्ञान परम्परा के अनुरूप आधुनिक शिक्षा को अपने मौलिक स्वरूप से जोड़ने हेतु वेदाध्ययन आवश्यक है। भारतवर्ष में हमारी इस विशिष्ट पैतृक ज्ञान संपदा को संरक्षित और सवंर्धित करने के महती कार्य में अपनी अग्रणी भूमिका के साथ वर्तमान राजस्थान शासन द्वारा वेदों के सर्वसुलभ अध्ययन की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जा रहा है। 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' अर्थात वेद ही सभी धर्मों का मूल है, के ध्येय के साथ राजस्थान सरकार द्वारा

प्रदेश में संस्कृत शिक्षा विशेषतः वैदिक शिक्षा के प्रोत्साहन व विस्तार हेतु संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इन वेद विद्यालयों में आवासीय सुविधा भी रहेगी। राज्य सरकार का यह कदम वैदिक परंपराओं, मूल्यों एवं ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। इन वेद विद्यालयों में पारंपरिक वेदों के ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक विषय भी पढ़ाये जाएंगे।

जयपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा संभागों में वेद विद्यालय प्रारम्भ

राजस्थान राज्य के बजट सत्र 2024-25 में (i) संभाग स्तर पर वेद विद्यालयों के संचालन, (ii) ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन एवं अनुसन्धान हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना एवं बजट सत्र 2025-26 में जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरूकुल एवं वैदिक पर्यटन केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की गई है। वर्ष 2025-26 में जयपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा संभागों में वेद विद्यालय प्रारम्भ हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा के अमूर्त रूप वैदिक अध्ययन प्रक्रिया को राजकीय स्तर पर पुन: प्रारम्भ करने के लिए वेद विद्यालयों की स्थापना की गई है।

इस वर्ष हाथोज (जयपुर), पुष्कर (अजमेर), देवली कलां, चेचट (कोटा) और तारातरा मठ, बाड़मेर (जोधपुर) इन चार वेद विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रतिविद्यालय 40 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमान में शिक्षकों व अन्य कार्मिकों की व्यवस्था संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों से ही की जा रही है। वैदिक विद्वानों को राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के अन्तर्गत रखा जा रहा है। इस वर्ष प्रारम्भिक तौर पर प्रति वेद विद्यालय 16.97 लाख रूपये की विभिन्न मदों में व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

छात्रों की दिनचर्या प्रात: 5:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक

आवासीय वेद विद्यालय की दिनचर्या प्रात: 5:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगी। इस दिनचर्या में सामान्य एवं वैदिक अध्ययन के साथ-साथ संध्या वंदन, हवन आदि का भी शिक्षण कराया जाएगा। रैवासा, सीकर में संचालित आदर्श वेद आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप में वेद विद्यालय स्थापित किए जाने के क्रम में तदनुरूप पाठ्यचर्या रहेगी। कक्षा उपवेशन व्यवस्था तथा गणवेश भी भारतीय-संस्कृति और शिक्षण के पारंपरिक स्वरूप अनुसार प्रस्तावित हैं। विश्वास है कि राज्य सरकार की उदात्त भावना के अनुरूप ये वेद विद्यालय भारतीय संस्कृति के पुनरूत्थान के अग्रदूत वैदिक विद्वानों को तैयार करने में समर्थ होंगे।

संस्कृत शिक्षा की नवीन पुस्तकों का विमोचन

28 जून को आयोजित 29वें राज्यस्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आरटीई के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की फीस पुनर्भरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर की एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि रिमोट का बटन दबाकर खातों में हस्तांतरित की। साथ ही, उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक व संस्कृत शिक्षा की कक्षा 1 से 8 तक की नवीन पुस्तकों, शिविरा ई-बुलेटिन और भामाशाह प्रशस्ति पुस्तिका का विमोचन किया।

शौर्य, प्रेम, वीरता और मेजबानी
हर हवेली की अपनी कहानी

चोखानी डबल हवेली, झुंझुनूं

– **हिमाशुं सिंह**, जन संपर्क अधिकारी

जग प्रसिद्ध हैं शेखावाटी की हवेलियां

कला व संस्कृति के क्षेत्र में शेखावटी क्षेत्र (सीकर, चूरू, झुंझुनूं) पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसी कला और संस्कृति की थाती को यदि एक साथ देखना हो, तो शेखावटी की किसी हवेली को देखना चाहिए। यहां की हवेलियां न केवल वास्तु शिल्प, भित्ति चित्रों समेत सांस्कृतिक धरोहर का अनूठा संगम और संग्रह हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी इनका विशेष महत्व रहा है। इन विशालकाय हवेलियों को देखकर यह सवाल मन में बरबस ही उठता है कि शेखावटी के व्यापारिक घराने और सेठ, जो स्वयं अक्सर 'परदेस' में रहते थे, वे इतनी बड़ी-बड़ी हवेलियां आखिर क्यों बनाते थे? इन हवेलियों का मालिकाना हक रखने वाले सेठ एक दशक में मुश्किल में एक बार आते थे, तो आखिर उनको इतना भारी-भरकम खर्च करने की कहां आवश्यकता थी? इस सवाल पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉ आर. डी. सैनी का कहना है कि शेखावटी के व्यापारिक घराने के लोग यानी सेठ बहुत समझदार और अपनी मिट्टी से जुड़ाव रखने वाले लोग थे और आज भी हैं।

सांवलका हवेली, सीकर

मालजी का कमरा, चूरू

रोजगार सृजन का एक प्रभावी माध्यम

जो व्यक्ति दूसरी जगह (परदेस) में जाकर करोड़ों रूपए का व्यापार कर रहा है, वह यूं ही बिना किसी मकसद के हवेलियां नहीं बनाता था। खासतौर से तब, जब वह 5-10 सालों में कभी-कभार 8-10 दिन के लिए ही यहां रहने आए। इन हवेलियों को बनाने के पीछे कई मकसद होते थे। इनमें से पहला यह है कि वे अपने गांव के, अपने इलाके के लोगों को रोजगार देना चाहते थे। वे यह बात जानते थे कि गांव-कस्बे का हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वह अपना देश छोड़कर व्यापार कर सके। वहीं, खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर थी। वार्षिक वर्षा औसत बहुत कम है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से पैदावार भी कम है। ऐसे में गांव के लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा नहीं हो, इसलिए वे हवेलियां बनाते थे, ताकि इस बहाने आस-पास के लोगों को रोजगार मिलता रहे। एक हवेली को बनने में कई साल लगते थे। मंडावा के कला मर्मज्ञ और होटल व्यवसायी रविकांत मिश्रा बताते हैं कि तब हवेलियों में कौड़ी का फर्श बनाया जाता था, जो कि पूरे दिनभर में एक कारीगर बमुश्किल 25-30 वर्ग सेंटीमीटर ही बना पाता था। तो, अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवेली के पूरे फर्श को तैयार होने में कितना समय लगता था। इसके अलावा चूने को पकाना, पत्थरों की ढलाई, लकड़ी की नक्काशी, चित्रकारी इत्यादि में भी इतना ही समय लगता था।

पोद्दार हवेली, नवलगढ़

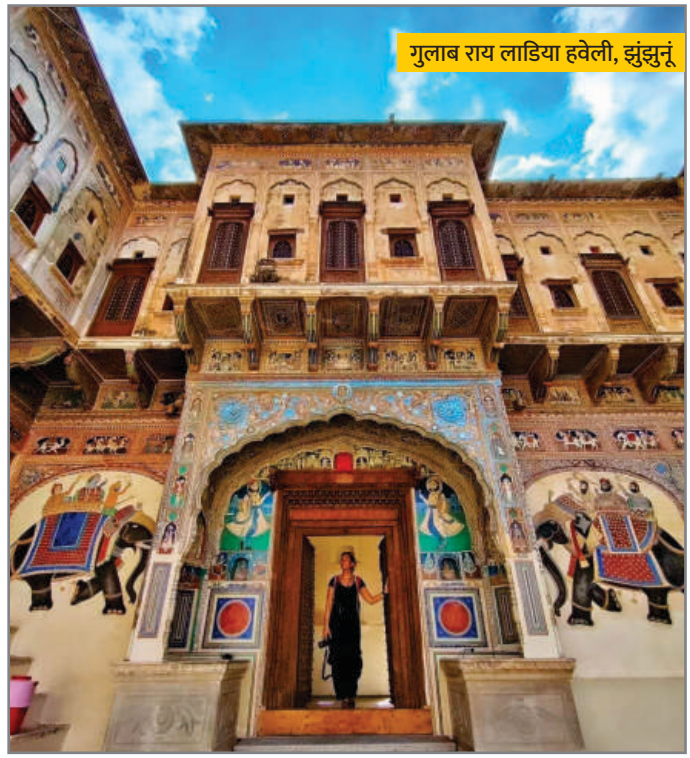
गुलाब राय लाडिया हवेली, झुंझुनूं

मंडावा हवेली, मंडावा

शेखावाटी हवेलियों में भित्ति चित्र परंपरा

शेखावाटी क्षेत्र, विशेषकर मंडावा, भित्ति चित्रकला की अद्भुत विरासत के लिए विश्वप्रसिद्ध है। यहाँ के भित्ति चित्र मुख्यत: 'फ्रेस्को' शैली में बनाए गए हैं, जो गीली दीवारों पर चित्रित होते हैं और धोये नहीं जा सकते। ये चित्र प्रायः हवेलियों, छतरियों और मंदिरों की दीवारों, छतों व आलों पर अंकित हैं। इनका विषय धार्मिक, सामाजिक, लोकजीवन, रास-लीला, इतिहास, पौराणिक कथाएँ तथा आधुनिक जीवन के चित्रों से जुड़ा होता है। शेखावाटी के धनपतियों, ठाकुरों और शासकों ने इन चित्रों को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया, जिससे कला, समाज और संस्कृति का विलक्षण संगम इन चित्रों में देखने को मिलता है। रंग संयोजन, रेखाओं की गति, शारीरिक गठन और विषयवस्तु की विविधता इन्हें विशिष्ट बनाती है। मंडावा की हवेलियाँ जैसे गोयन्का, लाडिया, बागड़ोदिया आदि भित्तिचित्र कला की अनमोल धरोहर हैं। गोयन्का हवेली के पार्श्व भाग और लाडिया हवेली के सोने की बर्क वाले चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन चित्रों को बनाने वाले प्रमुख कलाकार लक्ष्मणगढ़ व नवलगढ़ के कुम्हार और चेजारा रहे, जिनमें बालूराम चेजारा और जयदेव का योगदान अत्यंत सराहनीय है। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक देवेंद्र चौधरी बताते हैं कि शेखावाटी की हवेलियों की नक्काशी कार्य केवल सजावट नहीं, बल्कि उस युग की कला, संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता के मिलन का जीवंत दस्तावेज है। यह स्थापत्य और चित्रकला का अद्वितीय संगम है, जिसे संरक्षित करना हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना है।

मुख्यमंत्री ने दिए शेखावाटी की सभी 662 हेरिटेज हवेलियों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सीकर, झुंझनूं और चूरू जिले में स्थित शेखावाटी की हेरिटेज हवेलियों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। श्री शर्मा कहते हैं कि ये बहुत ही दुर्लभ हवेलियां हैं, जिनके संरक्षण के लिए अधिनियम भी लाने की आवश्यता हुई तो लाया जायेगा। पर्यटन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना और हमारी अनमोल विरासत का संरक्षण करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य की सभी हेरिटेज धरोहरों का सर्वे कर उनका विकास करवाने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग को शेखावाटी की सभी 662 हेरिटेज हवेलियों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के संबंध में निर्देश दिए हैं। साथ ही इस बाबत झुंझुनूं, चूरू और सीकर जिला कलेक्टरों को भी निर्देशित करते हुए कहा है सभी जिला कलेक्टर अपने जिले में स्थित हेरिटेज भवनों का संरक्षण करें तथा इसके लिए सीएसआर से भी सहयोग ले सकते हैं।

शेखावाटी की हेरिटेज हवेलियों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार हमारी प्राथमिकता

– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

प्रतिष्ठा की प्रतीक थीं हवेलियां

शेखावाटी में हवेलियों का निर्माण केवल आर्थिक या कार्यात्मक उद्देश्य से नहीं होता था, बल्कि यह सेठों की सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान और पहचान की प्रतीक भी थीं। जो व्यापारी परदेस में व्यापार कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करता था, वह अपने गांव में भव्य हवेली बनवाकर यह दर्शाना चाहता था कि वह न केवल आर्थिक रूप से सक्षम है, बल्कि अपनी जड़ों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रतिष्ठा के इस भाव ने शेखावाटी में स्थापत्य और चित्रकला को एक नई ऊंचाई दी, क्योंकि हर सेठ चाहता था कि उसकी हवेली न केवल सबसे सुंदर हो, बल्कि सबसे अलग दिखे भी। इससे शिल्पकारों, चित्रकारों और दस्तकारों को निरंतर काम और संरक्षण मिला, जिससे एक संपूर्ण लोक-कला संस्कृति विकसित हुई। इस तरह हवेलियां न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा की अभिव्यक्ति बनीं, बल्कि वे एक सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बन गईं, जिसने शेखावाटी को आज भी दुनिया भर में विशिष्ट पहचान दिला रखी है।

लक्ष्मीनारायण लाडिया हवेली, झुंझुनूं

सामाजिक उपयोग और सांस्कृतिक संरक्षण

शेखावाटी में हवेलियों के निर्माण का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य यह भी था कि उस समय आज की तरह मैरिज गार्डन या सामुदायिक भवन नहीं होते थे, इसलिए विवाह, त्योहार, और अन्य पारिवारिक समारोहों के लिए विशाल हवेलियां ही प्रमुख स्थल होती थीं। इन हवेलियों को इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि सैकड़ों मेहमानों के ठहरने, खाने-पीने और आयोजन की पूरी व्यवस्था सहज रूप से हो सके। हवेली न केवल एक परिवार का आवास होती थीं, बल्कि वह सामाजिक समागम और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनती थीं। इसके साथ ही हवेली की दीवारों पर बनाए गए भित्ति चित्रों से न केवल सौंदर्य और धार्मिकता झलकती थी, बल्कि ये चित्र कलाकारों के लिए आजीविका का साधन भी थे। इतिहासकार डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव के अनुसार, इन चित्रों के माध्यम से उस समय के चित्रकारों और कारीगरों को आर्थिक संरक्षण और सामाजिक पहचान प्राप्त होती थी, जिससे शेखावाटी में एक समृद्ध लोककला परंपरा विकसित हुई।

मोहनलाल सराफ हवेली, झुंझुनूं

हर हवेली की अलग कहानी

शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों की एक अलग सांस्कृतिक और कलात्मक पहचान है। झुंझुनूं के महनसर में स्थित 'पोहारों की हवेली' में एक कमरे में स्वर्णाक्षरों में संपूर्ण रामायण का अंकन किया गया है। पिलानी में 'राज बलदेवदाम बिड़ला की हवेली' में अब बिड़ला म्यूजियम भी संचालित है। यह भी अपनी उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। 'ईसरदास' मोदी की हवेली में 360 खिड़कियां हैं। यहां श्रीकृष्ण की लीलाओं के भित्तिचित्र अंकित हैं। नवलगढ़ की 'मानसिंह की हवेली' में शीशम की चौखटों पर बारीक कलात्मक कार्य और भित्तिचित्रों में घोड़े, ऊंट, हाथी, राजा की सवारी के मनमोहक चित्र हैं। सीकर के फतेहपुर में 'महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली' में सोने के पानी के इस्तेमाल से की गई चित्रकारी युक्त भव्य रंग महल आकर्षण का केंद्र है। चूरू में 'सेठ कन्हैयालाल बागला' की हवेली में ढोला-मरवण का ऊंटों पर पीछा करते हुए अमर सूमरा आकर्षक ढंग से दर्शाए गए हैं। मंडावा, रामगढ़, बिसाऊ, डूंडलोद आदि में दर्जनों हवेलियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।

मंडावा हवेली, मंडावा

चौखानी हवेली, झुंझुनूं

राधिका हवेली, झुंझुनूं

हवेलियों का संरक्षण और पर्यटन

शेखावाटी क्षेत्र की अधिकांश हवेलियां आज से लगभग 100 साल पहले बनाई गई थीं और समय के साथ इनका अस्तित्व खतरे में आ गया है। इन ऐतिहासिक हवेलियों को देखभाल, पुनर्निर्माण और संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि यह सांस्कृतिक धरोहर भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। हालांकि, समय के साथ इन हवेलियों के मालिकाना हक में जटिलताएं आई हैं, लेकिन कुछ संवेदनशील और जागरूक मालिकों ने इन्हें संरक्षित किया है। आज कई हवेलियां हेरिटेज होटल, आर्ट गैलरी, म्यूजियम, कला केंद्र, होमस्टे, और ग्रामीण गेस्ट हाउस के रूप में बदल चुकी हैं, जो न केवल इन ऐतिहासिक संरचनाओं को बचाए रखती हैं, बल्कि पर्यटन के माध्यम से आर्थिक योगदान भी देती हैं। इन हवेलियों से देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है और इससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिल रहा है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना का ऐलान किया है, जो इन ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा। इस योजना से न केवल इन हवेलियों की संरचनाओं को बचाया जाएगा, बल्कि शेखावाटी क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन उद्योग को भी मजबूती मिलेगी।

जन-मन में प्राण फूंकती 'वागड़ गंगा' माही

– **डॉ. कमलेश शर्मा**, अतिरिक्त निदेशक

देश, दुनिया में 'मरुभूमि' के रूप में ख्यातनाम रहा राजस्थान, जहां अपने शौर्य एवं स्वाभिमान से युक्त गौरवशाली इतिहास, शिल्प वैशिष्ट्य व सांस्कृतिक विविधता को अपने आंचल में समेटे हुए है, वहीं यहां के दक्षिण अंचल में स्थित वागड़ क्षेत्र आदिम संस्कृति के साथ-साथ सघन हरीतिमा और शताधिक आइलैंड्स की विशिष्टता को लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है।

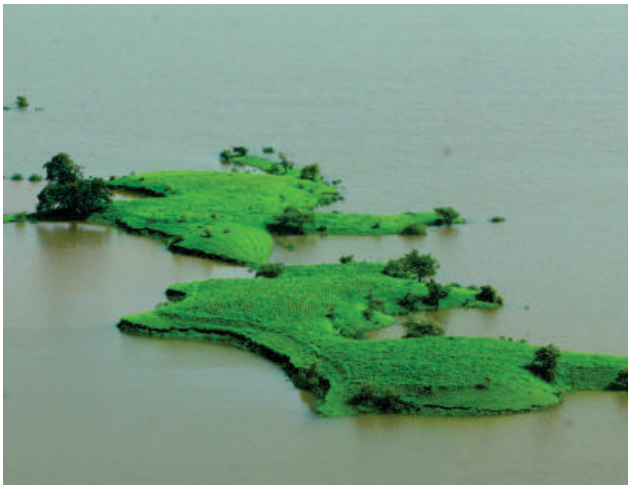

आदिम संस्कृति वाले दक्षिण राजस्थान की प्रज्ञा उर्वरा वागड़ भूमि को शस्य श्यामल और समृद्धि से सन्तृप्त बनाने का एकमात्र श्रेय जाता है 'वागड़ गंगा माही' को। मध्यप्रदेश के अमरकंटक पर्वत से आविर्भूत होकर यह सदानीरा अपनी नहरों रूपी धमनियों से बांसवाड़ा जिले के एक बड़े क्षेत्र तक जलामृत का संचार करती है और जन-मन में प्राण फूंकने वाली 'माही' की हरेक बूंद इस अंचल के रहवासियों में रक्त बनकर इसकी जयगाथा को बखानती प्रतीत होती है। इस अंचल के जन-जन के चेहरे का तेज, दिल की धड़कन, मन का उल्लास और बाजुओं का दमखम सिर्फ और सिर्फ माही की ही देन है। इस अंचल के हर गांव-ढाणी के हर एक व्यक्ति के चेहरे पर यदि संतुष्टि भरी मुस्कान के बीच विकास और उल्लास की स्मित आभा दिखाई देती है, तो उसके पीछे माही मैया का वात्सल्य है।

65 वर्ष पहले हुआ था शिलान्यास

इस परियोजना का शिलान्यास वर्ष 1960 में किया गया था, परंतु परियोजना का प्रारंभिक निर्माण कार्य योजना आयोग द्वारा नवम्बर, 1971 में रुपये 31.36 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में स्वीकृत योजना से सिंचाई सुविधा 44,170 हेक्टेयर भूमि में देने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 1974-75 में 80,000 हेक्टेयर किया गया था एवं 140 मेगावाट विद्युत क्षमता के दो विद्युत गृहों के निर्माण का प्रावधान रखा गया। पुन: वर्ष 1984-85 में कमाण्ड क्षेत्र को 80,000 हेक्टेयर से विस्तारित कर 1,23,500 हेक्टेयर करते हुए इसमें बांसवाड़ा जिले की आनन्दपुरी, भूंगड़ा, जगपुरा एवं डूंगरपुर जिले की माही सागवाड़ा नहर को सम्मिलित किया गया, परन्तु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मई, 2002 में 80,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिए स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें माही सागवाड़ा नहर के 0 से 8 किमी. तक के भाग एवं निठाउवा वितरिका को सम्मिलित किया गया।

माही परियोजना का निर्माण तीन इकाइयों में किया गया था। प्रथम इकाई के अन्तर्गत 435 मीटर लम्बे एवं अधिकतम 74.5 मीटर ऊंचे चुनाई वाले एवं कंकरीट बांध का निर्माण किया गया है एवं दायें तथा बायें किनारों पर 2,674 मीटर लम्बे मिट्टी के बांध का निर्माण किया गया है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 43 मीटर है। द्वितीय इकाई में नहरों एवं वितरण प्रणाली के तहत मुख्य बांध की परिधि पर स्थित विद्युत गृह-प्रथम द्वारा सिंचाई हेतु जल कागदी पिकअप वियर से निकलने वाली दाईं व बाईं मुख्य नहर तक पहुंचाने से संबन्धित निर्माण हुआ। दाईं मुख्य नहर एवं इसकी वितरण शाखा नहरें क्रमश: 71.72 किमी. एवं 977.50 किमी. लम्बी हैं वहीं दाईं मुख्य नहर एवं इसकी वितरण शाखा नहरों की लम्बाई क्रमश: 36.12 किमी. एवं 1028 किमी. हैं। बांध के कुल 77 टी.एम.सी. पानी में से 64 टी.एम.सी. पानी का उपभोग सामान्यत: सिंचाई के लिए किया जा रहा है और इससे ही दोनों जिलों के खेतों की प्यास बुझा रिकार्ड अन्न उत्पादन हो रहा है।

पौराणिक संदर्भों में भी पुण्यदायी 'मैया माही'

माही नदी का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। 'स्कन्द पुराण' के 'कुमारिका खण्ड' में इस बात का उल्लेख है कि इन्द्रद्युम्न नामक राजा द्वारा विंध्याचल के अमरकंटक पर्वत श्रेणी स्थान पर किए गए यज्ञ की अग्नि से तप्त धरा से निस्सृत जलधारा ही माही नदी है। इस तरह विंध्याचल के अमरकंटक पर्वत श्रेणी से 'आमझरा' नामक स्थान से माही नदी का उद्गम माना जाता है और यह नदी विंध्याचल से 120 किलोमीटर बहने के बाद बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है तथा डूंगरपुर होकर गुजरात में बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। पौराणिक संदर्भों में बताया गया है कि इस नदी के जल में स्नान करने से पुण्यार्जन होता है और यही कारण है कि इसे वागड़ के जाये-जन्मे 'महीसागर' तीर्थ की संज्ञा देते है व इसका स्नान-ध्यान करते हुए इसके प्रति अगाध आस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं।

बांध 'क्षीरसागर', नीर 'अमृत' और नहरें 'धमनियां'

मध्यप्रदेश और प्रतापगढ़ से आती अथाह जलराशि बहकर समुद्र में व्यर्थ ही चली जाती, अगर इस पर माही बांध का निर्माण न हुआ होता। माही बांध इस अंचल के निवासियों के मन में सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के शयन स्थल स्वरूप 'क्षीरसागर' की प्रतिकृति के रूप में स्थान बनाए हुए है। इस बांध में संग्रहित जल की एक-एक बूंद अमृत कण के समान है, जो इस अंचल की भूमि को सिंचित कर जन-मन में प्राण फूंकने का उपक्रम कर रही है। जिस तरह मानव शरीर में 'धमनियां' रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाकर जीवन का संचार करती हैं, उसी तरह माही बांध की नहरें भी यहां के दूरस्थ ग्राम्यांचलों के खेतों तक पानी का संचार कर मानव जीवन का आधार बनी हुई हैं।

प्रदेश का स्वदेशी मशीनों द्वारा निर्मित पहला पन बिजली घर

माही परियोजना के निर्माण की तृतीय इकाई में विद्युत गृह एवं सम्बन्धित कार्य संपादित किए गए। इसके तहत मुख्य बांध की परिधि पर सैडल बांध नंबर-5 पर स्थित सतही विद्युत गृह प्रथम एवं ग्राम लीलवानी के समीप सतही विद्युत गृह द्वितीय का निर्माण किया गया है। इस इकाई के अन्तर्गत विद्युत गृह प्रथम से प्राप्त जल को सिंचाई हेतु कागदी पिकअप वियर तक पहुंचाने के लिए 1462 मीटर लम्बी सुरंग एवं 3090 मीटर लम्बी नहर का निर्माण किया गया है। विद्युत गृह-प्रथम का निर्माण कार्य मई 1978 में प्रारम्भ हुआ था तथा इसकी कुल लागत 68 करोड़ रुपये है। विद्युत गृह-द्वितीय पर 1989 में ऊर्जा उत्पादन आरम्भ हुआ तथा उसकी लागत 120 करोड़ रुपये है। यह राजस्थान का पहला स्वदेशी मशीनों द्वारा निर्मित पन बिजली घर है। पावर हाउस-प्रथम पर 25 मेगावाट की 2 मशीनें हैं, तथा उनकी कुल क्षमता 50 मेगावाट है। पावर हाउस-द्वितीय, बागीदौरा पर 2 मशीनें हैं तथा उनकी कुल क्षमता 90 मेगावाट है। इस प्रकार माही हाइडल प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 140 मेगावाट है। पावर हाउस-प्रथम का राष्ट्र को समर्पण 13 फरवरी 1986 को हुआ था। माही बांध की बदौलत बांसवाड़ा जिला रिकॉर्ड बिजली उत्पादन करने वाला जिला भी बना है और अब तक माही के पानी के उपयोग के माध्यम से जिले के स्थापित दोनों जल विद्युत गृहों से अरबों यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है।

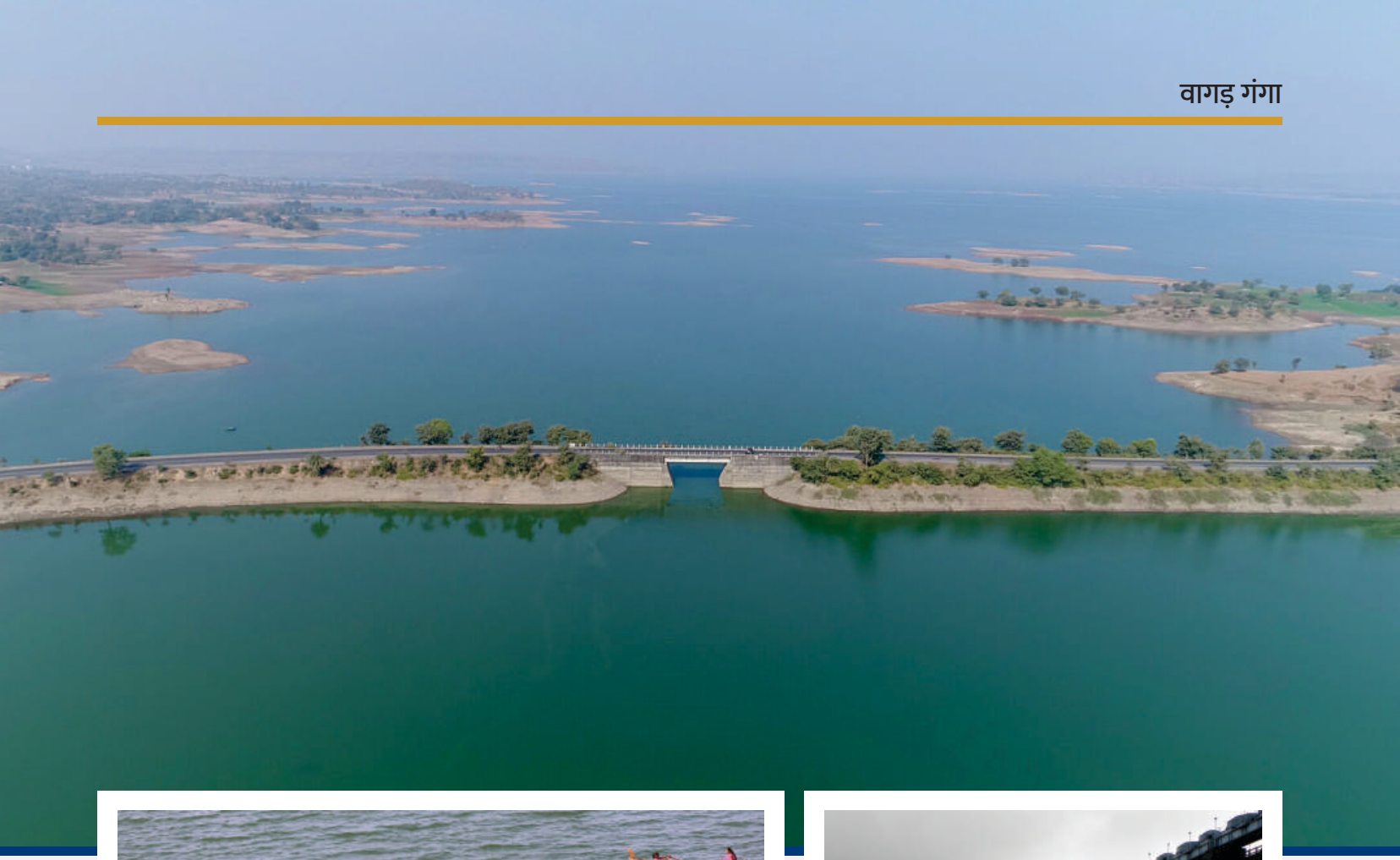

माही बजाज सागर परियोजना

माहीडेम या माही बजाज सागर परियोजना के कारण ही आज वागड़ अंचल सरसब्ज है। स्वाधीनता सेनानी स्व. श्री जमनालाल बजाज की पुण्य स्मृति में इस बांध का नामकरण 'माही बजाज सागर' किया गया। वागड़ अंचल की जीवनरेखा बनी माही बजाज सागर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है और इस परियोजना से सिंचाई हेतु जल प्रवाह का शुभारम्भ 1 नवम्बर, 1983 को किया गया था। माही नदी के जल उपयोग हेतु गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य निष्पादित वर्ष 1966 के अनुबन्ध के अन्तर्गत माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। मुख्य बांध की कुल भराव क्षमता 77 टीएमसी है एवं उपयोगी भराव क्षमता 60.45 टीएमसी है। अनुबंध के अनुसार बांध में संग्रहित उपयोगी जल में से 40 टीएमसी जल गुजरात राज्य एवं 16 टीएमसी जल राजस्थान राज्य के उपयोग हेतु निर्धारित किया गया है। बांध का निर्माण गुजरात व राजस्थान के सहयोग से किया गया है। मुख्य बांध एवं सम्बन्धित निर्माण कार्यों की लागत में अनुबन्ध के अन्तर्गत गुजरात एवं राजस्थान का आर्थिक सहयोग 55:45 प्रतिशत है।

निश्चय ही माही मैया इस अंचल की जीवन रेखा के रूप जहां सिंचाई के लिए पर्याप्त जलराशि उपलब्ध करवा रही है, वहीं बिजली उत्पादन के रूप में भी आमजन के जीवन को रोशन करने का उदात्त उपक्रम कर रही है।

आधे सावन में ही
छलके बांध

राजस्थान में सावन माह के प्रारंभ में ही इंद्रदेव की कृपा बरसी और प्रदेश के कई बड़े बांध जुलाई महीने में ही भरकर छलकने लगे। यह नज़ारा सिर्फ जल संचयन की दृष्टि से नहीं, बल्कि राज्य की जल नीति, कृषि समृद्धि और भावी जल संरक्षण योजनाओं के लिए भी अत्यंत शुभ संकेत है।

Post

Reply

Bhajanlal Sharma
@BhajanlalBjp

प्रकृति की कृपा, प्रदेश में खुशहाली की वर्षा

श्री गिरिराज जी महाराज की अनुपम कृपा से पवित्र सावन महीने में बीसलपुर बाँध का पूर्ण रूप से भरना अत्यंत हर्ष का विषय है। यह पहली बार है जब जुलाई माह में पूर्ण विधि-विधान के साथ बीसलपुर बाँध का गेट खोला गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'वंदे गंगा: जल संरक्षण-जन अभियान' के सुखद परिणामों से प्रदेशभर में जल की प्रचुरता हमारे किसान भाइयों, पशुपालकों एवं आमजन के जीवन में नवचेतना, समृद्धि और संभावनाओं की नई राह प्रशस्त करेगी।

#VandeGanga
#आपणो_अग्रणी_राजस्थान

नवनेरा बैराज

राणा प्रताप सागर

बीसलपुर बांध

राजधानी जयपुर सहित कई जिलों को जीवनदायिनी जल देने वाला बीसलपुर बांध जुलाई के अंतिम सप्ताह में ओवरफ्लो हो गया। इस वर्ष समय से पहले ही इसका जलस्तर पूरी क्षमता तक पहुंच गया, जिससे लोगों को आश्वस्ति और राहत दोनों मिली।

नवनेरा बैराज

राम जल सेतु लिंक परियोजना (ईआरसीपी) से जुड़ा यह महत्वपूर्ण बैराज भी जुलाई माह में छलकने लगा। इससे झालावाड़, बारां और कोटा क्षेत्र में सिंचाई और जलापूर्ति की व्यापक संभावनाएं फिर से जागृत हुई हैं।

गुढ़ा बांध

बूंदी जिले में स्थित यह बांध भी वर्षा से पूरी तरह भर चुका है। इसकी जलधारा अब ओवरफ्लो होकर खेतों और प्राकृतिक स्रोतों में समाहित हो रही है, जिससे पूरे इलाके में जल संतुलन स्थापित हो रहा है।

पांचना बांध

करौली जिले की खूबसूरत वादियों में बसा पांचना बांध जिले के सबसे महत्वपूर्ण मीठे पानी के स्त्रोतों में से एक है। मानसून के शुरूआती दौर में ही इस बार मेघों की मेहरबानी से यह बांध लबालब हो चुका है।

राणा प्रताप सागर बांध

राणा प्रताप सागर बांध, चम्बल नदी पर बने चार प्रमुख बांधों की श्रृंखला का दूसरा वृहद बांध है। इस मानसून बांध के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते गेट खोल दिए गए हैं।

गुढ़ा बांध

पांचना बांध

अक्षय ऊर्जा का नव सूर्योदय

राजस्थान फिर सिरमौर

– **सविता सिंह**, सहायक जन संपर्क अधिकारी

राजस्थान अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने में देशभर में अग्रणी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम है कि अक्षय ऊर्जा में राजस्थान ने देशभर में एक बार फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस वर्ष जून माह की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 37,818 मेगावाट हो गई है, जबकि 37,494 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर है। इससे पहले मई माह में राजस्थान (35,400 मेगावाट) के मुकाबले गुजरात की स्थापित क्षमता बढ़कर 35,900 मेगावाट हो गई थी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2030 तक देश में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में उन्होंने कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने तथा वर्ष 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन तक ले जाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में प्रदेश का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।

नीतिगत बदलाव से बदला परिदृश्य

राज्य सरकार ने "एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024" लागू की है, जिससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। इस नीति में वर्ष-2030 तक राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसे मूर्त रूप देने के लिए 10 हजार मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज, बैटरी ऊर्जा भंडारण तथा हाइब्रिड जैसी नवोन्मेषी ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन देने के साथ ही अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, बायोमास, ग्रीन हाइड्रोजन एवं बैटरी स्टोरेज को "रिप्स- 2024" के अंतर्गत विभिन्न लाभ दिये गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोलर परियोजनाओं की भूमि आवंटन की बाधाओं को दूर करने सहित कई अन्य पहल की हैं। जिसका परिणाम है कि वर्तमान राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में प्रदेश में करीब 10, 775 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई है।

बैटरी एनर्जी स्टोरेज में न्यूनतम टैरिफ

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने में राजस्थान देशभर में अग्रणी प्रदेश है। ऊर्जा भंडारण की प्रदेश को आवंटित करीब 2 हजार मेगावाट आवर क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया क्रियान्वित की गई, जिसमें राजस्थान को देश में सर्वाधिक न्यूनतम टैरिफ प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश को वायबलिटी गैप फंडिंग के तहत 4 हजार मेगावाट आवर अतिरिक्त बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता प्रदान की है। मार्च 2027 तक प्रदेश में यह परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। ग्रिड स्थिरता तथा प्रदेश की पीक डिमांड को पूरा करने की दिशा में इसे एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य में तीन स्थानों पर कुल 4,760 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं।

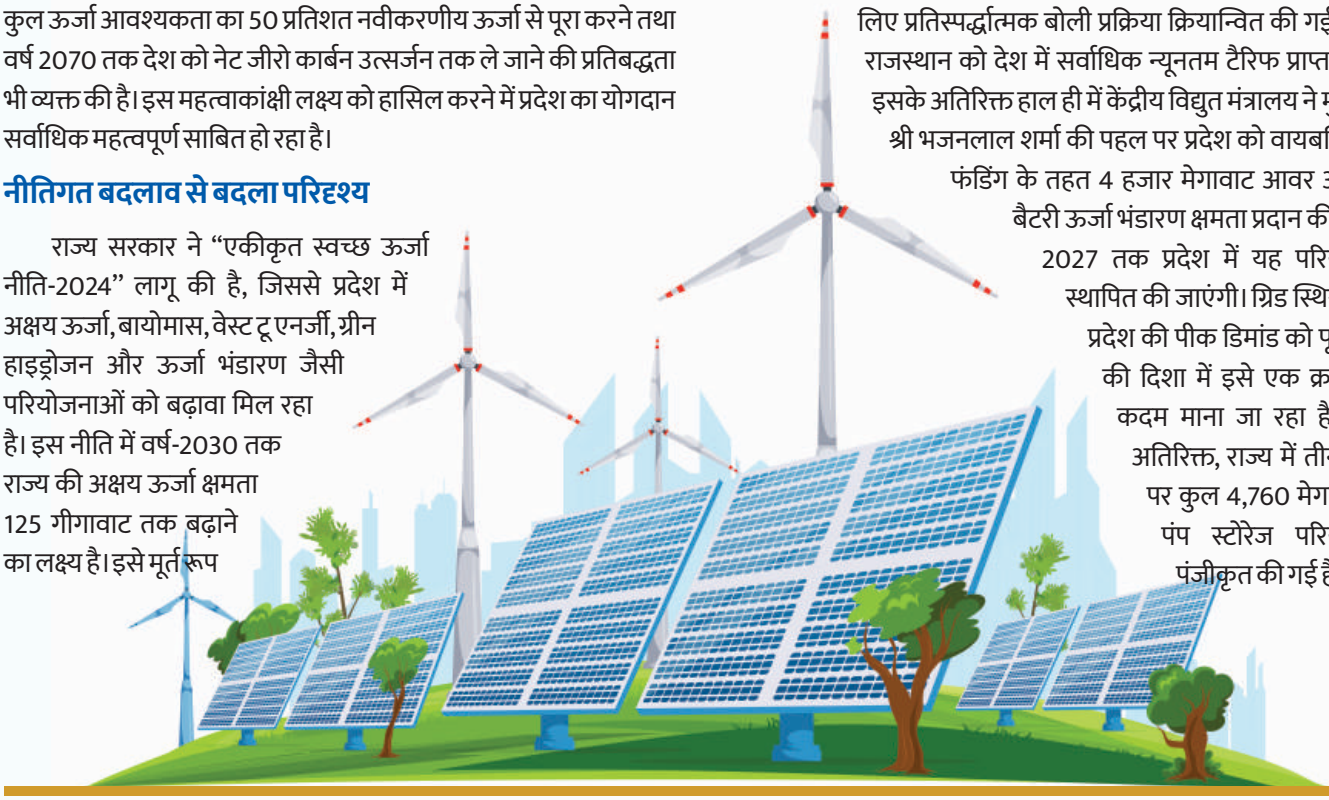

कुसुम कम्पोनेंट-ए में प्रथम एवं कम्पोनेंट-सी में तीसरा स्थान

राज्य में कुसुम योजना में जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट काम हो रहा है। लगभग 1,305 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि क्षेत्र को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रही है। कुसुम कम्पोनेंट-ए में राजस्थान देश में पहले पायदान पर है। कुल 457 मेगावाट क्षमता के प्लांट अकेले राजस्थान में हैं। वहीं कम्पोनेंट-सी में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान तीसरे स्थान पर है। इस योजना में विगत एक साल में जिस गति से प्रदेश आगे बढ़ा है, उसे देखते हुए और सुधार आने की उम्मीद है।

कंपोनेंट-ए के अन्तर्गत 354 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं कम्पोनेंट-सी में 848 मेगावाट क्षमता के 330 सौर संयंत्र लग चुके हैं। राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कम्पोनेंट-ए में वित्त वर्ष 2024-25 में 397 मेगावाट तथा वर्ष 2025-26 में 5 हजार मेगावाट क्षमता का आवंटन बढ़ाया है। वहीं कम्पोनेंट-सी में दोनों वर्षों में कुल 2 लाख सोलर पंप क्षमता का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत अब तक राजस्थान को कम्पोनेंट-ए में कुल 5,500 मेगावाट तथा कम्पोनेंट-सी में 4 लाख सोलर पंप के लक्ष्य आवंटित किए हैं।

पीएम सूर्यघर में देश के शीर्ष पांच राज्यों में शुमार

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में राज्य में 262 मेगावाट क्षमता के 61,372 रूफ टॉप सोलर स्थापित हो चुके हैं। इस संख्या के साथ राजस्थान देश के प्रथम-5 राज्यों में है। योजना लागू होने के करीब सवा साल के भीतर ही राज्य ने यह प्रगति हासिल की है। राजस्थान में तीनों डिस्कॉम्स में अब तक कुल 61 हजार 372 घरों में रूफ टॉप सोलर लगाए जा चुके हैं। इस योजना में केन्द्र सरकार घर की छत पर अधिकतम 3 किलोवाट तक क्षमता का संयंत्र स्थापित करने पर उपभोक्ता को 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी देती है। गुजरात 3,54,797, महाराष्ट्र 2,05,997, उत्तर प्रदेश 1,35,071 तथा केरल 1,03,347 के बाद राजस्थान का स्थान देश में पांचवां है। रूफ टॉप सोलर की स्थापना को सुगम एवं आसान बनाने के लिए डिस्कॉम्स द्वारा एसओपी जारी की गई एवं विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप राजस्थान में इस कार्य को गति मिली और मार्च माह में प्रदेश 7वें स्थान पर था, जो अब 5 वें स्थान पर आ गया है।

ऊर्जा सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सोलर पार्क भड़ला फेज-1, भड़ला फेज-2 एवं नोख में अब तक कुल 1435 मेगावाट क्षमता विकसित की गई है। निगम को भारत सरकार द्वारा बीकानेर के पूगल में 2245 मेगावाट क्षमता के 3 सोलर पार्कों का आवंटन किया गया है, जिनका कार्य प्रगतिरत है। राज्य सरकार द्वारा 14,834 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को 34,050 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। विभिन्न कंपनियों द्वारा पवन व हाइब्रिड परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 2,831 मेगावॉट की परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 3 सार्वजनिक तथा 5 निजी कंपनियों को कुल 10,000 मेगावाट परियोजनाएं विकसित करने हेतु भूमि आवंटन किया गया है। हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर प्रदेश में सरकारी कार्यालय भवनों पर 1020 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं।

सर्वाधिक निवेश का सेक्टर

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसमें भी 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक तो अकेले ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हैं। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत 66.40 गीगावाट क्षमता की पवन तथा हाइब्रिड परियोजनाओं की स्थापना के लिए लगभग 4.23 लाख करोड़ रुपए के निवेश के 31 एमओयू हुए हैं। इनमें से 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 26 हजार 970 मेगावाट के 14 एमओयू की परियोजनाओं का पंजीकरण हो चुका है तथा 12 एमओयू के तहत कार्य की शुरूआत हो चुकी है।

नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ रहा राजस्थान पूरे देश के लिए इस क्षेत्र में सफलता का एक उदाहरण बनता जा रहा है। राज्य सरकार के सकारात्मक प्रयासों से अब यह मरुप्रदेश अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कभी प्रदेश के विकास प्रतिमानों को पीछे खींचने के लिए जिम्मेदार माना जाने वाला थार का मरुस्थल अब हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है, जहां सूर्य की किरणें सर्वाधिक प्रखर हैं। सौर परियोजनाओं के लिए सर्वाधिक आवश्यक लैंड बैंक की उपलब्धता तथा राज्य सरकार के प्रयासों से आज राजस्थान अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन गया है।

किसान संग सरकार
हर खेत समृद्धि का द्वार

मैं स्वयं किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए अन्नदाता की ज़रूरतों और संघर्षों को गहराई से समझता हूँ

– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

प्रदेश की धरती पर मेहनत से लिपटी उम्मीदों को लिए हर सुबह एक किसान सूरज के उगने से पहले उठकर इस आस के साथ कि उसकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी, अपने खेतों में अपना और पूरे परिवार का भविष्य बोता है। खुद किसान परिवार में जन्म लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी इसी मिट्टी से जुड़कर अन्नदाता की हर धड़कन को जिया है।

मुख्यमंत्री कहते हैं- 'मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए मैं किसानों की तकलीफों को समझता हूं।' यही संवेदना और किसान की तकलीफों के समाधान की भावना अब शासन का संकल्प बन चुकी है। उनका मानना है कि सरकार का असली उद्देश्य तब पूरा होता है, जब योजनाओं का लाभ उस आखिरी छोर पर खड़े उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके पास अक्सर उम्मीदें तो होती हैं, पर सहारा नहीं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत@2047' के सपने को साकार करने की दिशा में सरकार ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, वह सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर उतर चुकी है। गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता और समाज के हर वंचित वर्ग को सशक्त बनाने का जो बीज बोया गया है, वह अब नीतियों और उनके परिणामों के रूप में फल देने लगा है। किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और ग्रामीण खुशहाली को केंद्र में रखते हुए राजस्थान सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिन्होंने खेतों की हरियाली के साथ-साथ किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी लौटाई है।

– ईशा सैनी, सहायक जन संपर्क अधिकारी

राजस्थान के खेतों में अब सिर्फ फसलें ही नहीं, 'उम्मीदें' भी लहलहा रही हैं। किसानों की मेहनत को सहारा देने के लिए राज्य सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जो न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी संबल दे रही हैं।

बरसात का पानी, खेत की तिजोरी – फार्म पॉण्ड (खेत तलाई) योजना

राजस्थान की धरती पर पानी की हर बूंद सोने से कम नहीं मानी जाती। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने 'फार्म पॉण्ड (खेत तलाई) योजना' शुरू की है, ताकि किसान बारिश के पानी को संजो सकें और उसका उपयोग सालभर सिंचाई में कर सकें। इस योजना के तहत किसान अपने खेत में खुद की तलाई बनवा सकते हैं, जिसके लिए सरकार आर्थिक सहयोग भी देती है। अगर कोई किसान कच्चा फार्म पॉण्ड बनवाना चाहता है, तो उसे 63,000 रुपए से लेकर

73,500 रुपए तक की सहायता मिलती है। वहीं प्लास्टिक लाइनिंग वाली तलाई के लिए सरकार 1.20 लाख से 1.35 लाख रुपए तक का अनुदान देती है।

यह योजना उन किसानों के लिए खास है, जिनके पास कम से कम 0.3 हेक्टेयर कृषि भूमि हो। आवेदन की प्रक्रिया भी सरल है। किसान ई-मित्र या किसान साथी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खेत में तलाई बनवाकर किसान न सिर्फ आज जल संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं।

खेत को सुरक्षा, तब किसान को सुकून–खेत की तारबंदी योजना

राजस्थान के किसानों की एक बड़ी चिंता है- मेहनत से उगाई गई फसल को आवारा पशुओं और नीलगायों से बचाना। कई बार पूरी की पूरी फसल एक ही रात में तबाह हो जाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने खेत की तारबंदी योजना शुरू की है, जो किसानों को न सिर्फ आर्थिक सहयोग देती है, बल्कि उनकी मेहनत से तैयार की गई फसल के लिए सुरक्षा की दीवार भी बनाती है।

इस योजना के तहत यदि कोई लघु या सीमांत किसान अपने खेत के चारों ओर 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी करता है, तो उसे 60 प्रतिशत तक का अनुदान, यानी 48,000 रुपए तक की मदद मिलती है। अन्य किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रुपए का सहयोग दिया जाता है। यदि 10 या उससे अधिक किसान सामूहिक रूप से मिलकर तारबंदी करना चाहें, तो उन्हें 72,000 रुपए तक की राशि तक 90 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है, बशर्ते वे कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि पर संयुक्त रूप से तारबंदी करें।

तारबंदी न सिर्फ एक सुरक्षा उपाय है, बल्कि यह किसान की मेहनत का पहरेदार है, जो दिन-रात खेत की रक्षा करता है। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें यह भरोसा भी देती है कि अब उनकी भाग्य पर नहीं, बल्कि योजना में जुड़कर खेतों को सुरक्षित करने के उनके पुरुषार्थ पर निर्भर हैं।

बेटियां बढ़ेंगी खेतों की ओर – छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि योजना

राजस्थान सरकार मानती है कि अगर बेटियां भी खेत से जुड़ेंगी, तो खेती को नई दिशा मिलेगी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए शुरू की गई है छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि योजना। इसका उद्देश्य है- कृषि विषय पढ़ रही बेटियों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की मूल निवासी छात्राओं को, जो राज्य मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों या कृषि विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं, कक्षा 11 से लेकर पीएचडी तक 15,000 रुपए से 40,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। कृषि स्नातक, एमएससी (एग्रीकल्चर), पीएचडी और कृषि प्रबंधन जैसे व्यावसायिक कोर्स कर रही छात्राएं इस योजना के दायरे में आती हैं।

यह योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देती है, बल्कि उन परिवारों के लिए भी उम्मीद का संदेश है जो बेटियों को पढ़ाना तो चाहते हैं, पर संसाधन नहीं जुटा पाते। अब खेती का भविष्य बेटियों के हाथों में सुरक्षित है और यही है असली समृद्धि का रास्ता।

जब संकट आए, तो सरकार बने साथी – मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना

किसानी का काम मेहनत के साथ ही कई बार जोखिम भरा भी होता है। खेत में हल चलाते समय या मंडी में अनाज बेचते वक्त, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जो पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल देती हैं। इन्हीं मुश्किल घड़ियों में सरकार एक सच्चे साथी की तरह सामने आती है, माध्यम बनती है- "मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना"

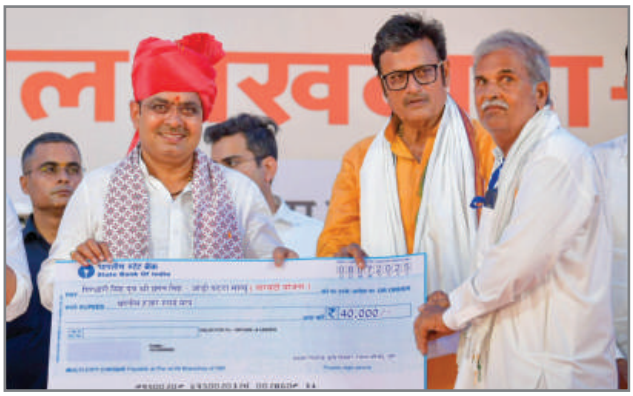

इस योजना के तहत यदि किसी किसान, खेतीहर मजदूर या मंडी में कार्यरत श्रमिक की कृषि या कृषि विपणन कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिजनों को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। वहीं अंगभंग या चोट लगने की स्थिति में 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता शरीर के अंगों की हानि के स्तर के अनुसार तय होती है चाहे आंख की रोशनी चली जाए, हाथ या पैर का नुकसान हो या गंभीर चोट लगे, सरकार इस योजना के जरिए हर स्थिति में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहती है।

इस योजना का आवेदन 'राज किसान साथी पोर्टल' के जरिए किया जाता है और जरूरी चिकित्सा प्रमाणपत्रों के साथ मंडी सचिव स्तर पर स्वीकृति दी जाती है। यह योजना सरकार की उस भावना को दर्शाती है, जिसमें किसान को सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि राज्य का अभिन्न और सम्माननीय अंग माना गया है।

किसान का पेट और मन दोनों भरे – किसान कलेवा योजना

खेती के बाद जब किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचता है, तो एक लंबा और थकाऊ दिन उसका इंतजार कर रहा होता है। धूप हो या सर्दी, जमीन से अन्न उगाने वाला यही अन्नदाता कई बार खाली पेट लिए अपनी फसल बेचने मंडियों में जुटता है। ऐसे ही परिश्रमी किसानों और मंडी में काम करने वाले हम्मालों, तुलादारों और पल्लेदारों के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू की है- 'किसान कलेवा योजना'।

इस योजना के तहत मंडी परिसर में काम करने वाले हर किसान और पंजीकृत श्रमिक को मात्र 5 रुपए में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। भोजन की थाली में 8 गरम चपातियां, दाल, सब्जी, गुड़ और छाछ शामिल होता है। यानी एक ऐसा संतुलित भोजन जो शरीर को ऊर्जा दे और मन को तृप्ति। गर्मियों में जहां छाछ से राहत मिलती है, वहीं सर्दियों में गुड़ शरीर को ताकत देता है।

इस योजना का उद्देश्य सिर्फ भोजन देना नहीं, बल्कि किसानों को यह महसूस कराना है कि सरकार उनके साथ है उनके हर संघर्ष में। मंडी गेट पर प्रवेश पत्र दिखाकर किसान को कूपन मिलता है, जिसके जरिए वह भोजन पा सकता है। यह योजना उस सोच का प्रतीक है जिसमें 'पहले किसान का पेट भरे, तभी देश का पेट भरेगा' और यही सच्ची कृषक कल्याण की भावना है।

सेहत भी, रोजगार भी – औषधीय पौधों की खेती से नई राह

आज जब दुनिया प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौट रही है, राजस्थान सरकार भी किसानों को एक नई दिशा दे रही है- "औषधीय पौधों की खेती योजना" के जरिए। यह सिर्फ खेती नहीं, एक ऐसे बीज का रोपण है जो किसान की आय बढ़ाने के साथ-साथ समाज की सेहत भी सुधारता है।

इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश में औषधीय पौधों जैसे अश्वगंधा, तुलसी, सर्पगंधा, एलोवेरा आदि की खेती को बढ़ावा देना। सरकार इन पौधों की खेती करने वाले किसानों को 30 से 75 प्रतिशत तक अनुदान देती है, ताकि वे कम लागत में लाभकारी खेती कर सकें।

सबसे खास बात यह है कि इस योजना का लाभ कोई भी इच्छुक किसान ले सकता है। आवेदन के लिए बस कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे जमाबंदी की प्रति (6 माह से पुरानी न हो), आधार, जनआधार कार्ड और सिंचाई साधन का प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करवाना होता है।

इस योजना से जुड़कर किसान न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र में कदम रख सकते हैं, जहां बाजार की मांग लगातार बढ़ रही है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रसार के साथ औषधीय खेती का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और राजस्थान के किसान इस बदलाव के अग्रदूत बन सकते हैं।

बैलों से खेती को सम्बल – किसान आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम

राजस्थान की मिट्टी में परंपरा की जड़ें आज भी गहराई तक बसी हुई हैं। एक समय था, जब हर खेत में बैलों की जोड़ी मेहनत से धरती को जोतती थी और किसान की आत्मा उसमें बसती थी। बदलते वक्त में जहां तकनीक ने खेती के तौर-तरीकों को बदला, वहीं कई सीमांत व लघु किसान ऐसे भी हैं जो आज भी संसाधनों के अभाव में बैलों पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इन्हीं अन्नदाताओं की संवेदनाओं को समझते हुए बजट वर्ष 2025-26 में "बैलों से खेती" योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य परंपरागत खेती को प्रोत्साहित करना, सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करना और पशुपालन को बढ़ावा देना है। यह सहायता उन किसानों को दी जाएगी जिनके पास एक जोड़ी बैल (दो बैल) हों

और जो लघु या सीमांत श्रेणी में आते हों। इसके अतिरिक्त, बैलों का पशु बीमा होना भी अनिवार्य है, ताकि आकस्मिक क्षति की स्थिति में किसान को राहत मिल सके।

कई आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में आज भी पारंपरिक खेती को संरक्षित रखने वाले किसान सीमित संसाधनों में बड़ी लगन से खेती करते हैं। सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान किया है, जिससे वन भूमि पर खेती करने वाले पात्र किसानों को योजना का लाभ मिल सके।

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से सरल और डिजिटल है। किसान ई-मित्र या "राज किसान साथी पोर्टल" के माध्यम से अपने बैलों की फोटो, बीमा प्रमाण–पत्र और भूमि संबंधित दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। यह पहल न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि परंपरागत खेती को पुनर्जीवित कर आत्मनिर्भर भारत की भावना को भी साकार करती है।

"बैल से जुड़ी खेती एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक है।" इस सोच को साकार करने के लिए राज्य सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से राजस्थान के किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जल एवं संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो रहा है और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बल मिल रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रदेश का मुखिया, एक किसान का बेटा किसानों के सपनों को साकार करने और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में निरंतर जुटा है।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

Atal Pension Yojana

India's Financial Inclusion Drive Reaches Rural Heartlands

Reaching the Last Mile : India's Campaign for Financial Security and Rural Empowerment

– **Rakshita Yadav**, APRO

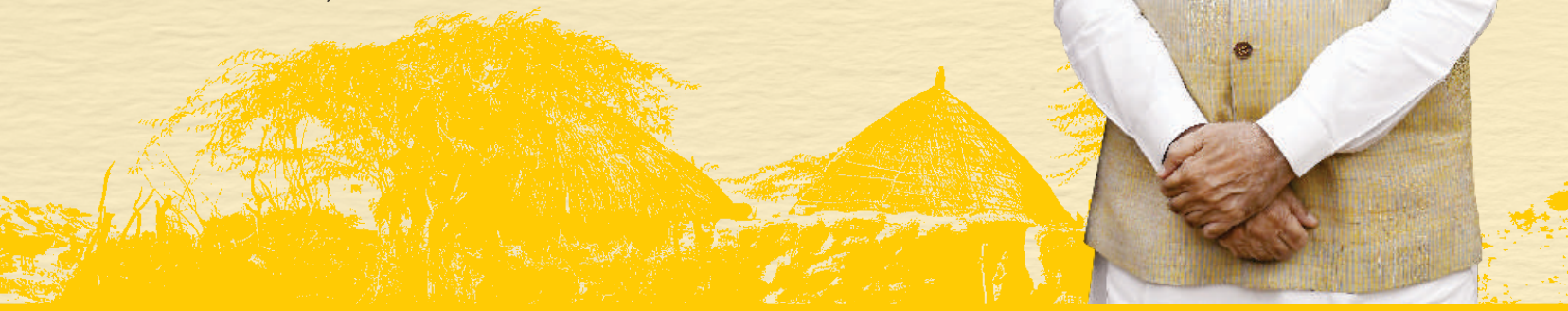

In a bold and focused move to bring every citizen under the umbrella of financial security, the Government of India has launched a transformative three-month campaign (July to September 2025) aimed at expanding the reach of social security schemes across the country. The efforts are not just urban-centric but dive deep into the Gram Panchayats, focusing especially on those who have remained excluded from formal financial systems.

This ambitious drive sends a strong message inclusive growth begins with inclusive finance. The government is not only pushing for higher enrolment in banking and insurance schemes but is also actively raising awareness to combat digital frauds that prevent millions from accessing basic financial services.

In this campaign, Rajasthan has emerged as a beacon of execution and commitment. The state is organizing camps in 11,483 Gram Panchayats, demonstrating not just scale but the seriousness with which this mission is being pursued.

Launched with great fanfare in Jaipur, the campaign is being steered by the highest levels of state administration. All District Collectors and Divisional Commissioners have been given the responsibility to ensure smooth coordination, infrastructural readiness, and inter-departmental cooperation.

This is not a top-down directive delivered in isolation. It is a grassroots movement, fuelled by local leadership, public institutions, and community networks.

Putting Citizens First : Government's Role in Transformation

Through extensive door-to-door awareness and enrolment drives, the campaign ensures that even the most remote communities are not left behind. These efforts are not just about opening bank accounts – they are about empowering people with the knowledge they need to participate fully in the economy.

For inactive Jan Dhan accounts, the campaign offers a practical and supportive approach to restoring financial activity. By simplifying the process of updating Know Your Customer (KYC) details, the initiative removes barriers that often discourage account holders from re-engaging with

their banks. This not only helps individuals regain access to financial services but also strengthens the overall banking ecosystem by reviving dormant accounts.

Another vital component of the strategy is enhancing financial security, particularly for low-income and vulnerable populations. The campaign actively promotes enrolment in low-cost insurance schemes such as the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). These schemes offer life and accident insurance at nominal premiums, providing a crucial safety net for families that might otherwise face financial ruin in the event of an emergency. By encouraging participation, the campaign is helping to build a culture of financial protection and resilience.

Looking toward the future, the strategy also places strong emphasis on long-term financial well-being. One of its major goals is to increase participation in the Atal Pension Yojana (APY) – a government-backed pension scheme tailored for informal sector workers who typically lack access to retirement planning. By highlighting the benefits of APY and making enrolment easier, the campaign is working to ensure that more citizens can look forward to a stable and secure retirement.

In addition to promoting access and security, the campaign plays a crucial educational role. It spreads awareness about critical issues such as digital financial fraud, the existence and claiming of unclaimed bank deposits, and the importance of maintaining proper financial documentation. These topics are especially relevant in today's rapidly digitizing financial environment, where awareness is the first line of defense against exploitation or loss.

Each of these initiatives underscores the government's commitment to empowering citizens – not just economically, but with knowledge, dignity, and a sense of security.

On the Ground : Coordination and Community Engagement

In Rajasthan, Bank of Baroda has taken charge as the State Level Bankers' Committee (SLBC) convener, issuing clear directives to banks and Lead District Managers. Specific banks have been assigned to each Gram Panchayat based on their rural reach. Coordination with district-level officials ensures that camps are held efficiently and that the right financial products reach the right audience.

Beyond formal banking institutions, Self-Help Groups (SHGs) are playing a key role in the campaign's community outreach. These women-led groups are being equipped to lead local economic transformation. SHGs act as both beneficiaries and catalysts, spreading financial awareness, supporting credit linkages, and fostering income-generating opportunities within villages.

Not Just Inclusion – Empowerment

This campaign is a statement of intent: that financial empowerment is the cornerstone of poverty alleviation, and that rural communities deserve the same level of access as their urban counterparts.

It is also a reminder of the power of governance when it aligns resources, institutions, and purpose around people. The Government of India, through this focused campaign, is not merely delivering services – it is fostering trust in the system and confidence among citizens.

By September 2025, this initiative hopes to leave behind more than statistics. It aims to build a legacy of confidence, access, and financial dignity for every household it touches.

In an era where financial inclusion is no longer optional but essential for equitable development, India's latest push – led proudly by states like Rajasthan – stands as a model of how proactive governance can bring meaningful change, one village at a time.

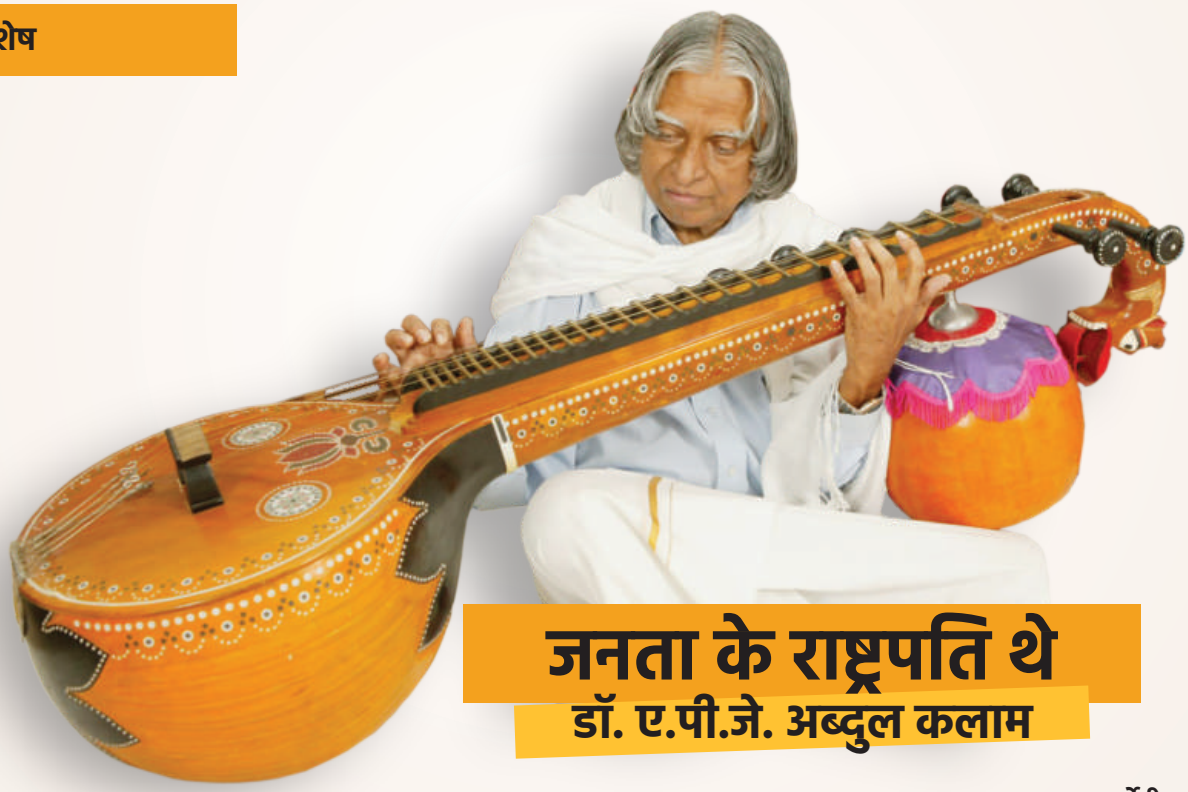

जनता के राष्ट्रपति थे
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

– **अनुज चतुर्वेदी**, स्वतंत्र लेखक

जनता के राष्ट्रपति नाम से प्रसिद्ध डॉ. अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2002 को एक सादे कार्यक्रम में शपथ ली। बाल सुलभ मुस्कान और जिज्ञासु प्रकृति के कलाम तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उनमें समुद्री पक्षियों की उड़ान के पीछे का विज्ञान जानने की उत्सुकता जगी, बस यहीं से कलाम का नाता विज्ञान से जुड़ने लगा था। शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में अभियांत्रिकी में स्नातक की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ गए और नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों, नियंत्रित मिसाइलों, प्रक्षेपास्त्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1980 में कलाम के नेतृत्व में भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV 3 विकसित हुआ, जिसके द्वारा रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। 1974 में पोकरण में हुए भारत के पहले परमाणु कार्यक्रम के बाद कलाम ने 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ-साथ कलाम भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे।

सादगी भरा जीवन

राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम सादगी भरे तरीके से ही रहना पसंद करते थे। अक्सर नीले रंग की शर्ट पहनना पसंद करने वाले कलाम बाहरी चमक–दमक की जगह विचारों पर जोर दिया करते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए खोल दिया। राष्ट्रपति भवन के स्टाफ को सख्त आदेश था कि उन तक आने वाली कोई भी मेल या चिट्ठी पर यथोचित कार्यवाही की जाए। आगरा की एक बालिका ने जब अपनी कॉलोनी

''मैं यह बहुत गर्वोक्तिपूर्वक तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिये आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया उससे किसी ऐसे गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामजिक दशाओं में रह रहा हो। शायद यह ऐसे बच्चों को उनके पिछड़ेपन और निराशा की भावनाओं से विमुक्त होने में अवश्य सहायता करे।''

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
पूर्व राष्ट्रपति

के पार्क में लगे झूले के खराब होने संबंधी पत्र अपने प्रिय राष्ट्रपति को लिखा उस पर भी तुरंत संज्ञान लेते हुए स्थानीय प्रशासन को समस्या का समाधान करने का आदेश दिया गया।

कला के प्रति प्रेम

मिसाइलमैन कहे जाने वाले कलाम को रुद्र वीणा बजाना भी बहुत प्रिय था। तमिल संत तिरुवल्लुवर की रचना 'तिरुक्कुरल' कलाम को प्रिय थी। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने की पहल की और उस कार्यक्रम को 'इंद्रधनुष' का नाम दिया गया। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की अंतिम प्रस्तुति राष्ट्रपति भवन में ही हुई। इसी प्रकार के एक कार्यक्रम में कलाम संगीत में इतने मुग्ध हो गए कि प्रस्तुति दे रहे प्रसिद्ध ड्रम वादक शिवामणि के साथ स्वयं भी ड्रम बजाने लगे थे।

एक बार अमृत उद्यान(मुगल गार्डन) में घूमते हुए जब उन्होंने एक बीमार मोर को देखा तो तत्काल अपने स्टाफ के माध्यम से राष्ट्रपति भवन के पशु चिकित्सक को उस मोर की स्थिति से अवगत करवाया। मोर के मुंह में ट्यूमर था, जिसका बाद में इलाज किया गया।

ईमानदारी की मिसाल

सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। जब कलाम के परिवारजनों का 52 सदस्यीय दल उनसे मिलने आया तो उनके निवास में होने वाले समस्त खर्च का वहन राष्ट्रपति भवन कार्यालय से न करवा कर स्वयं कलाम ने किया। 52 सदस्यीय परिवारजनों का 8 दिनों का कुल खर्च 3 लाख 52 हजार आया, जिसे कलाम ने ही वहन किया। इसी प्रकार कलाम राष्ट्रपति भवन में परंपरागत रूप से होने वाली ईद की इफ्तार दावत के आयोजन से भी असहमत थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के आयोजनों में अधिकतर समृद्ध लोग ही आते हैं। इसी क्रम में राष्ट्रपति ने अपने स्टाफ को कहा कि इफ्तार की दावत के स्थान पर अनाथालयों में सहायता की जा सकती है। उस वर्ष ऐसे 28 अनाथालयों की सूची तैयार की गई और वहां आवश्यक राशन, कम्बल व स्वेटर वितरित किए गए।

इस प्रसंग को बताते हुए कलाम के निजी सचिव रहे पी एम नायर अपनी पुस्तक "द कलाम इफेक्ट" में लिखते हैं कि मुझे राष्ट्रपति ने कहा कि यह खर्च राष्ट्रपति भवन कार्यालय से न किया जाए। इसके लिए उन्होंने मुझे एक लाख का चेक दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस बात को किसी से न कहा जाए।

एक ओर कलाम जहां मिशन 2020, मिसाइल की बात किया करते थे वहीं दूसरी और वह भारत के गांवों को भी उन्नत होते देखना चाहते थे। PURA (Providing urban Amenities in Rural Areas,ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं) प्रदान करना एक ऐसा ही प्रयास था, जिसके माध्यम से वे गांवों में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत बनाने की बात किया करते थे। कलाम दुनिया के सर्वोच्च युद्ध स्थल सियाचिन पर जाने वाले, सुखोई 30 उड़ाने वाले साथ ही INS सिंधुरक्षक S 63 पनडुब्बी में यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे।

सहज और सरल व्यक्तित्व

कलाम अपने नाम के आगे महामहिम या हिज एक्सीलेंसी जैसे सम्बोधनों से भी परहेज किया करते थे। औपचारिकताओं से दूर, सहज रहने वाले कलाम जब रामनाथ गोयनका पत्रकारिता अवॉर्ड कार्यक्रम में थे, तो देश के विकास पर चर्चा करते हुए मंच पर ही बैठ कर अपनी बात रखने लगे। इस समय वो बता रहे थे कि राष्ट्रीय समृद्धि का सूचकांक तीन बिंदुओं से मिलकर बना है पहला सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के स्तर में सुधार और तीसरा जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक भी है नैतिक व्यवस्था में सुधार।

सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु कलाम को 1998 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2007 में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी कलाम देश के लिए अपनी सेवा में अनवरत लगे रहे। वे जब भी समय मिलता, अध्यापन और वैज्ञानिक संस्थाओं में अपने अमूल्य अनुभवों को साझा करते और युवा पीढ़ी को प्रेरणा दिया करते। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग में अपना सबसे प्रिय कार्य छात्रों से 'रहने योग्य ग्रह' विषय पर संवाद करते हुए कलाम का हृदयाघात से निधन हो गया।

कलाम भारत ही नहीं, विश्व के लिए एक प्रेरणा पुंज थे, जिन्होंने प्रारंभिक जीवन की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने हौसलों से आसमान की ऊंचाइयां तय की थीं।

राजस्थान के पोकरण में डॉ. कलाम का ऐतिहासिक योगदान

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का राजस्थान, विशेष रूप से पोकरण में, भारत की सामरिक शक्ति को स्थापित करने में अमूल्य योगदान रहा है। 11 और 13 मई 1998 को पोकरण में हुए परमाणु परीक्षणों के पीछे डॉ. कलाम की दूरदृष्टि, नेतृत्व और वैज्ञानिक सूझबूझ का बड़ा हाथ था। उस समय वे रक्षा मंत्रालय में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने परीक्षण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अपना नाम बदलकर "मेजर जनरल पृथ्वीराज" रखा और सेना की वर्दी में कार्यस्थल पर पहुंचे। खेतोलाई गांव में बनाए गए कंट्रोल रूम से उन्होंने इस मिशन की कमान संभाली। उनकी अगुवाई में भारत ने सफलतापूर्वक पांच परमाणु विस्फोट कर पूरी दुनिया को अपनी वैज्ञानिक और सामरिक ताकत का अहसास कराया। राजस्थान की भूमि इस ऐतिहासिक उपलब्धि की साक्षी बनी, जो भारत को एक परमाणु शक्ति राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई।

सुनियोजित और आर्थिक विकास को मिलेगी गति

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय, 3 नई नीतियों को मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 14 जुलाई को उनके कार्यालय में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में 'हील इन राजस्थान नीति-2025' के प्रारूप एवं टाउनशिप पॉलिसी-2024 एवं राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति, 2025 का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा नगरीय विकास, मेडिकल ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने, अक्षय ऊर्जा सहित ऊर्जा क्षेत्र के विकास, कर्मचारी कल्याण एवं विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

प्रदेश को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल की बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति-2025) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह नीति राजस्थान को सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (एम.वी.टी.) डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगी। यह नीति स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी।

टाउनशिप पॉलिसी-2024 का अनुमोदन : प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन टाउनशिप पॉलिसी-2024 लाई जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिससे शहरी योजनाओं के विकास में आने वाली समस्याओं का त्वरित निदान हो सकेगा। इस नीति में सभी क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में एकरूपता के दृष्टिगत 7 प्रतिशत पार्क व खेल मैदान एवं 8 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। योजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात विकास कार्यों का रख रखाव 5 वर्ष की अवधि अथवा योजना के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तान्तरण किया जाने तक योजना के 2.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे जाने का प्रावधान किया गया है। मिश्रित भू-उपयोग, ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट आवास, एकीकृत योजना, वाणिज्यिक भू-उपयोग की योजना हेतु इस नीति में नवीन प्रावधान रखे गये हैं।

राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति, 2025 का अनुमोदन : गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति, 2025 का अनुमोदन भी किया गया। इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आमजन तक सुलभ हो सकेगी। इस नीति से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) के इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे पीएनजी एवं सीएनजी नेटवर्क का छोटे शहरों व नगरों में तेजी से विस्तार हो सकेगा। इस नीति में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं सरल बनाया गया है। इसके लिए सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी।

प्रक्रियाधीन भर्ती में रिक्तियों की संख्या में सौ प्रतिशत तक वृद्धि : वर्तमान में विविध सेवा नियमों में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या का 50% तक वृद्धि कर चयन किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की अनुपालना में इसे बढ़ाते हुए विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी रिक्तियों की संख्या में सौ प्रतिशत तक वृद्धि का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। इस संशोधन से प्रक्रियाधीन भर्ती के दौरान उसी भर्ती में अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे एवं इससे विभागों में रिक्त पदों की संख्या में कमी आएगी।

कार्मिकों को पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 2 वर्ष का शिथिलन : मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि में 2 वर्ष का शिथिलन दिए जाने का निर्णय किया है। यह शिथिलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा, जिन्होंने वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शिथिलन नहीं लिया है। कार्मिक परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। शासन सचिवालय सेवा (मंत्रालयिक संवर्ग) के कार्मिकों को पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सचिवालय सेवा नियम-1954 में संशोधन किया जाएगा। इसके अनुसार वरिष्ठ उप शासन सचिव एवं उप शासन सचिव पदों के लिए निर्धारित अनुपात 13 रुपये 10 के स्थान पर 16 रुपये 10 में संशोधित किया जाएगा।

परिवर्तित पदनाम एवं नवीन पद सेवा नियमों में शामिल : कृषि विभाग में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-10) का पद सृजित किया गया है। वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद का पे-लेवल राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में सम्मिलित किया जा रहा है। पशुपालन विभाग में नवीन पद मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी (लेवल-12) को भी सेवा नियमों में शामिल किया जा रहा है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में सहायक आयुक्त, उप आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त को राजस्थान

सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में शामिल किया जा रहा है। वाहन चालकों के वरिष्ठ वाहन चालक (लेवल-8), वरिष्ठ वाहन चालक ग्रेड-प्रथम (लेवल-10) एवं मुख्य वाहन चालक (लेवल-11) के पद सृजित किये गये हैं। चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के लिए जमादार ग्रेड-प्रथम (लेवल-4) एवं मुख्य जमादार (लेवल-5) के पद सृजित किए गए हैं। इन पदों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की अनुसूची-2 में शामिल किया जाएगा।

शिक्षकों के सीएएस हेतु रिफ्रेशर कोर्स की छूट बढ़ाई : राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम-1986 में यूजीसी विनियम 2018 के तृतीय एवं चतुर्थ संशोधन के अनुरूप प्रावधान शामिल नहीं होने के कारण बहुत से शिक्षक करियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति से वंचित हो रहे थे। इन संशोधनों को सेवा नियमों में शामिल करने का निर्णय किया गया है।

विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी : राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में प्राध्यापक (कृषि) के पद पर सीधी भर्ती हेतु योग्यता में यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त डिग्री को मान्य किया गया है। इसी प्रकार, एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त बीएड को ही मान्य किया गया है। इसके लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग में राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम-1967 में पटवारी पद की शैक्षणिक योग्यता, भर्ती हेतु स्कीम व परीक्षा पाठ्यक्रम को राजस्व विभाग के पटवारी के समान की जा रही है। साथ ही, चयनित पटवारियों के प्रशिक्षण हेतु स्कीम व पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा भर्ती प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से कराये जाने के लिए भी सेवा नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन के उपरांत राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के पटवारी के समस्त पदों की एक सयुंक्त परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। जल संसाधन विभाग में राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम-1967 में जिलेदार पद को सौ प्रतिशत पदौन्नति से भरे जाने हेतु आवश्यक संशोधन को भी केबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई। विभाग में जिलेदार के सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु 15 पद स्वीकृत हैं, जो कि 30 पदों से कम की श्रेणी में होने के कारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती नहीं हो पाने के फलस्वरूप रिक्त चल रहे थे।

आरपीएससी में सदस्यों की संख्या में वृद्धि : राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत सदस्य के 3 नवीन पद सृजित किये जाएंगे। इस प्रकार आरपीएससी में 7 के स्थान पर अब 10 सदस्य होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से आयोग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तथा आयोग का कार्य सुचारू रूप से एवं तत्परता से सम्पादित हो सकेगा। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974 के विनियम-3 (1) में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

आर.यू.एच.एस. अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश : राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 में आवश्यक संशोधन के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश-2025 लाया जाएगा। इस निर्णय के फलस्वरूप जयपुर में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) को एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

ऊर्जा क्षेत्र में आएगा
11 हजार करोड़ से अधिक निवेश

8 अगस्त 2024 और 29 सितम्बर 2024 को राज्य सरकार और 3 केन्द्रीय पीएसयू के बीच हुए एमओयू की अनुपालना में 3 ज्वाइंट वेंचर कंपनियों के गठन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इससे राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, बिजली उत्पादन में वित्तीय भार में कमी आएगी।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच स्थापित होने वाली जे.वी. में हिस्सेदारी क्रमश: 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत रहेगी। इसमें आरवीयूएनएल के सोलर पार्क में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। इस परियोजना से 2,000 करोड़ रुपये का प्रदेश में निवेश होगा। ऑइल इंडिया लिमिटेड एवं आरवीयूएनएल के मध्य ज्वाइंट वेंचर भी बनाई जाएगी। यह उपक्रम एक हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगा। इस जेवी के माध्यम से प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। गेल (इंडिया) लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच 50-50 प्रतिशत की शेयरधारिता वाली जेवी की स्थापना की जाएगी। इस जेवी कम्पनी को गैस आधारित धौलपुर पावर प्लांट की 300 मेगावाट क्षमता की व रामगढ़ पावर प्लांट की 270.50 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाइयों का हस्तान्तरण किया जाएगा। गेल इन दोनों पावर प्लांटों के संचालन के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इससे इन पॉवर प्लांटों के संचालन और दक्षता में बढ़ोतरी होगी। यह जेवी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा व 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना करेगी। इससे 4200 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 में संशोधन : राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 में संशोधन को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के फलस्वरूप ऐसे निवेशक जिन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 1000 मेगावाट या उससे अधिक अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाईड्रोजन परियोजनाओं के लिए एमओयू किए हैं एवं जिनके पास पीपीए अथवा कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, उनके द्वारा अक्षय ऊर्जा निगम में भूमि हेतु पंजीयन एवं आवश्यक शुल्क जमा कराए जाने पर राजस्व विभाग को इन परियोजनाओं हेतु मौजूदा प्रावधानों के तहत सेट-अपार्ट की अनुशंसा की जा सकेगी। सेट-अपार्ट जमीन का न्यूनतम एक-तिहाई क्षेत्रफल हेतु भूमि आवंटन का आवेदन 3 वर्ष के अंदर तथा अगले कम से कम एक-तिहाई क्षेत्रफल हेतु भूमि आवंटन का आवेदन 4 से 6 वर्ष एवं बाकी आवंटन का आवेदन 7 से 9 वर्ष के बीच आवश्यक राशि जमा कर करना होगा।

प्रदेश मेडिकल टूरिज्म का नया हब, अब
'हील इन राजस्थान'

– **सुधाकर सोनी**, सहायक जन संपर्क अधिकारी

देश-विदेश में अपने किलों और हवेलियों के लिए मशहूर राजस्थान में अब पर्यटकों को सुलभ, किफायती और विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से 14 जुलाई को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति-2025) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि राज्य में मेडिकल सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। किफायती एवं विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाओं के साथ ही कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता के कारण यह सेक्टर देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। 8 हजार से अधिक अस्पतालों, 40 से अधिक मेडिकल कॉलेजों और विश्वस्तरीय निजी अस्पतालों के साथ प्रदेश में एक मजबूत स्वास्थ्य तंत्र विकसित है। इसे और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार ने अपने पहले बजट में ही स्वास्थ्य के लिए 27 हजार 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जो कि बजट का 8.26 प्रतिशत था। इसी मंशा के साथ मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी (हील इन राजस्थान नीति-2025) का प्रारूप तैयार किया गया है।

पर्यटकों को मिलेंगी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चिकित्सा सुविधाएं

मुख्यमंत्री की पहल पर अनुमोदित इस नीति से राजस्थान की सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (एम.वी.टी.) डेस्टिनेशन के रूप में एक नई पहचान बनेगी। प्रदेश में आने वाले घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप

चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध को अपनाकर वे स्वस्थ जीवनशैली की ओर आगे बढ़ सकेंगे। इस नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही एमवीटी से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम का विकास भी सुनिश्चित होगा।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं

नवीन पॉलिसी के तहत एक सेल की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से एमवीटी सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाताओं को प्रमाणित किया जायेगा। साथ ही, एमवीटी पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया जाएगा, जिसमें पर्यटकों को अद्यतन तकनीक के साथ चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। इनके माध्यम से पर्यटक टेलीकंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और एप-आधारित डायग्नोस्टिक्स जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। विदेशी और विभिन्न क्षेत्रीय सैलानियों को होने वाली भाषा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बहुभाषी हेल्पलाइन सेवाएं भी स्थापित होंगी।

इस नीति के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति और मेडिकल शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की जाएगी। इसके तहत एमवीटी सेल और सिंगल-विंडो पोर्टल की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि आवंटित की जायेगी एवं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, मार्केटिंग, और ब्रांडिंग के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवायी जायेगी।

इस पॉलिसी के लागू होने के बाद पर्यटकों के लिए राजस्थान भ्रमण एक पंथ दो काज जैसा साबित होगा। वे यहां की ऐतिहासिक धरोहरों और विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की जानकारी लेने के साथ ही अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। यह पॉलिसी राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म के वैश्विक मानचित्र पर एक अग्रणी गंतव्य बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम साबित होगा।

आर्थिक विकास के साथ रोजगार के मौके होंगे सृजित

मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी-2025 स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत करके आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। इसके लागू होने के बाद जहां एक ओर मेडिकल क्षेत्र में निवेश बढ़ने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। राज्य सरकार इस नीति के तहत निवेशकों को राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (रिप्स), राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहित करेगी तथा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी उपयोग किया जाएगा।

'स्वस्थ राजस्थान–विकसित राजस्थान' के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 'हील इन राजस्थान नीति-2025' को मंजूरी दी है। इस दूरदर्शी नीति का उद्देश्य राजस्थान को एक विश्वस्तरीय, किफायती और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रैवल हब के रूप में स्थापित करना है। सेवा, तकनीक और टूरिज्म के समन्वय से यह नीति न केवल चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाएगी, बल्कि रोजगार, अनुसंधान और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

20 जुलाई

अंतराष्ट्रीय शतरंज दिवस

64 खानों में बिछी बिसात, किसी की शह-किसी की मात

भारत की बौद्धिक विरासत : राजस्थान का उभरता भविष्य

– वंजुल सांखला, चन्दन गुप्ता, स्वतंत्र लेखक

एक वर्ग में विन्यासित, क्रमांतर से श्वेत-श्याम आठ घरों (खानों) की एक पंक्ति और उसमें दो खिलाड़ियों के बीच चतुरंगिनी सेना के दावपेंच! खेल क्या? पैनी बुद्धि को और धार देने वाला मानो असल में एक युद्धमंचन है। पूरी भरी बिसात पर हजारों संयोजनों में रणनीतिक चालें समय के साथ एक ही बाजी में मानो पूरे राज के उत्थान-पतन की कहानी है। जी हां बात हो रही है 'शतरंज' की।

शतरंज विश्व को भारत की देन माना जाता है। भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत से जुड़ा यह खेल धैर्य और रणनीति का है। यह खेल करीब 5000 साल पहले महाभारत काल से खेला जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर माना जाता है कि शतरंज का आविष्कार छठी शताब्दी ईस्वी के आस-पास उत्तरी भारत में हुआ था। शतरंज का पहला आधिकारिक टूर्नामेंट 1886 में खेला गया था। आज भारत वैश्विक शतरंज के मंच पर तेजी से उभरती हुई महाशक्ति बन चुका है। देश में अब तक 88 ग्रैंडमास्टर्स हैं। आज राज्य में 900 से अधिक सक्रिय रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं, जो राज्य में शतरंज के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं।

भारत का वैश्विक शतरंज में दबदबा

भारत न केवल ग्रैंडमास्टर्स की संख्या में आगे है, बल्कि कई इतिहास रच रहा है, शतरंज में भारत के खिलाड़ियों की अन्य उपलब्धियां....

- **डी. गुकेश (18 वर्ष) :** वर्तमान विश्व चैम्पियन।
- **हरिकृष्णन (चेन्नई) :** हाल ही में फ्रांस में तीसरा GM नॉर्म हासिल कर 87वें ग्रैंडमास्टर बने।
- **प्रज्ञानानंद और विश्वनाथन आनंद** जैसे दिग्गजों ने इस खेल को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया।
- **पुरूष और महिला दोनों वर्गों में ओलंपियाड गोल्ड मेडल** - ऐसा कारनामा अभी तक किसी अन्य देश ने नहीं किया।

भारत करेगा फिडे विश्व कप-2025 की मेज़बानी

भारत अब शतरंज आयोजन का भी वैश्विक केंद्र बन रहा है। FIDE वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जिसमें दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी शामिल होंगे और देश के युवाओं को सीखने का बड़ा मंच मिलेगा।

चौखानों पर सजे नए अवसर

राजस्थान की राजधानी जयपुर 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025' की मेज़बानी करेगी। एक निजी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी संयुक्त

दिव्या देशमुख : भारत की शतरंज शेरनी

19 वर्षीय भारतीय ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज में देश का परचम लहराया है। साल 2025 में उन्होंने महिला शतरंज विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया और इसके साथ ही 2026 महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया।

दिव्या ने महिला शतरंज ओलंपियाड में भारत के लिए दो स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा वे एशियाई चैम्पियनशिप, विश्व जूनियर और विश्व युवा चैम्पियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। कड़ी मेहनत और धैर्य से उन्होंने यह साबित किया है कि भारतीय युवा वैश्विक स्तर पर किसी से कम नहीं।

कोनेरू हंपी जैसी दिग्गज शतरंज खिलाड़ी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, दिव्या ने भारतीय महिला शतरंज को नई ऊँचाइयों पर पहुंचाया है। जहां हंपी वर्षों से भारत का नेतृत्व करती रही हैं, वहीं दिव्या उस विरासत को और भी सशक्त बना रही हैं। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ भारत को विश्व शतरंज मानचित्र पर गौरवान्वित करती हैं।

रूप से इस आयोजन की मेज़बान होंगी, जिसमें 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। राजस्थान ने शतरंज की दुनिया में अब मजबूत और संगठित कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। जहां पहले यह खेल कुछ हदों में सीमित था, वहीं अब राज्य में शतरंज को लेकर नई जागरूकता और ऊर्जा देखने को मिल रही है।

राज्य के युवाओं में शतरंज के प्रति बढ़ते रूझान और प्रशिक्षण की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए Chess Parents Association Rajasthan (CPAR) की स्थापना की गई। ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों की रणनीतिक सोच, धैर्य और निर्णय क्षमता जैसे गुणों में निखार लाया जा रहा है। इसका सीधा परिणाम यह है कि आज राजस्थान के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। राजस्थान की यह नई शुरूआत अब एक संगठित आंदोलन बन चुकी है, जो न केवल इस खेल को लोकप्रिय बना रही है, बल्कि आने वाले समय में राज्य को शतरंज की नई शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

राजस्थान के चमकते सितारे

यश भरड़िया (जयपुर) : 15 वर्ष की उम्र में 4 राष्ट्रीय और 2 अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने के साथ इंटरनेशनल मास्टर (IM) की उपाधि प्राप्त की (20 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले राजस्थानी खिलाड़ी हैं।)

अद्विक शर्मा : मात्र छह साल और नौ महीने की उम्र में राजस्थान के सबसे कम उम्र के FIDE-रेटेड खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा, उन्होंने पुणे में चार ग्रैंडमास्टर शतरंज टूर्नामेंट में भाग लिया, जिसमें दो बार प्रथम, एक बार तृतीय और एक बार चतुर्थ स्थान प्राप्त किया।

शतरंज में प्रतिभा विकास की योजनाएं

AICF (अखिल भारतीय शतरंज महासंघ) ने 25 जून, 2025 को शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी स्टाइपेंड योजना (टीएनपीएसएस) प्रारम्भ करने की घोषणा की, जो प्रतिभा विकास में सहायता के लिए एक वित्तीय सहायता पहल है। AICF शीर्ष युवा शतरंज प्रतिभाओं के खातों में सीधे 60,000 से 1.5 लाख रुपये तक की अपनी पहली तिमाही वजीफा राशि भेज रहा है। अप्रैल से जून तक के महीनों के लिए कुल 42.30 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं। अंडर-7 से लेकर अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ी इस योजना के लाभार्थी हैं। इसका उद्देश्य कोचिंग व यात्रा खर्च में मदद देना है, जिससे प्रतिभाएं आर्थिक बाधाओं के बिना आगे बढ़ सकें।

राजस्थान में शतरंज की समृद्ध परंपरा

राजस्थान में भी शतरंज की एक समृद्ध परंपरा रही है 1980-90 के दशक में एस.एस.एन. जोशी, शंकर लाल हर्ष, जेठु सिंह सिसोदिया, कन्हैया

कम उम्र में शतरंज से जुड़ने के बाद बच्चे अब आगे बढ़ने का तैयार

अंग्रेजी में कहावत है 'Well begun is half done' हम शतरंज के क्षेत्र में देखें तो पाएंगे कि अधिकतर खिलाड़ी जो इस खेल में आगे तक बढ़ पाए हैं, जैसे इंटरनेशनल मास्टर व ग्रैंडमास्टर, उन्होंने कम उम्र से ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। शायद यही बात अन्य खेलों या चीजों के लिए भी उतनी ही सही है।

भारत में शतरंज दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा खेला जाता है और आज भारत में कुल 88 ग्रैंडमास्टर हैं, जिनमें से 31 सिर्फ अकेले तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु की इस उपलब्धि का का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि तमिलनाडु में 7 वर्ष तक की आयु की राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में दो सौ से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होते हैं, जबकि यह आंकड़ा राजस्थान में मात्र 50 खिलाड़ी ही है। यानी राजस्थान में, जहां बच्चे कम उम्र से खेलना शुरू नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आगे चलकर अन्य राज्यों के मुकाबले उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए हैं।

इस स्थिति को देखते हुए पिछले 10 साल से शतरंज खेल रहे बच्चों के अभिभावकों ने मिलकर 'चेस पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान' संगठन की स्थापना की। इसका मकसद राजस्थान के बच्चों के लिए शतरंज खेलने के अवसर व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था। पिछले 10 साल में 'चेस पेरेंट्स एसोसिएशन' ने कई अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व जिला स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट एवं कई ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया। इसके अलावा 5 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य के 20 स्कूलों में जाकर हर सप्ताह, सालभर बच्चों को शतरंज सिखाया और इस तरह के और भी ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाए, जिसका परिणाम अब दिखने लगा है। शतरंज की गतिविधियां राजस्थान में निरंतर बढ़ रही हैं और अब राजस्थान के खिलाड़ी से हर वर्ष राष्ट्रीय मेडल व कुछ अंतरराष्ट्रीय मेडल भी हासिल कर रहे हैं।

राजस्थान के यश भरड़िया ने चार बार राष्ट्रीय पदक व दो बार अंतरराष्ट्रीय पदक प्राप्त किया है और हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर की डिग्री प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली हैं। राजस्थान को बीस वर्ष बाद कोई इंटरनेशनल मास्टर मिला है। भारत में कुल 124 इंटरनेशनल मास्टर हैं। यश के अलावा पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान से अरूण कटारिया, वृशांक चौहान, श्रेयांशी जैन व रीशेन जीलोवा भी राष्ट्रीय पदक अर्जित कर चुके हैं।

'चेस पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार जिला व राजस्थान शतरंज संघ के माध्यम से राज्य की शतरंज प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन व वैश्विक मंच पर राजस्थान का नाम ऊंचा करने का प्रयास कर रही है।'

डॉ. ललित भराड़िया
सचिव, चेस पेरेंट्स एसोसिएशन राजस्थान

लाल दवे, उम्मेद सिंह आदि खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। 1996 ई. में नासिर वजीह ने नेशनल 'बी' प्रतियोगिता जीतकर राजस्थान को प्रथम राष्ट्रीय स्वर्ण पदक दिलाया और U-25 में भी पदक जीता। इसी वर्ष अभिजीत गुप्ता, भरत गुप्ता, अभिषेक श्रीवास्तव, वैभव बाकलीवाल, अमित डाड, रोहित ठाकुर, रवि खन्ना, रवि सोहनी और अभ्युदया राजपुरोहित जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी सामने आए, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के पंजीकृत खिलाड़ियों में निश्चित रूप से वृद्धि हुई हैं। वर्तमान में राजस्थान के लगभग 900-1000 सक्रिय खिलाड़ी हैं।

शतरंज अब राजस्थान के लिए सिर्फ एक खेल नहीं, हमारे गर्व का प्रतीक बनता जा रहा है। राज्य सरकार की पहल से राजस्थान के बच्चों को मंच, प्रशिक्षण और पहचान मिल रही है।

युवा खिलाड़ियों को मिला अंतरराष्ट्रीय मंच

राजस्थान के कई युवा खिलाड़ी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यश ने इंटरनेशनल मेडल जीतने के साथ इंटरनेशनल मास्टर (IM) की उपाधि अर्जित की है, जबकि कियाना परिहार ने अंतरराष्ट्रीय पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। वृशांक चौहान ने राष्ट्रीय पदक जीतने के साथ (FIDE) मास्टर (FM) की उपाधि प्राप्त की, वहीं अरुण कटारिया ने भी राष्ट्रीय पदक के साथ (FM) का खिताब हासिल किया है। श्रेयांशी जैन और रिशेन जिलोवा ने भी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं, जबकि होनी अरोरा ने कैंडिडेट मास्टर (CM) की उपाधि अर्जित की है। इन सभी के बीच अद्विक ने राजस्थान के सबसे कम उम्र के रेटेड खिलाड़ी बनकर खास पहचान बनाई है। शतरंज अब राजस्थान के लिए सिर्फ एक खेल नहीं, हमारे गर्व का प्रतीक बनता जा रहा है। Chess Parents Association Rajasthan, AICF और राज्य सरकार की पहल से राजस्थान के बच्चों को मंच, प्रशिक्षण और पहचान मिल रही है।

बैठकें

अधिवक्ता न्याय प्रणाली के स्तंभ

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिवक्ताओं को न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग बताते हुए कहा है कि वे पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाकर राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर राज्य बजट 2024-25 में बार काउंसिल के लिए 7.50 करोड़ रुपये की सहायता के प्रावधान हेतु आभार जताया। इस दौरान न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विधिक सुधारों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध रूप से अदालतों की सुविधाएं बढ़ा रही है तथा उन्होंने अधिवक्ताओं से सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का आह्वान भी किया।

सरकार खनन-पर्यावरण संतुलन बनाए रखने को प्रतिबद्ध

राजस्थान में खान विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्य की खनिज संपदा और खनन क्षेत्र की प्रगति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज हैं, जिनमें से 57 का दोहन हो रहा है। उन्होंने नए खनिज ब्लॉक्स की पहचान और नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने, साथ ही पर्यावरण क्लीयरेंस को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने खनिज संपदा का व्यापक प्रचार-प्रसार कर निवेश आकर्षित करने पर भी जोर दिया। केन्द्रीय मंत्री ने राजस्थान की खनिज संपदा और ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में दुर्लभ खनिजों के सुनियोजित खनन को महत्व देते हुए राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। राजस्थान को हाल ही में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

प्रस्तुतीकरण में राज्य के राजस्व स्रोत, खनिज ब्लॉक्स की नीलामी, खनन संभावनाएं, और कोयला-खनन संबंधित प्रकरणों की जानकारी दी गई। बैठक में केन्द्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

रोजगार सृजन में राइजिंग राजस्थान समिट मजबूत आधार

मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर बनाने में समिट के निवेश प्रस्ताव उल्लेखनीय भूमिका निभाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार सृजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार सृजन के हमारे लक्ष्य की दिशा में भी यह समिट मजबूत आधार बनेगी। समिट के तहत हुए एमओयू के धरातल पर मूर्त रूप लेने से युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से एमओयू को धरातल पर मूर्त रूप देने के साथ ही आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उद्योग विभाग को सभी विभागों से समन्वय कर एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की मॉनिटरिंग करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की समयबद्ध हो प्राप्ति

मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विभागों के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए ऊर्जा, उद्योग, खनन, यूडीएच, कृषि और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागों के एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी तिमाही में भी इसी प्रकार ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया में और तेजी लाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एविएशन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र के निवेश प्रस्तावों के धरातल पर मूर्त रूप लेने से प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

स्वच्छता में राजस्थान को राष्ट्रीय उपलब्धि

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत 17 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में राजस्थान ने देशभर में गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा डूंगरपुर को "सुपर स्वच्छता लीग" और जयपुर ग्रेटर को "प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर" श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। डूंगरपुर की ओर से यह सम्मान नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने व जयपुर ग्रेटर की ओर से महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर ने ग्रहण किया।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इन उपलब्धियों को पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय बताया और कहा कि ये सम्मान आमजन, प्रशासन और नगर निकायों की साझी प्रतिबद्धता का परिणाम हैं। उल्लेखनीय है कि पहली बार राजस्थान के तीन शहर उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज टॉप 20 स्वच्छ शहरों में शामिल हुए हैं। साथ ही उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर (नॉर्थ और साउथ), कोटा (नॉर्थ और साउथ), अजमेर और सीकर कुल 12 शहर देश के टॉप 100 स्वच्छ शहरों में शामिल हुए हैं। राजस्थान के चार शहर उदयपुर, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज और राजाखेड़ा को GFC (कचरा मुक्त शहर) थ्री स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। वहीं जयपुर का ढेलावास एसटीपी "बेस्ट प्रैक्टिस" के रूप में चुना गया है।

निवेश, नवाचार और समावेशी विकास के क्षेत्र में अपूर्व प्रगति

लंदन में आयोजित हुआ 12वां 'भारत गौरव अवार्ड' समारोह

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई, 2025 को आयोजित 12वें 'भारत गौरव अवार्ड' समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और प्रभावी विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान "राइजिंग राजस्थान" पहल के तहत निवेश, नवाचार और समावेशी विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है और खनन, पर्यटन, शिक्षा व उद्योग क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से राजस्थान में निवेश कर विकास यात्रा में भागीदारी का आह्वान किया। 'भारत गौरव अवार्ड' को उन्होंने देश की एकता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक बताया। इस समारोह में देश-विदेश की 25 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और 18 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

महिला सशक्तीकरण के लिए कृतसंकल्पित

राज्य महिला सदन में 11 आवासनियों का विवाह सम्मेलन

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 4 जुलाई को सांगानेर स्थित राज्य महिला सदन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र और राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसे आयोजनों से समाज को सकारात्मक दिशा मिलती है। उन्होंने बताया कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत 11 योग्य युवकों का चयन कर 11 बेटियों का विवाह कराया गया, जिसमें बेटियों की पसंद को प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब तक 13 हजार से अधिक बेटियों को 71 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। साथ ही, लाडो प्रोत्साहन योजना को बेटियों के जन्म, शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए गेम-चेंजर बताया। मुख्यमंत्री ने नवविवाहितों को आशीर्वाद देते हुए 21-21 हजार रुपये की सहायता राशि के चैक भेंट किए। समारोह में मंत्री श्री अविनाश गहलोत सहित कई अधिकारी व समाजसेवी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री की युवाओं को बड़ी सौगात

एक ही दिन में 26,000 से अधिक पदों पर भर्तियों के विज्ञापन जारी

राज्य सरकार ने युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हाल ही में विभिन्न विभागों में 26 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणाएं कीं। शिक्षा, गृह, कृषि, पशुपालन, वन, ऊर्जा, पीएचईडी और आयुर्वेद विभाग समेत कई क्षेत्रों में प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, उप निरीक्षक, पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता, वनरक्षक व आयुष अधिकारी जैसे पदों के लिए विज्ञप्तियां जारी हुईं।

विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर युवा शक्ति

26 जून 2025 को जोधपुर में आयोजित IIT जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तकनीक, स्टार्टअप, शिक्षा और कौशल विकास में निरंतर निवेश कर रही है, जिससे युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर मिल सकें। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक परंपरा का स्मरण करते हुए युवाओं से 'भारत प्रथम' की भावना के साथ नवाचार और सीखने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखने की अपील की। सरकार द्वारा अटल इनोवेशन स्टूडियो, स्टार्टअप लॉन्चपैड, लर्न-अर्न-प्रोग्रेस (LEAP) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से दो वर्षों में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने, 10 लाख रोजगार सृजन करने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के संकल्प पर भी प्रकाश डाला

प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं देशभर में बन रहीं मिसाल

एसएमएस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स-डे का आयोजन

1 जुलाई 2025 को एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में डॉक्टर्स-डे पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं देश में मिसाल बन रही हैं। उन्होंने बताया कि गांव-ढाणी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने, चिकित्सकों की नियुक्तियों, नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत और "मा योजना" जैसे सुधारात्मक कदमों से चिकित्सा तंत्र को मजबूती मिली है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने 27,660 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य बजट, 24,000 से अधिक नियुक्तियाँ, कई अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना व उन्नयन, और 15,000 करोड़ रुपये के हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। कार्यक्रम में चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग राज्य सरकार

जयपुर में एसीबी के 68वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार को विकास में सबसे बड़ी बाधा बताते हुए इसे खत्म करने के लिए राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और पुलिस को बिना किसी दबाव के कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने एसीबी की सराहना करते हुए कहा कि पद के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति और गबन जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई ने इसकी भूमिका को मजबूत किया है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन, पुलिस बल में 10,000 नई भर्तियाँ, महिलाओं की तीन नई बटालियन और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। साथ ही, भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध पेंशन रोकने से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता और सहभागिता की अपील भी की।

खनन क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने का संकल्प

जयपुर में स्टार रेटिंग ऑफ माइन्स पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने खनन उद्योग के विकास और पारदर्शिता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में लोहे से लेकर सोने तक 57 प्रकार के खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और प्रदेश ने प्रधान खनिज पट्टों की नीलामी में देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और एम-सैंड इकाइयों को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीतियों को रेखांकित किया। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण को खनन उद्योग का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 24 प्रतिशत अधिक रॉयल्टी राजस्व अर्जित किया है। समारोह में 7 और 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने केंद्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार के तहत प्रदेश के समग्र विकास की भी बात कही।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में भेंट कर राजस्थान के विकास पर चर्चा की। उनके दूरदर्शी नेतृत्व एवं निरंतर सहयोग के लिए राजस्थान की ओर से हृदय से आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आने वाले समय में राजस्थान को और अधिक सहयोग देने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिनों राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे, सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, कानून एवं न्याय मंत्री तथा केन्द्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल और नव नियुक्त पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा से शिष्टाचार भेंट कर राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

सुशासन और समावेशी विकास प्राथमिक लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एचसीएम रीपा में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. भीमराव अंबेडकर के अंत्योदय सिद्धांतों को आधार बनाकर शुरू किए गए आशान्वित जिला (2018) और आशान्वित ब्लॉक (2023) कार्यक्रमों के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में राजस्थान के 5 जिलों (बारां, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, सिरोही) और 27 ब्लॉकों को शामिल किया गया, जिन्होंने नीति आयोग के निर्धारित मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति की है।

उन्होंने बताया कि जुलाई से सितंबर 2024 तक चलाए गए संपूर्णता अभियान को अभूतपूर्व सफलता मिली है। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के अंतर्गत 41 ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल और आधारभूत संरचना क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवसर पर 6 प्रमुख संकेतकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर करौली को स्वर्ण पदक तथा बारां, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही को कांस्य पदक प्रदान किए गए, वहीं जायल

(नागौर), रानी (पाली) और खैरवाड़ा (उदयपुर) ब्लॉकों को स्वर्ण पदक एवं अन्य को रजत, कांस्य व ताम्रपत्र श्रेणी में सम्मानित किया गया।

1,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

हर विधानसभा में तेजी से हो रहा विकास

राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तेजी से विकास कार्यों को क्रियान्वित कर रही है। इसी कड़ी में अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। केकड़ी में सामुदायिक अस्पताल, कॉलेज, 132 केवी जीएसएस, पशु चिकित्सालयों का उन्नयन, और नगरपालिका गठन जैसे फैसले क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के बजट 2024-25 और 2025-26 में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है। हमारी सरकार गरीब, किसान, महिला और युवा के उत्थान को प्राथमिकता दे रही है।

केकड़ी में प्रमुख विकास कार्य

423 करोड़ रुपये से जल जीवन मिशन के तहत केकड़ी-सरवाड़ जल आपूर्ति प्रणाली कार्य। 300 करोड़ रुपये से क्लस्टर पंपिंग सिस्टम, ऑवरहेड टैंक और वितरण प्रणाली स्थापित करने के कार्य, 291 करोड़ रुपये की लागत से बीसलपुर बांध से केकड़ी तक वर्षाजल ट्रांसमिशन मुख्य प्रणाली और इनटेक पर इलेक्ट्रो–मैकेनिकल कार्यों का शिलान्यास किया गया।

सुजस प्रश्नोत्तरी

प्रश्नोत्तरी नं. – 01

1. **राजस्थान में Give up अभियान कब शुरू किया गया?**
   i. 1 नवम्बर 2024 ii. 1 अक्टूबर 2024
   iii. 15 नवम्बर 2024 iv. 1 जुलाई 2024

2. **निम्न में से किस जिले में बीहड़ क्षेत्र (Ravine Area) सर्वाधिक है?**
   i. कोटा ii. भरतपुर iii. बूंदी iv. जयपुर

3. **CAMPA योजना किससे संबंधित है?**
   i. वनीकरण ii. बाल पोषण
   iii. शहरी विकास iv. क्षय निवारण

4. **राजस्थान में मंदिर मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत मंदिरों की संख्या कितनी है?**
   i. 8 ii. 7 iii. 2 iv. 1

5. **राजस्थान में निम्न में किस स्थान पर पोटाश खनिज के भंडार नहीं है?**
   i. सतीपुरा ii. लाखासर iii. भरूसरी iv. रोहिल

6. **राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार मिला है?**
   i. जावर माइंस ii. आनंदपुर भूकिया (उदयपुर)
   iii. भाटी खेड़ा (बालोतरा) iv. सतीपुरा (हनुमानगढ़)

7. **राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इस वर्ष संभाग स्तरीय राजकीय आवासीय वेद विद्यालय खोला गया है?**
   i. हाथोज ii. नाथद्वारा iii. फलोदी iv. सालासर

8. **भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा कौनसे उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया?**
   i. भास्कर ii. आर्यभट्ट iii. रोहिणी iv. चंद्रयान

9. **पुस्तक "द टू प्लान्स : प्रॉमिसेस, परफॉर्मेंस, प्रॉस्पेक्ट्स" के लेखक कौन हैं?**
   i. शशि थरूर ii. जनरल ए.एस वैद्य
   iii. पंडित दीनदयाल उपाध्याय iv. नानाजी देशमुख

10. **राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा निम्न में से किस अवधि में चलाया गया?**
    i. 5 जून से 20 जून 2025 ii. 24 जून से 9 जुलाई 2025
    iii. 5 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 iv. 24 मई से 9 जून 2025

11. **राजस्थान बजट वर्ष 2025–26 में बैलों से खेती योजना, जिसके अंतर्गत पात्र किसान को प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है?**
    i. ₹60,000 ii. ₹50,000 iii. ₹30,000 iv. ₹20,000

12. **भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है?**
    i. बारां ii. बूंदी iii. बांसवाड़ा iv. भीलवाड़ा

13. **राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है?**
    i. 5000 ii. 10,000 iii. 15,000 iv. 20,000

14 **पोहरों की हवेली किस जिले में स्थित है?**
    i. झुंझुनूं ii. हनुमानगढ़
    iii. सीकर iv. चूरू

15. **दर्शनीय पर्यटन स्थल "चाचाकोटा" राजस्थान के किस जिले में स्थित है?**
    i. बांसवाड़ा ii. डूंगरपुर iii. उदयपुर iv. सिरोही

16. **राजस्थान कितने आभा (ABHA) आईडी बनाकर देश में दूसरे स्थान पर है?**
    i. 4.31 करोड़ ii. 5.31 करोड़ iii. 6.23 करोड़ iv. 7.31 करोड़

17. **राजस्थान में वर्ष 2023 - 24 में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबीमुक्त घोषित किया गया?**
    i. 586 ii. 1086 iii. 1586 iv. 2086

18. **राजस्थान सरकार की "एक जिला–एक उत्पाद" योजना में जिला व उत्पाद का कौन सा युग्म सही है?**
    i. चित्तौड़गढ़ - थेवा कला आभूषण ii. बाड़मेर – कशीदाकारी
    iii. भरतपुर - लहसुन उत्पाद iv. बारां - चावल

19. **निम्न में से राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला?**
    i. हनुमन्तसिंह ii. पंकज सिंह
    iii. गगन खोड़ा iv. पी. कृष्णकुमार

20. **राजस्थान में पंजीकृत गौशालाओं को बड़े व छोटे गोवंश पर प्रति पशु प्रतिदिन क्रमश: कितना अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है?**
    i. 50 रुपये व 25 रुपये ii. 100 रुपये व 50 रुपये
    iii. 80 रुपये व 40 रुपये iv. 40 रुपये व 20 रुपये

21. **निम्न में से लेखक रचना का कौनसा युग्म सुमेलित नहीं है?**
    i. विजयदान देथा - प्रिया मृणाल ii. रानी लक्ष्मीकुमारी चूंडावत - मूमल
    iii. कन्हैयालाल सेठिया - लीक लकोडिया iv. यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र - आपसदारी

22. **राजस्थान के संस्कृत विद्वानों व उनकी रचना का कौनसा युग्म सुमेलित नहीं है?**
    i. भट्ट मथुरानाथ शास्त्री - जयपुर वैभवम् ii. कालिदास - मेघदूतम्
    iii. पंडित अंबिका दत्त व्यास - गुप्ताशुद्धिप्रदर्शनम्
    iv. मधुसूदन ओझा - शिशुपालवधम्

23. **राजस्थान सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में किस कार्य हेतु सहायता देय नहीं है?**
    i. प्रसूति सहायता ii. विवाह के लिए सहायता
    iii. चिकित्सा सहायता iv. आवास निर्माण सहायता

24. **राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा 'नवनेरा बैराज' राज्य के किस ज़िले में स्थित है?**
    i. झालावाड़ ii. कोटा
    iii. बूंदी iv. जयपुर

राज्य सरकार की प्रमुख गतिविधियों, योजनाओं तथा राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी के उत्तर 20 अगस्त, 2025 तक ईमेल द्वारा **sujasconnect@gmail.com** पर प्रेषित करें। प्राप्त प्रविष्टियों में से चयनित प्रतिभागियों के नाम एवं सही उत्तर 'राजस्थान सुजस' के आगामी अंक में प्रकाशित किए जाएंगे

सुख महल

बूंदी

जैत सागर झील के किनारे स्थित यह महल एक ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल है। इसका निर्माण 1776 ई. में राजा विष्णु सिंह ने अपने दीवान और वास्तुकार सुखराम की देखरेख में करवाया था, इसी कारण इसका नाम सुख महल पड़ा। दो मंजिला इस महल में भूतल पर एक बड़ा हॉल है, जो ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में बनाया गया था और ऊपरी मंजिल पर दो गुंबदनुमा कमरे तथा एक सुंदर छतरी बनी हुई है।

प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक और पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग ने यहाँ दो दिन बिताकर बूंदी की अतुलनीय विरासत और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखा था। इसी वजह से यह विदेशी पर्यटकों के बीच किपलिंग पैलेस के नाम से भी लोकप्रिय है।

17-18वीं शताब्दी में राजपूत वास्तुकला शैली में निर्मित इस महल का स्थापत्य कला, प्रकृति और साहित्यिक महत्व का यह संगम आज भी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता है।

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991

जोधपुर बनेगा उत्तर भारत का

पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब

देश की ऊर्जा क्रांति में बड़ा कदम बढ़ाते हुए आईआईटी जोधपुर में करीब 205 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर स्थापित होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनने वाला यह क्लस्टर सालाना करीब 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जिसकी लागत 1 से 3 डॉलर प्रति किलोग्राम के बीच होगी। यह देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर होगा, जो उत्तरी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा भुवनेश्वर (पूर्व), पुणे (पश्चिम) और केरल (दक्षिण) में भी ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। आईआईटी जोधपुर और राजस्थान सरकार के बीच हुए एमओयू के तहत पहले ही परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन की दिशा में काम शुरु हो चुका है।

राजस्थान सुजस का यह अंक
https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/sm/government-order/attachments/134/85/10/1702
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, संदेश नायक द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक - डॉ. रजनीश शर्मा, मैसर्स कृष्णा प्रिन्टर्स, जयपुर से मुद्रित (26,500 प्रतियां), 'राजस्थान सुजस' - पृष्ठ संख्या 80, मूल्य 1.00 रुपये • अंक प्रतियां 80,000